चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 24 अप्रैल– 30 अप्रैल 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

प्रधानमंत्री आधार कार्ड के समर्थक क्यों बने?

आधार का रहस्य

इस देश में अजीब माहौल बन गया है. सभी लोग अच्छी-अच्छी बातें बोलना और सुनना चाहते हैं. देश का भविष्य और लोगों की सुरक्षा के मामले में भी जिम्मेदार संस्थाएं सिर्फ मीठी-मीठी बातों को ही तरजीह दे रही हैं. कड़वी बातें बोलना और सुनना देश की सरकार और संस्थाओं के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद कर दिया है. सरकार लगातार बिना बहस के कानून पास कराने में सफल हो जा रही है और विपक्ष अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा का परिचय दे रहा है. विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हो रहे छोटे-मोटे झगड़े को लेकर संसद में जोरशोर से हंगामा तो होता है, लेकिन विदेशी शक्तियों के इशारे पर देश के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ पर विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सरेआम उल्लंघन विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं है. देश की जनता की निजता और सुरक्षा जैसे चिंताजनक मामलों पर किसी सांसद या राजनीतिक दल का ध्यान तक नहीं जाता है. चौथी दुनिया ने आधार कार्ड के ख़तरे से हमेशा आगाह किया है. हम एक बार फिर आधार को लेकर नई चुनौतियों और सरकार की करतूतों पर से पर्दा उठा रहे हैं.

मनीष कुमार

पिछले संसद सत्र में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. उनमें से फाइनेंस एक्ट 2017 बहुत महत्वपूर्ण है. मोदी सरकार ने जिस फाइनेंस एक्ट 2017 को पास किया है, उसके 40 कानूनों में 250 संसोधन किया गया है. इसमें कंपनी एक्ट और आधार एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण हैं. इसके कई दूरगामी असर होने वाले हैं. इन दोनों एक्ट में जो बदलाव हुए हैं, वो वैचारिक दृष्टि से प्रजातंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. हैरानी की बात ये है कि ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाए कि ये बदलाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सवाल तो ये भी है कि लोकसभा और राज्यसभा के किसी सांसद को भी इसका पता नहीं चला और न ही किसी ने सवाल उठाया. कंपनी एक्ट में बदलाव कर सरकार ने कंपनियों की पहचान को छिपाने का फैसला लिया है. मसलन, कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को पैसा दे सकती है, लेकिन उसकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. लेकिन ठीक इसके विपरीत, सरकार आधार के जरिए आम जनता की पहचान को सार्वजनिक करने के समर्थन में बदलाव कर रही है. मतलब यह कि सरकार आम नागरिकों को तो पारदर्शी बनाना चाहती है, लेकिन कंपनियों को पारदर्शी बनाने के बजाय अपारदर्शी बना रही है, यानि उसकी पहचान छिपाना चाहती है. इससे सवाल उठाना लाजिमी है कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है. ये भेदभाव क्यों है. सरकार एक तरफ कंपनियों को गुमनाम होकर काम करने की इजाजत देती है, वहीं आम नागरिकों की सारी जानकारियां व क्रियाकलाप सार्वजनिक करना चाहती है. लोगों की सारी जानकारी बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध रहेगी. आधार का सबसे बड़ा फायदा विदेशी कंपनियों को होने वाला है, जिन्हें आधार के जरिए भारत के ग्रामीण बाजार में घुसने की खुली छूट मिल जाएगी.

पहले यूपीए और अब मोदी सरकार भी वही गलतियां कर रही है, जिसके बारे में दुनिया की तमाम एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं. क्या सुरक्षा एजेंसियों को अब तक ये मालूम नहीं है कि इस योजना के तहत ऐसे लोग भी पहचान पत्र हासिल कर सकते हैं, जिनका इतिहास दागदार रहा है. एक अंग्रेजी अख़बार ने विकीलीक्स के हवाले से अमेरिका के एक केबल का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन के आतंकवादी इस योजना का दुरुपयोग कर सकते हैं. कुछ कश्मीरी आतंकियों के पास से यूआईडी बरामद भी किए गए हैं. फिर भी किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है. अजीब स्थिति है. अब पता नहीं नंदन निलेकणी ने पहले मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी को कौन पट्टी पढ़ाई है कि दोनों ही प्रधानमंत्री यूआईडी के दीवाने बन गए. जबकि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी पानी पी-पी कर इस योजना को कोसते थे और अपने चुनावी भाषणों में आधार का उदाहरण देखकर मनमोहन सिंह सरकार को घेरते थे. लेकिन जब वे खुद प्रधानमंत्री हैं, तो उन सारी समस्याओं को भूल चुके हैं. यानि कि आधार में जरूर ऐसी कोई बात है कि देश की सरकार बदल जाती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं बदलता. दरअसल, ये पूरा प्रोजेक्ट ही एक सैन्य रणनीति का हिस्सा है. इसका रिश्ता अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हमले से है. उस हमले के बाद से अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने लोगों पर नजर रखने के लिए एक सुरक्षा प्रोजेक्ट बनाया, जिसके तहत अलग-अलग देशों में इसे लागू किया गया. हैरानी की बात ये है कि इंग्लैंड में इसे लागू करने के बाद बीच में ही इस प्रोजेक्ट को खत्म करना पड़ा. वहां इसे लोगों की निजता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया. ऐसा प्रोजेक्ट, जो इंग्लैंड के लोगों की निजता और सुरक्षा के लिए खतरा है, वो भारत के लोगों के लिए लाभकारी कैसे हो सकता है?

समझने वाली बात ये है कि आधार को एक सैन्य प्रोजेक्ट के रूप में लागू नहीं किया जा सकता था, इसलिए भारत में इसे नागरिक सुविधाओं से जोड़ कर पेश किया गया. इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक काम कर रहा था. इस पर 2007 से ही काम शुरू हो गया था. वर्तमान यूआईडीएआई के चैयरमैन जे सत्यनारायणा उस वक्त आईडेंटिटी मैनेजमेंट के टास्क फोर्स के सदस्य भी थे. गैर सरकारी तौर पर विप्रो ने 2006 में एक रिपोर्ट तैयार की थी और सरकारी तौर पर टास्क फोर्स ने आधार की पूरी रूप रेखा तैयार की. 2009 में प्रणब मुखर्जी ने भारत में इसे लागू किया. इससे पहले अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऐसे प्रोजेक्ट को अपना चुकी थी. इसलिए भारत में इसके लागू होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ. ये पूरा प्रोजेक्ट नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल काउंटर-टेररिज्म सेंटर से जुड़ा हुआ है. बताया ये जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की सेक्युरिटी कॉन्सिल भी इस तरह के प्रोजेक्ट पर स्वीकृति दे चुकी है. जिसका सार ये है कि इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में आतंकवाद और समाजिक उपद्रव पर कंट्रोल करना एक कारगर तरीका है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में भारत की तरह बायोमैट्रिक के जरिए पहचान देने की प्रक्रिया चल रही है. इसमें दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां और खुफिया एजेंसियां अपरोक्ष रूप से दखल दे रही हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि इस प्रोजेक्ट में कोई विघ्न-बाधा न पड़े. वर्तमान में ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सेंट्रल एशिया समेत दुनिया के 14 देशों में चल रहा है.

अब कुछ सवाल हैं, जिसका जवाब मोदी सरकार को देश की जनता को देना चाहिए. सरकार एक-एक करके लगातार हर सेवा में इसका इस्तेमाल अनिवार्य कर रही है. क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से मना कर दिया है? 23 सितंबर 2013, 26 नवंबर 2013 और 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश के नागरिकों पर आधार कार्ड जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है. फिर भी सरकारी एजेंसियां इसे अनिवार्य क्यों बना रही हैं? हालात तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों को हर सुनवाई के दौरान दोहराती है, लेकिन सरकार उसके कुछ दिन बाद ही किसी नए विभाग में इसके इस्तेमाल को अनिवार्य कर देती है. जैसे कि हाल में ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान भी आधार नंबर के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया. साथ ही हर व्यक्ति के बैंक एकाउंट को आधार से जोड़ने का सख्त आदेश दिया गया है. हैरानी कि बात ये भी है कि विपक्ष के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट भी मूकदर्शक बनी हुई है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी का आधार पर बयान

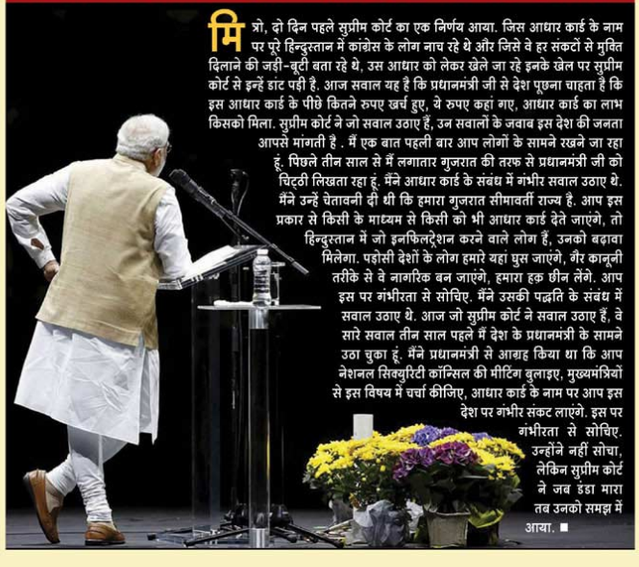

मि. मोदी, दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया. जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिन्दुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और जिसे वे हर संकटों से मुक्ति दिलाने की जड़ी-बूटी बता रहे थे, उस आधार को लेकर खेले जा रहे इनके खेल पर सुप्रीम कोर्ट से इन्हें डांट पड़ी है. आज सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी से देश पूछना चाहता है कि इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, वे रुपए कहां गए, आधार कार्ड का लाभ किसको मिला. सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब इस देश की जनता आपसे मांगती है . मैं एक बात पहली बार आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं. पिछले तीन साल से मैं लगातार गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखता रहा हूं. मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे. मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि हमारा गुजरात सीमावर्ती राज्य है. आप इस प्रकार से किसी के माध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाएंगे, तो हिन्दुस्तान में जो इनफिलट्रेशन करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा. पड़ोसी देशों के लोग हमारे यहां घुस जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से वे नागरिक बन जाएंगे, हमारा हक छीन लेंगे. आप इस पर गंभीरता से सोचिए. मैंने उसकी पद्धति के संबंध में सवाल उठाए थे. आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, वे सारे सवाल तीन साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूं. मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्युरिटी कॉन्सिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों से इस विषय में चर्चा कीजिए, आधार कार्ड के नाम पर आप इस देश पर गंभीर संकट लाएंगे. इस पर गंभीरता से सोचिए. उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा मारा तब उनको समझ में आया. ■

आधार का रहस्य

पृष्ठ 1 का शेष

अब तो चुनाव आयोग ने भी वोटिंग के लिए आधार कार्ड का उपयोग करने की तैयारी कर ली है. राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मतदान में आधार के उपयोग को लेकर आज तक किसी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत या विरोध दर्ज नहीं की है.

नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने आधार के खतरे को लेकर कई सारी बातें कही. उनमें से एक खतरा लोगों की सुरक्षा को लेकर था. अब वो प्रधानमंत्री हैं और आधार के समर्थक बन गए हैं. अगर प्रधानमंत्री के रुख में कोई बदलाव आया है, तो जरूर स्थिति में कई फर्क हुआ होगा. ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि क्या आज भी देशवासियों के पर्सनल सेंसिटिव बायोमीट्रिक डाटा विदेश भेजे जा रहे हैं या नहीं? क्या आधार से जुड़े डाटा के इस्तेमाल और उनके ऑपरेशन का अधिकार विदेशी निजी कंपनियों को दिया गया है? अगर सरकार इस सवाल का जवाब सार्वजनिक रूप से नहीं देती है, तो इसका मतलब साफ है कि लोगों का बायोमैट्रिक डाटा विदेश भेजा जा रहा है और उन डाटा के आपरेशन का अधिकार विदेशी कंपनियों के पास है. अगर मोदी सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया है, यानि अगर डाटा को विदेशी हाथों में जाने से रोक दिया है, तो इस जानकारी को जनता के साथ शेयर करने में क्या परेशानी है? हम जैसे लोगों का वहम भी खत्म हो जाएगा और देश की सुरक्षा के लिए सरकार को इसका क्रेडिट भी जाएगा. चूंकि सरकार इन सवालों के ऊपर चुप है, इसलिए शक होना लाजिमी है. विपक्ष भी चुप है, इसलिए साजिश का संदेह होना बेमानी नहीं है.

चौथी दुनिया ने सबसे पहले आधार से जुड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में पर्दाफाश किया था. चौथी दुनिया ने अगस्त 2011 में ही बताया था कि कैसे यह यूआईडी कार्ड हमारे देश की सुरक्षा के लिए ख़तरनाक है. दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इसके लिए तीन कंपनियों को चुना- एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोफो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन के बारे में हमने बताया था कि इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जैसी चीजों को बेचती है. इस कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी बोर्ड में शामिल किया है. ग़ौरतलब है कि जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक़ के ख़िलाफ़ झूठे सबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. सवाल यह है कि सरकार इस तरह की कंपनियों को भारत के लोगों की सारी जानकारियां देकर क्या करना चाहती है? एक तो ये कंपनियां पैसा कमाएंगी, साथ ही पूरे तंत्र पर इनका क़ब्ज़ा भी होगा. इस कार्ड के बनने के बाद समस्त भारतवासियों की जानकारियों का क्या-क्या दुरुपयोग हो सकता है, यह सोचकर ही किसी के भी दिमाग़ की बत्ती गुल हो जाएगी. तो अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार ने आधार से जुड़ी इन कंपनियों के इतिहास और विदेशी खुफिया एजेंसियों से इन कंपनियों के रिश्ते की तहकीकात की है?

मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि आधार योजना का काम सरकारी एजेंसियों के बजाय विदेशी कंपनियों के हाथों में क्यों है? अब आधार को लेकर जो नई जानकारियां आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं. केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि आधार के नागरिक इस्तेमाल को सैन्य इस्तेमाल से क्यों जोड़ दिया गया? लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यूआईडी योजना पर पुनर्विचार करने की बात कहती रही. चुनाव के बाद भाजपा का स्टैंड क्यों बदल गया? भाजपा ने चुनाव से पहले कहा था कि आधार योजना को लेकर पार्टी की दो चिंताएं हैं, एक तो इसका क़ानूनी आधार और दूसरा सुरक्षा का मुद्दा. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक़, क्या आधार योजना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसा और नागरिकों की संप्रभुता और निजता के अधिकार पर हमला नहीं है? क्या ये चिंताएं अब ख़त्म हो गई हैं? सरकार को बताना चाहिए कि पिछले तीन सालों में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से आधार, जो बीजेपी के लिए एक ख़तरनाक प्रोजेक्ट था, अचानक से सरकार की प्राथमिकता बन गई.

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार से ये पूछा था कि आधार योजना पर कितना पैसा ख़र्च हुआ है और आगे कितना होगा. आज यही सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहिए. अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है, तो ये क्यों न मान लिया जाए कि देश की सरकार और सरकारी संस्थाएं विदेशी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हाथ की कठपुतली बन गई है. उन्हीं के इशारों पर भारत की जनता की निजता और सुरक्षा को खतरे में डालने की शर्मनाक साजिश हो रही है. विदेशी संगठन ताकतवर हैं. दुनिया के किसी भी देश में वो कुछ भी करने में सक्षम हैं. खासकर उन देशों में इनकी शक्ति और भी ज्यादा है, जिन देशों की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक नीतियों का संचालन उन संगठनों के हाथ में है. अफसोस की बात ये है कि 1991 से भारत उन्हीं देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिसकी कमान वैश्विक संगठनों के हाथ में है. आखिर में, किर्गिस्तान नामक देश का एक उदाहरण देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आधार योजना किस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और क्यों भारत ने घुटने टेक दिए हैं.

किर्गिस्तान की सरकार ने भी आधार जैसी योजना को लागू किया और वहां के नागरिकों के बायोमैट्रिक्स को जमा करना शुरू किया. जिस तरह भारत में इसे हर जगह लागू किया जा रहा है, उसी तरह किर्गिस्तान में भी पासपोर्ट, पहचान पत्र और चुनाव में इसके इस्तेमाल को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया. किर्गिस्तान की सरकार ने 2014 में एक कानून पास कर नागरिकों की बायोमैट्रिक जानकारी को जमा करने पर कानूनी मुहर लगा दी थी. भारत की तरह वहां के भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया. विरोध का तर्क और साक्ष्य वही, जो भारत में पेश किया जा रहा है. इस पर किर्गिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज क्लारा सूरोनकुलोवा ने एक दस्तावेज तैयार किया. इसके ड्राफ्ट में जज साहिबा ने इस पूरी प्रक्रिया को गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया. यह खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की कॉन्सिल ने क्लारा सूरोनकुलोवा को बर्खास्त कर दिया. इसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया और संसद का घेराव कर यह आग्रह किया कि संसद से उन्हें न्याय मिले. संसद से न्याय देने के बजाय किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद में फर्जीवाड़े से बहुमत जुटाकर जज क्लारा सूरोनकुलोवा को दोषी करार दिया और उन्हें बर्खास्त कर दिया. सूरोनकुलोवा के मुताबिक कॉन्सिल ऑफ जज पर राष्ट्रपति अल्माज़बेक आतमबायेव ने ही यह दबाव दिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाए. यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ताकि आधार के पीछे लगी विदेशी शक्तियों की ताकत का अंदाजा लग सके. भारत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है. हर सुनवाई के दौरान कोर्ट अपने पुराने फैसले को दोहराती है और अगली सुनवाई में यह पता चलता है कि सरकार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है. फिर भी, कोर्ट हताश निराश और असहाय होकर सिर्फ सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दे रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूआईडी की शुरुआत

यह एक हैरत अंगेज दास्तां है. देश में एक विशिष्ट पहचान पत्र के लिए विप्रो नामक कंपनी ने एक दस्तावेज तैयार किया. इसे प्लानिंग कमीशन के पास जमा किया गया. इस दस्तावेज का नाम है स्ट्रैटेजिक विजन ऑन द यूआईडीएआई प्रोजेक्ट. मतलब यह कि यूआईडी की सारी दलीलें, योजना और उसका दर्शन इस दस्तावेज में है. बताया जाता है कि यह दस्तावेज अब गायब हो गया है. विप्रो ने यूआईडी की ज़रूरत को लेकर 15 पेज का एक और दस्तावेज तैयार किया, जिसका शीर्षक है, इज इंडिया नीड ए यूनीक आइडेंटिटी नंबर. इस दस्तावेज में यूआईडी की ज़रूरत को समझाने के लिए विप्रो ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया. इस प्रोजेक्ट को इसी दलील पर हरी झंडी दी गई थी. हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया. उसने यह दलील दी कि यह कार्ड खतरनाक है, इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा और आम जनता जासूसी की शिकार हो सकती है. अब सवाल यह उठता है कि जब इस योजना की पृष्ठभूमि ही आधारहीन और दर्शनविहीन हो गई, तो फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इसे लागू करने के लिए सारे नियम-कानूनों और विरोधों को दरकिनार करने पर आमादा है. क्या इसकी वजह नंदन नीलेकणी हैं, जो यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री के करीबी और यूआईडीएआई के चेयरमैन थे. क्या यह विदेशी ताक़तों और मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पर किया जा रहा है? देश की जनता को इन तमाम सवालों के जवाब जानने का हक़ है, क्योंकि यह काम जनता के हज़ारों करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसे सरकार के ही अधिकारी अविश्वसनीय, अप्रमाणिक और दोहराव बता रहे हैं. ■

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार से ये पूछा था कि आधार योजना पर कितना पैसा ख़र्च हुआ है और आगे कितना होगा. आज यही सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहिए. अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है, तो ये क्यों न मान लिया जाए कि देश की सरकार और सरकारी संस्थाएं विदेशी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हाथ की कठपुतली बन गई हैं.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 08
24 अप्रैल- 30 अप्रैल 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

गो-रक्षक बनाम गो-पालक

गाय भी तभी बचेगी जब इंसान बचेगा

1 अप्रैल को मवेशियों से भरी 4 गाड़ियों और 11 लोगों को उनके थाने में लाया गया था. सिंह के मुताबिक मेवात के रहने वाले इन 11 लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे. इसलिए पुलिस ने उन्हें गायों के अंतर-राज्यीय आवागमन (इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन) के आरोप में संबंधित एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया और गायों को गोशाला में भेज दिया गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो

हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ इलाके में कथित गोरक्षकों ने पहलू खान नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की इस शक के आधार पर पीट-पीट कर हत्या कर दी कि वो गोतस्करी कर रहा था, जबकि सच्चाई ये है कि पहलू खान जयपुर से गाय खरीद कर अपने गांव जा रहे थे. ये गाय उन्होंने नगर पालिका द्वारा संचालित हाट से खरीदी थी. बकायदा नगरपालिका की ओर से जारी रसीद उनके पास थी. लेकिन कथित गोरक्षकों ने रास्ते में ही घेर कर उनकी हत्या कर दी और ये आरोप लगा दिया कि पहलू खान उक्त गाय को तस्करी कर ले जा रहे थे. गौरतलब है कि पहलू खान अपने गांव में डेयरी चलाते थे. बहरहाल, इस घटना को ले कर मीडिया में तमाम रिपोर्टिंग भी हुई और सोशल मीडिया ने भी अपने तौर पर इस खबर को प्रचारित किया. इन सबके बीच, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का एक प्रतिनिधिमंडल अलवर जिले के बहरोड़ पहुंचा, जहां ये घटना घटी थी. इस टीम ने सबसे पहले बहरोड़ पुलिस थाने पहुंच कर पुलिस उपाधीक्षक परमाल सिंह से बातचीत की और पूरी जानकारी ली. इस प्रतिनिधिमंडल में माकपा की पोलितब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली, सांसद बदरूद्दोजा खान, सांसद शंकर प्रसाद दत्ता आदि शामिल थे.

बहरोड़ के पुलिस उपाधीक्षक परमाल सिंह ने उन्हें बताया कि 1 अप्रैल को मवेशियों से भरी 4 गाड़ियों और 11 लोगों को उनके थाने में लाया गया था. सिंह के मुताबिक मेवात के रहने वाले इन 11 लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे. इसलिए पुलिस ने उन्हें गायों के अंतर-राज्यीय आवागमन (इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन) के आरोप में संबंधित एक्ट के तकत न्यायिक हिरासत में भेज दिया और गायों को गोशाला में भेज दिया गया. सिंह ने आगे बताया कि इस घटना के तुरंत बाद ही उन्हें सन्देश मिला कि हाड़वे पर कुछ लोगों ने एक गाड़ी (जिसमें पहलू खान गाय लेकर अपने गांव जा रहा थे) को रोक कर उसमें सवार लोगों के साथ मारपीट की है. जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पीटे गए लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं. पुलिस उन्हें प्राइवेट अस्पताल तक ले कर गई. इस मामले में पुलिस ने 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 308 के तहत प्राथमिकी दर्ज की. पहलू खान की दुखद मौत के बाद पुलिस ने धारा 308 को बदल कर 302 कर दिया. पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इस प्रतिनिधिमंडल ने जब पुलिस उपाधीक्षक को खरीदी गई गायों की रसीद दिखाई, जो जयपुर नगर निगम द्वारा जारी की गई थी, तो उनका कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई रसीद नहीं देखी है और राजस्थान से बाहर किसी गाय को ले जाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति की जरूरत होती है.

इस मामले में आईओ का रवैया खराब था. पुलिस का कहना है कि पहलू खान के पास पशु के इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी ईएम का परमिशन नहीं था, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके पास नगर निगम से जारी बाजार की रसीद थी. उस रसीद में स्टेट के बाहर ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र था, लेकिन पुलिस ने इसे साक्ष्य नहीं माना. अभी भी कई लोगों की गाड़ियां और जानवर जब्त हैं.

- सुभाषिनी अली सहगल, पूर्व सांसद और सीपीआई(एम) नेता

सवाल है कि अगर ऐसा कोई नियम है, तो जयपुर नगर निगम ने राज्य से बाहर (पहलू खान और अन्य लोगों जो हरियाणा के मेवात के नूह जिले के रहने वाले थे) के लोगों के हाथों गायों की बिक्री कैसे कर दी. जयपुर नगर निगम द्वारा जारी रसीद का अर्थ ही ये है कि खरीददार उसे अन्य राज्य में ले जा सकता है. प्रतिनिधिमंडल को ये भी जानकारी मिली कि राज्य से बाहर गायों को ले जाने के लिए नगर निगम अतिरिक्त पैसा वसूलती है, जो पहलू खान ने चुका दिया था. पहलू खान सरकारी हाट से पशु खरीद कर ले जा रहे थे और इसके कागजात उनके पास थे. इसके बाद भी पुलिस का ये कहना कि नगर निगम द्वारा जारी रसीद वैध नहीं है और इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति की जरूरत है, सवालों के घेरे में है. अब या तो जयपुर नगर निगम को सफाई देनी चाहिए कि उसके नियम इस संबंध में क्या हैं या फिर राजस्थान सरकार को अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए. इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल अलवर के जिलाधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से पहलू खां हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. सुभाषिनी अली सहगल ने जिलाधिकारी को बताया कि मृतक पहलू खां के साथियों का कहना है कि उन्हें अस्पताल में भी डर लग रहा था, वे अभी तक भयभीत हैं. जाहिर है, ये हमला इनलोगों की आजीविका पर हमला था. इस प्रतिनिधिमंडल ने चौथी दुनिया से बात करते हुए बताया कि इस घटना के बाद भी यहां हिंदू चौकियां स्थापित की जा रही हैं. स्टेट इंटेलीजेंस ने भी इस मामले में एक रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक सभी आरोपी हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी हैं. राजस्थान पुलिस के इंटेलीजेंस ने आरोपियों के नाम-पते और हिंदूवादी संगठनों में उनके पद की पूरी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को भेजी है.■

feedback@chauthiduniya.com

भद्रक साम्प्रदायिक हिंसा का ज़िम्मेदार कौन?

सोशल मीडिया या 2019 चुनाव

बिभूति पति
feedback@chauthiduniya.com

पिछले दिनों तटीय ओडीशा का भद्रक शहर साम्प्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया. कर्फ्यू के कारण इस शहर का सम्पर्क बाकी की दुनिया से कुछ दिनों के लिए टूट गया. हिंसा को काबू में करने के लिए अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा. दो हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी शहर अपनी सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रहा है. अब तो राजनीतिक दलों के लिए आरोप-प्रत्यारोप का समय आ गया है.

भद्रक शहर की आबादी का एक चौथाई हिस्सा मुसलमानों की है. आम तौर पर यहां सद्भाव बना रहता है, लेकिन कभी-कभी साम्प्रदायिक संघर्ष की स्थिति भी बन जाती है. इस बार हिंसा कुछ अधिक भड़क गई. यहां 1991 में आखिरी बार साम्प्रदायिक दंगे हुए थे. उस समय भी ये दंगे रामनवमी के जुलूस के दौरान शुरू हुए थे. इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन और पुलिस ने इतिहास से बहुत कम सीख हासिल की है. इस बार झगड़े का सबब आधुनिक सोशल मीडिया बना.

भद्रक में इस साल रामनवमी उत्सव के दौरान हथियारों का खुल कर प्रदर्शन किया गया. हिन्दू समुदाय के एक व्यक्ति ने उत्सव की तस्वीरें फेसबुक पर डाली थी. जवाब में तीन मुस्लिम युवकों ने कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की. ये फेसबुक पोस्ट 5 अप्रैल 2017 को रामनवमी के दिन वायरल हो गया और उसके बाद साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी. स्थानीय पुलिस से जिस मुस्तैदी की उम्मीद थी, उसने वैसी मुस्तैदी नहीं दिखाई. उस निंदात्मक फेसबुक पोस्ट की शिकायतों के बाद 36 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और दोषियों को गिरफ्तार करने के मांगों की अनदेखी करती रही. इस दौरान शहर और पड़ोसी इलाकों में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता रहा. आग भड़काने का काम व्हाट्सएप ने भी किया. व्हाट्सएप के एक संदेश के जरिए अफवाह फैला दी गई कि मुसलमानों ने एक हिंदू व्यापारी की दुकान में आग लगा दी है. इसके बाद हिंसा और भड़क गई.

इसके बाद भद्रक में धारा 144 लगाया गया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया. 7 अप्रैल को शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई. इस बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या सामान्य रूप से अधिक थी. लेकिन शांति प्रयास असफल रहा, क्योंकि एक समूह अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को रिहा करने की मांग पर अड़ गया. इसी बीच, युवाओं के एक समूह ने धारा 144 लागू होने के बावजूद जुलूस निकाली. जलूस में शामिल लोग कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, जिसकी वजह से दंगे भड़क उठे.

कई दुकानें लूटी और जलाई गईं. मीडिया को फोटोग्राफ लेने की इजाज़त नहीं थी. सुकून की बात ये रही कि मामला आगजनी और लूट तक ही सीमित रहा, किसी की जान नहीं गई. हिंसा के दौरान लाखों रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ. यह सवाल पूरे राज्य में फैल रहा है कि आखिर भद्रक में हिंसा क्यों भड़की?

एक 60 वर्षीय बुजुर्ग, जिन्होंने इस घटना को करीब से देखा था, ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें ऐसी थीं, जिनकी वजह से ऐसी स्थिति बनी. पहली, रामनवमी का जुलूस, जिसमें हथियार का प्रदर्शन आम है. इससे साम्प्रदायिक दंगे भड़कने की सम्भावना अधिक होती है. पूर्व में संबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जयनारायण मिश्रा उस समय विवादों के घेरे में आ गए, जब उन्होंने तलवार का प्रदर्शन किया. हालिया पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत के बाद ऐसी घटनाएं राज्य में कई जगहों पर दुहराई गई. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और ओडीशा के प्रभारी बी के हरिप्रसाद कहते हैं कि यह ओडीशा सरकार और पुलिस की नाकामी है. खास तौर पर पुलिस का खुफिया तंत्र इस मामले में नाकाम रहा. हालांकि ये साफ़ है कि वोट हासिल करने और सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए ध्रुवीकरण का भाजपा का यह पुराना फार्मूला है. उधर, ओडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कहना है कि यह प्रशासन की नाकामी नहीं है. हमने कानून के मुताबिक सही समय पर सही क़दम उठाए. जिला प्रशासन और पुलिस ने कामयाबी के साथ स्थिति को नियंत्रण में किया.

भद्रक में आखिरी बार 1991 में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे. उस साल दंगे का कारण बना, एक नारा. वे नारा था- जब भारत में रहना होगा, राम नाम कहना होगा. पुलिस और स्थानीय प्रशासन को पता होना चाहिए था कि ऐसे नारे साम्प्रदायिक हिंसा में प्रेरक का काम करते हैं और ये सच्चाई है कि कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं, जो ऐसे मौकों का इंतज़ार करते रहते हैं. प्रशासन इस पूरे प्रकरण के दौरान उंघता हुआ नजर आया. खास तौर पर घटना के शुरुआती दौर में. जब फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा था, उसी समय पुलिस को हरकत में आ जाना चाहिए था.

इस दंगे का तीसरा सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है. यदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया गया, तो यह बम बनाने वाले कारखाने से भी अधिक हानिकारक बन जाएगा. ऐसे हालात में सोशल मीडिया कितना नुकसान पहुंचा सकता है, पुलिस और प्रशासन इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके. फेसबुक पोस्ट ने दंगे के लिए माहौल तैयार किया और व्हाट्सएप ने दंगे की शुरुआत करा दी. दरअसल, प्रशासन को सोशल मीडिया की शक्ति का देर से एहसास हुआ. लेकिन जब एहसास हुआ, तो 9 अप्रैल को 48 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया. जब बहुत नुकसान हो गया, तब राज्य सतर्कता विभाग ने इसका संज्ञान लिया और सोशल मीडिया वाले हिस्से की जांच की ज़िम्मेदारी ली. पंचायत चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा और आरएसएस, भुवनेश्वर में होने वाली भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक से पहले अपनी ताक़त का प्रदर्शन करना चाह रहे थे. इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 2019 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण अपनी चरम सीमा पर जा सकती है. ये घटना शायद भविष्य में घटित होने वाली ऐसी घटनाओं की पहली कड़ी थी. बहरहाल, इस घटना का ज़िम्मेदार चाहे जो हो, इसे रोकने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की थी, जिसमे वो असफल साबित हुई.■

दो पहिया वाहनों पर लाखों टन धान ढोकर ले लिया अरबों का भुगतान

झारखंड
घोटालों का
राज्य

एक और घोटाले की जद में झारखंड

सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है, लेकिन एक सच नहीं बदलता और वो है, घोटालों का सच. अपनी स्थापना से ठीक पहले झारखंड जिस घोटाले के दौर से गुजरा था, आज फिर से उसी दौर में जाता दिख रहा है. स्कूटर जैसे दो पहिया वाहनों पर ढुलाई का सच सामने आने के बाद जिस चारा घोटाले ने देश को हतप्रभ कर दिया था, आज एक बार फिर से झारखंड में एक वैसा ही घोटाला उजागर होता दिख रहा है. हैरानी की बात ये है कि इसमें भी धान की ढुलाई दो पहिया वाहनों से हुई है और ये घोटाला, मंत्री बने उसी व्यक्ति के विभाग में सामने आया है, जिसने कभी चारा घोटाले का उद्भेदन किया था.

प्रशान्त शरण

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पदभार ग्रहण करते ही बड़े ही तल्ख अंदाज में कहा था कि अब इस राज्य में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, अफसर सुधर जाएं, या हम सुधार देंगे. लेकिन ऐसे दावों के बाद भी इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है. धान की खरीद के नाम पर अधिकारियों एवं नेताओं के गठजोड़ ने एक तरफ जहां अरबों रुपयों का गबन किया, वहीं अधिकारियों ने गरीबों को भी नहीं बख्शा. आयोडीन नमक के नाम पर ऐसे नमक की खरीददारी की, जिससे गरीबों को घेंघा नामक बीमारी से बचाने की बात तो दूर, उन्हें और बीमारी परोस दिया गया. अधिकारी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे अपने विभागीय मंत्री की भी नहीं सुनते हैं. जाहिर है कि इस राज्य में अभी भी भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह मिल रही हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों मामले पड़े है, लेकिन बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है. छोटी-छोटी मछलियों को पकड़ कर सरकार वाहवाही लूटने में लगी हुई है. मुख्यमंत्री रघुवर दास के ड्रीम प्रोजेक्ट मोमेंटम झारखंड में भी व्यापक पैमाने पर लूट-खसोट हुआ, लेकिन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी मूकदर्शक बने रहे.

चारा घोटाले के बाद राज्य में एक और बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, वह भी उस विभाग में जिसके मंत्री सरयू राय हैं. गौरतलब है कि सरयू राय ने ही एक हजार करोड़ से अधिक का चारा घोटाला उजागर कर, इसे जांच के मुकाम तक पहुंचाया था. इस घोटाले में अविभाजित बिहार के दो मुख्यमंत्री, कई मंत्री, दर्जनों आईएएस अधिकारी सहित सैकड़ों लोग अभियुक्त बनाए गए थे. अभी को ये धान घोटाला भी चारा घोटाले की तर्ज पर ही हुआ है. जिस तरह से चारा घोटाले में स्कूटर, मोटरसाईकिल, कार पर फर्जी ढुलाई दिखा कर करोड़ों रुपयों का गबन किया गया था, ठीक उसी तरह इस बार भी 200 करोड़ रुपए से भी अधिक के धान की ढुलाई बाईक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस और कार के नम्बरों वाली गाड़ियों पर दिखाकर, अरबों रुपयों का गबन कर लिया गया है. घोटाले में शामिल सिंडिकेट ने कागजों पर ही धान को मिल से एफसीआई गोदाम पहुंचा दिया. घोटालेबाजों ने धान की फर्जी खरीद के रूप में तो गबन किया ही, एफसीआई गोदाम तक धान पहुंचाने के एवज में भी परिवहन भुगतान के रूप में लाखों रुपए डकार लिए. गोदाम तक धान लाने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल दिखाया गया है, उनमें से 14 नम्बर दो पहिया वाहनों के निकले, जबकि अन्य नम्बर कार, जीप और ऑटो के हैं. घोटाले में शामिल सिंडिकेट ने धान को पैक्स मिल तक पहुंचाने के लिए 207 फर्जी वाहनों का जिक्र किया है. नंबरों की जांच से पता चला कि इनमें से 192 बाइक हैं, जबकि 14 बस, 5 जीप, 9 कार, 2 स्कूटर और 8 ऑटो हैं. ठीक इसी तरह चारा घोटाले में भी स्कूटर और बाइक पर चारा ढोए गए थे और करोड़ों का घोटाला कर लिया गया था.

भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस घोटाले को गंभीरता से लिया है. लेकिन वे कितने गंभीर है, इसका सहज अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जांच के आदेश दिए जाने के बाद अभी तक जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है. राज्य सरकार ने इस घोटाले से

जुड़े सभी आठ जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा है, लेकिन अब तक किसी भी जिले के उपायुक्त ने जांच की रिपोर्ट नहीं भेजी है.

इस घोटाले में भी कई आईएएस और वरिष्ठ अधिकारियों के फंसने की संभावना है. खाद्य आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग के कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं. यही कारण है कि आईएएस लॉबी इस घोटाले पर पर्दा डालने की साजिश कर रहा है. इसकी तह तक जाने पर पता चल सकेगा कि ये भी हजारों करोड़ का घोटाला है. अधिकारी भी इसे बखूबी जानते हैं और यही सोच कर सभी ने चुप्पी साध रखी है.

हालांकि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय यह मानते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और धान खरीद एवं ढुलाई के नाम पर अरबों रुपयों का गबन हुआ है.

बड़ा घोटाला हुआ है कोई नहीं बचेगा: सरयू राय

यह महज संयोग ही है कि चारा घोटाले को उजागर कर, अपनी एक नई पहचान बनाने वाले सरयू राय के ही विभाग में घोटाला हो रहा है. धान खरीद से लेकर नमक खरीद का घोटाला. हालांकि खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय खुद भी इसे एक बड़ा घोटाला मानते हैं. मंत्री का यह मानना है कि राज्य में धान खरीददारी और इसकी ढुलाई केनाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है. वर्ष 2011 से 2014 के बीच धान ढुलाई के नाम पर अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है. जिन गाड़ियों का इस्तेमाल ढुलाई में दिखाया गया है, वे बाईक और स्कूटर हैं. मंत्री सरयू राय ने बताया, जिले के उपायुक्त को यह निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द इस मामले में रिपोर्ट दें. जो भी अधिकारी इस घोटाले में लिप्त पाया जाएगा,

उसे बख्शा नहीं जाएगा. मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा तीन माह पूर्व ही इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे. हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं होने के मामले में मंत्री ने चुप्पी साधते हुए कहा कि मैं विभागीय सचिव से जानकारी ले रहा हूं. उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि इस घोटाले में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है, बिना सहकारिता विभाग की संलिप्तता के ये घोटाला संभव ही नहीं है. मंत्री ने कहा कि इसमें जिलों के उपायुक्तों की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि राजस्व के हर मामले की निगरानी की जिम्मेवारी उपायुक्तों की ही होती है.

झारखंड में नमक की खराब गुणवत्ता के मामले में मंत्री का मानना है कि ये बात सामने आई है कि यहां नमक के उपयोग से दाल-सब्जी काला हो जा रहे हैं. इस मामले की भी जांच कराई जा रही है कि नमक कंपनियों ने डबल फोर्टिफिकेशन में मानकों का पालन किया है कि नहीं. जांच के बाद का दूसरा विकल्प भी तलाशा जा रहा है, वैसे ये टेंडर तीन महीने का ही था और इसमें पांच कंपनियों ने भाग लिया था. राज्य में अब जिस नमक की आपूर्ति होगी, उसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा. ■

मंत्री का भी कहना है कि इसमें कई लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा है कि पूरे घोटाले की जांच कराई जाएगी. इसमें कोई बचेगा नहीं. मंत्री सरयू राय के लिए यह प्रतिष्ठा का भी विषय है, क्योंकि राय ने ही चारा घोटाले को उजागर कर लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र जैसे दिग्गज नेताओं को जेल की कोठरी तक पहुंचा दिया था.

इस पूरे मामले का खुलासा महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ था. आठ जिलों में हुए ऑडिट के बाद महालेखाकार ने पाया कि अफसरों के भ्रष्ट सिंडिकेट ने कागज पर ही धान खरीदा, कागज पर ही उसे पैक्स से मिल भेजा और फिर कागज पर ही धान को मिल से एफसीआई गोदाम भी भेज दिया. ऐसा कर अफसरों ने साल 2011 से 2014 के बीच 25,212.29 क्विंटल धान की फर्जी खरीद कर 3.58 करोड़ का फर्जी भुगतान उठा लिया. अफसरों ने कागज पर खरीदे गए धान को पैक्स से मिल और फिर मिल से एफसीआई भेजने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल दिखाया, उसमें से अधिकांश वाहनों के नंबर बाइक, स्कूटर, बस, कार, ऑटो के पाए गए हैं. सीएजी का अनुमान है कि इन आठ जिलों, धनबाद, रांची, बोकारो, खूंटी, हजारीबाग, गढ़वा, दुमका और देवघर को मिलाकर यह घोटाला लगभग सौ करोड़ रुपए का हो सकता है. महालेखाकार ने इन आठ जिलों की रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करा दी है. 16 अन्य जिलों में भी सीएजी जांच कर रही है. माना जा रहा है कि वहां भी ऐसे घोटाले सामने आ सकते हैं.

ऐसे तो, राज्य सरकार ने जांच के लिए सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले में राज्य के पंद्रह आईएएस सहित 24 सहकारिता पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. इन्हीं लोगों ने यह खेल खेला और अब जांच से बचने के लिए आईएएस अधिकारियो एवं सरकार पर दबाव बना रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि जिलों के उपायुक्तों ने धान खरीद की सही ढंग से निगरानी नहीं की है. धान खरीद, धान को मिल तक पहुंचाना एवं वहां से एफसीआई गोदाम तक पहुंचाना, ये सारे काम सहकारिता विभाग करता है. लेकिन इसकी निगरानी की जिम्मेदारी उपायुक्तों की होती है. अभी जहां जांच हुई है, वहां इस बात का पता चला है कि उपायुक्तों ने निगरानी सही ढंग से नहीं की है. इधर, विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने यह माना है कि महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ है. उन्होंने कहा कि 2011-14 के दौरान फर्जी तरीके से धान की खरीद कर भुगतान उठा लिया गया है. सभी जिलों के उपायुक्तो को जांच के लिए कहा गया है, जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

झारखंड अपने स्थापना काल से ही घोटालों के मामले में पूरे देश में एक अलग पहचान बना चुका है. इसे घोटालों का राज्य भी कहा जाता है. लगातार हो रहे घोटालों में यहां की गरीब जनता पिस रही है. जब मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़े जोश-खरोस के साथ भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का दावा किया था, तो लोगों के बीच यह उम्मीद जगी कि अब यहां रामराज्य कायम हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के तल्ख तेवर और अंदाज भी ढकोसला ही साबित हो रहे हैं और यहां भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सुशील मोदी की आशा के अनुरूप तेज प्रताप यादव ने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे मोदी पर मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे. तेज की इस प्रतिक्रिया के बाद लालू कुछ समझते या बोलते, तब तक हंगामा खड़ा हो चुका था. लालू प्रसाद को शायद मोदी की रणनीति का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. मामले को ठंडा करते हुए उन्होंने पत्रकारों के जवाब में यह कह डाला कि चिड़ियाघर को तो वे मुफ्त में अपनी गायों का गोबर देते हैं.

मिट्टी और मॉल पर मोदी के जाल में उलझे लालू

सरोज सिंह

जम्हूरियत यानि लोकतंत्र के बारे में अल्लामा इकबाल के एक शेर का सार यह है कि लोकतंत्र में बंदे को गिना जाता है, तौला नहीं जाता. यही कारण है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में की जाने वाली राजनीति में तमाम दल, जन को प्रभावित करके उसे अपने पक्ष में करने के लिए हर समय कोशिश करते हैं. तमाम दल अपने विरोधी दल को बुरा और खुद को अच्छा साबित करने में लगे रहते हैं. मौजूदा दौर की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली होने के बावजूद लोकतंत्र की लिमिटेशन ये है कि तथ्य और हकीकत कुछ भी हो, लेकिन जनमानस का परसेप्शन राजनीतिक दलों को सत्ता सौंपने का आधार बन जाता है. यही कारण है कि राजनीतिक दल भी जनसमर्थन जुटाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, बंदे को तौलने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती. इस लिहाज से देखें, तो बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी कानूनी तौर पर यह कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए कोचर बंधुओं को रेलवे के दो होटल देकर फायदा पहुंचाया और उसके बदले कोचर बंधुओं ने डिलाइट मार्केटिंग नामक कम्पनी को पटना की धड़कन कहे जाने वाले बेली रोड (जवाहरलाल नेहरू मार्ग) पर दो एकड़ जमीन दी. फिर उस जमीन को लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया. हालांकि सुशील मोदी ने अपनी सरकार के रेल मंत्रालय से आग्रह करने की बात कही है कि वे लालू प्रसाद द्वारा कथित तौर पर कोचर बंधुओं को फायदा पहुंचाने की जांच करें. सुशील मोदी अपने दावे की सच्चाई किसी भी कीमत पर साबित नहीं कर सकते. इसकी वजह लालू प्रसाद के उस जवाब में है, जिसे उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस करके दिया था. लालू ने पांच पन्नों के अपने जवाब में जो तर्क दिए हैं उसके अनुसार, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रेलवे के लिए एक निगम आईआरसीटीसी का गठन किया था. आईआरसीटीसी अपने होटलों और यात्री निवासों को पंद्रह वर्षों के लिए लीज पर निजी पार्टियों को हस्तांतरित करता है. इसके लिए वह ओपेन बीड निकालता है और जिस पार्टी द्वारा उच्चतम मूल्य की बोली लगाई जाती है, उसे होटल या यात्री निवास सौंप दिया जाता है. इस प्रकार कोचर बंधुओं को लीज पर दो होटल दिए जाने की प्रक्रिया तकनीकी और कानूनी मानदंडों के अनुकूल थी. लालू ने यह भी कहा कि आईआरसीटीसी स्वतंत्र संस्था है और उसमें वतौर रेल मंत्री उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और न ही कर सकते थे. लालू ने प्रेस कांफ्रेंस में यह भी बताया कि कोचर बंधुओं ने होटल के आवंटन के 22 महीने पहले डिलाइट मार्केटिंग को बेली रोड की जमीन बेची थी. तब यह किसी को पता भी नहीं था कि आईआरसीटीसी अपने होटलों और यात्री निवासों को खुली निविदा के अधार पर निजी कम्पनियों को आवंटित करने वाला है. लालू ने इस तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया को भी समझाया कि समहर्ता द्वारा निर्धारित नियमों और मूल्य के मुताबिक कोचर बंधुओं से डिलाइट मार्केटिंग कम्पनी ने जमीन प्राप्त की थी. ये बातें समझाने के बाद लालू ने सुशील मोदी से सवाल पूछा कि क्या कोचर बंधुओं को 22 महीने पहले यह सपना आया था कि आईआरसीटीसी होटलों का आवंटन करेगा.

सुशील मोदी द्वारा लालू के परिवार, जिसमें उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी शामिल हैं, पर आरोप लगाया गया था कि डिलाइट मार्केटिंग ने 2 एकड़ जमीन की मिलकियत उन्हें सौंप दी है. इस भूमि पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल निर्माणाधीन है. मोदी के आरोप और उस पर लालू के तथ्यात्मक जवाब से यह तय है कि मोदी अपने आरोपों को शायद ही कानूनी तौर पर सिद्ध कर सकें. लेकिन यह भी तय है कि तथ्य और हकीकत भले जो भी हों, मोदी ने लालू परिवार के विरुद्ध जनमानस में एक परसेप्सन तैयार करने की कोशिश की और इसमें वे सफल रहे. सुशील मोदी द्वारा लालू परिवार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए गए थे, जिनका जवाब लालू प्रसाद ने प्वाइंटवाइज दिया है. इसका अवलोकन बॉक्स में किया जा सकता है.

यहां हम मोदी के आरोपों के पीछे की रणनीति और बिहार की राजनीति में उसके संभावित प्रभाव की गुत्थियों को तलाशने की कोशिश करते हैं. सुशील मोदी ने एक रणनीति के तहत प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की. उसमें उन्होंने आरोप का महज एक लेकिन सटीक तीर छोड़ा. उन्होंने न तो लालू पर सीधा निशाना साधा और न ही उनके उपमुख्यमंत्री पुत्र तेजस्वी यादव पर. उनका सीधा हमला तेज प्रताप यादव पर था, जो स्वास्थ्य मंत्री के अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं. मोदी ने कहा था कि लालू के परिवार की जमीन पर आरजेडी विधायक अबु दोजाना की कम्पनी द्वारा मॉल बनाया जा

रहा है. उस जमीन से खोदी गई मिट्टी पटना के चिड़ियाघर को 90 लाख रुपए में बेची गई, वह भी बिना टेंडर के. इस तरह तेज प्रताप यादव ने अपने विभाग के मंत्री के बतौर 90 लाख रुपए का फायदा खुद उठा लिया. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने स्ट्रैटिजिकली तेज को लपेटा, क्योंकि उन्हें पता है कि तेज प्रताप यादव तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं. सुशील मोदी की आशा के अनुरूप तेज प्रताप यादव ने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे मोदी पर मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे. तेज की इस प्रतिक्रिया के बाद लालू कुछ समझते या बोलते, तब तक हंगामा खड़ा हो चुका था. लालू प्रसाद को शायद मोदी की रणनीति का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. मामले को ठंडा करते हुए उन्होंने पत्रकारों के जवाब में यह कह डाला कि चिड़ियाघर को तो वे मुफ्त में अपनी गायों का गोबर देते हैं. वैसे अगर किसी को संदेह हो, तो इस मामले की जांच करा ली जाय. इसके एक दिन बाद मोदी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर आरोपों की झड़ी लगा दी, (जिनका उल्लेख बाक्स में है). साथ ही पत्रकारों को ऑफ दी रिकार्ड यह भी बताया कि अभी उनके पास आरोपों का और भी पुलिंदा है, जिसे वे आगे उजागर करते रहेंगे. मोदी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लालू उनकी रणनीति समझ गए और उन्होंने चुप्पी साध ली. उनकी ये चुप्पी लगातार पांच दिनों तक बनी रही. इस बीच सुशील मोदी एक पर एक आरोप मढ़ते रहे. लेकिन पांचवें दिन लालू प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा कर दी, जिससे ये अंदाजा हो गया कि वे अब पूरी तैयारी के साथ मोदी के आरोपों का जवाब देने वाले हैं. यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि जैविक उद्यान को कथित तौर पर 90 लाख रुपए की मिट्टी बचने का जो आरोप मोदी ने लगाया था, उसके जवाब में लालू ने ये कहा कि जैविक उद्यान को एक रुपए की भी मिट्टी नहीं बेची गई है. मॉल की जमीन से निकली मिट्टी दानापुर कब्रिस्तान को दी गई है. लालू के इस जवाब पर सुशील मोदी ने चुप्पी साध ली. उसके बाद उन्होंने 90 लाख की मिट्टी बेचने के आरोप को नहीं दोहराया और अपने आक्रमण को मॉल और जमीन पर केंद्रित कर दिया. लालू ने सवाल खड़ा किया कि मोदी हिट एंड रन का तरीका अपना रहे हैं. उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा- देखा न, मिट्टी के मामले में जवाब मिलने के बाद अब मोदी चुप हो गए हैं. हालांकि इस मामले में मोदी की चुप्पी संशय बढ़ाने वाली है. बिना टेंडर के मिट्टी बेचने की तथ्यात्मक सूचना अगर मोदी के पास थी, तो उन्हें लालू प्रसाद के जवाब पर अपनी बात कहनी चाहिए थी.

मोदी द्वारा लालू परिवार पर लगाए गए आरोपों का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है. जिस डिलाइट मार्केटिंग कम्पनी से लालू के परिवार को जमीन हस्तांतरित करने का आरोप मोदी ने लगाया था, वो कम्पनी प्रेम गुप्ता के परिवार के सदस्यों की थी. प्रेम गुप्ता लालू के खासे करीबी हैं और राजद की ओर से राज्यसभा सदस्य रहे हैं. राजद जब केंद्र सरकार का हिस्सा थी, तो प्रेम गुप्ता कम्पनी मामलों के मंत्री थे. लिहाजा मोदी के आरोपों का जवाब देने के लिए लालू प्रेम गुप्ता के साथ प्रेस के सामने आए. प्रेम गुप्ता ने समझाने की कोशिश की कि जब बिहार में काम करने का माहौल नहीं था, तो कम्पनी के निदेशकों ने तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) के तहत डिलाइट मार्केटिंग को लारा प्रोजेक्टस में बदल दिया. जिसके शेयर राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के पास हैं. प्रेम गुप्ता ने पत्रकारों को याद दिलाया कि यह मामला 2008 में भी उठाया गया था. हालांकि उन्होंने उस नेता का नाम नहीं लिया, जिन्होंने इस मामले को 2008 में उठाया था. दरअसल, 2008 में ललन सिंह ने ये मामला उठाया था, जो जदयू के नेता हैं और अभी नीतीश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं. गौर करने की बात है कि 2008 में नीतीश और लालू राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे. लेकिन अब, जब इस मामले को भाजपा के नेताओं ने उठाना शुरू किया है, तो जदयू बिल्कुल खामोश है. जाहिर सी बात है कि राज्य में जदयू और राजद, गठबंधन की सरकार का हिस्सा हैं और इन दोनों दलों का सेपरेट राजनीतिक वजूद है. ऐसे में भाजपा और राजद की आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई से एक तरफ जहां भाजपा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, वहीं राजद डैमेज कंट्रोल में लगा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले में जदयू की चुप्पी एक तीर से दो निशाने जैसी है. जदयू एक तरफ तेज प्रताप और तेजस्वी को मंत्रिमंडल से निकालने के सुशील मोदी की मांग पर चुप्पी साध कर राजद के मनोबल को मजबूत बनाए रखने में मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ उसे यह भी उम्मीद है कि राजद-भाजपा की लड़ाई में उसे फायदा होगा. ■

कथित भ्रष्टाचार पर सुशील मोदी के आरोप और लालू की सफाई

सुशील मोदी- निर्माणाधिन मॉल वाली तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जमीन से मिट्टी निकाल कर उसे पटना के जैविक उद्यान को बेचा गया. इसके लिए कोई टेंडर भी नहीं निकाला गया और बदले में जैविक उद्यान से 90 लाख रुपए लिए गए, जिसका लाभ तेज प्रताप को हुआ. तेज प्रताप वन एंव पर्यावरण मंत्री भी हैं.

लालू प्रसाद- जिस मॉल की जमीन से मिट्टी निकाल कर बेचने की बात कही जा रही है, उस जमीन से एक रुपए की मिट्टी भी जैविक उद्यान को नहीं बची गई है. मोदी का आरोप मनगढ़त, वे बुनियाद और झूठा है.

सुशील मोदी- लालू ने रेल मंत्री रहते हुए कोचर ब्रदर्स को रेलवे के दो होटल औने पौने दामों में बेच दिए और उसके बदले उनसे दो एकड़ जमीन ले ली.

लालू प्रसाद- सुशील मोदी ने जिस जमीन की बात कही है, वह जमीन 2005 में कोचर ब्रदर्स ने डिलाइट कम्पनी को दी थी. उसके 22 महीने बाद आईआरसीटीसी (रेलवे का स्वावत्त निगम) के माध्यम से ओपेन बीड के तहत कोचर ब्रदर्स ने रेलवे से होटल की लीज प्राप्त की थी. कोचर ने ओपेन बीड में तमाम बीडर्स से ज्यादा बोली लगाई और भारी कम्पिटिशन के बाद उसे 15 साल की लीज आईआरसीटीसी ने दी. आईआरसीटीसी के काम में रेल मंत्री का कोई दखल नहीं होता. यह डील तमाम नियम कानून के तहत हुई. कोचर्स को होटल बेचा नहीं गया. ऐसे में मोदी का आरोप बेबुनियाद और झूठा है.

सुशील मोदी- डिलाइट कम्पनी को राबड़ी, तेजस्वी, तेज और चंदा यादव (बेटी) ने लारा प्रोजेक्ट्स नामक कम्पनी में बदल दिया और उससे ही दो एकड़ जमीन औने पौने दामों में खरीद ली.

लालू प्रसाद- मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर बेली रोड की जमीन है ही नहीं. डिलाइट कम्पनी ने 2007 के कम्पनी ऐक्ट के तहत एलएलपी के तहत लारा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हो गई. इस कम्पनी में श्रीमति राबड़ी देवी का हिस्सा था जिसके शेयर उन्होंने तेज और तेजस्वी को दिए. डिलाइट कम्पनी की स्थापना 1981 में प्रेम गुप्ता और उनके परिवार ने मिल कर की थी. लेकिन प्रेम गुप्ता के परिवार वालों ने उसके शेयर का हस्तांतरण कर इनकम टैक्स, कम्पनी लॉ और तमाम कानूनी प्रक्रिया के बाद एलएलपी कम्पनी बनाई. बेटी चंदा यादव का नाम इस मामले में मोदी ने घसीटा है, जबकि उनका इस कम्पनी से कोई लेना देना नहीं है.

सुशील मोदी- नीतीश मंत्रिमंडल में रहते हुए तेज और तेजस्वी प्रसाद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे में उन्हें मंत्रिपद से हटाया जाय.

लालू प्रसाद- लारा प्रोजेक्ट्स की जमीन पर मेरेडियन नामक कम्पनी मॉल बनवा रही है. नियमों के अनुसार उसमें निर्माण का सारा खर्च उसे उठाना है और बदले में उसे मॉल का आधा हिस्सा मिलेगा. इसमें मेरे परिवार का एक पैसे भी नहीं लग रहा है. बिजनेस मॉडल में कारोबार ऐसे होता है, ये दुनिया को पता है. इस जमीन के संबंध में सारा रिकार्ड तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले चुनाव आयोग को सौंपा था. साथ ही इन दोनों ने मंत्री बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार को भी अपनी जायदाद की पूरी जानकारी दी थी. इस मामले में भी झूठे आरोप लगा कर सुशील मोदी खुद अपनी जगहसाई कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

ख़ुफ़िया एजेंसियां कश्मीर में नाकाम साबित हो रही हैं!

श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में तीन ज़िले हैं- श्रीनगर, बड़गांव और गांदरबल. हिंसा की अधिकतर घटनाएं बड़गांव में घटीं. अन्य जगहों के मुक़ाबले श्रीनगर में हालात शांतिपूर्ण रहे. हालांकि इसके बावजूद इस ज़िले में महज़ 3.84 प्रतिशत मतदान हुआ. यानि जहां हिंसा नहीं हुई, वहां भी पोलिंग का प्रतिशत बेहद कम रहा. 12 लाख 60 हज़ार से अधिक मतदाताओं में से केवल 80 हज़ार लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. गौरतलब है कि 3 वर्ष पूर्व यानि 2014 के संसदीय चुनावों में श्रीनगर में 3 लाख 12 हज़ार से अधिक लोगों ने मतदान किया था. जीतने वाले प्रत्याशी तारिक़ हमीद ने अकेले 1 लाख 75 हज़ार से अधिक वोट प्राप्त किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर फारूक़ अब्दुल्ला थे, जिन्हें 1 लाख 15 हज़ार से अधिक वोट मिले थे.

हारून रेशी

एक बार फिर ये साबित हो गया है कि कश्मीर के ज़मीनी तथ्य और यहां के हालात व घटनाओं के बारे में इंटेलीजेंस एजेंसियां जितनी बेबस हैं, उतनी ही बेख़बर भी हैं. किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लिए केवल 7.14 प्रतिशत लोग ही मतदान करेंगे. ज़ाहिर है कि अगर खुफ़िया एजेंसियों को इस स्थिति की पहले से जानकारी होती, तो सरकार को इतनी शर्मिंदगी न उठानी पड़ती. सरकार ने अपने तरीके से ठीक-ठाक व्यवस्था की थी. कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए सुरक्षाबल और पुलिस की 168 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गईं थीं. चुनावों से एक दिन पूर्व पूरी घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. यहां तक कि श्रीनगर में अख़बार के कार्यालयों तक को भी इंटरनेट से वंचित रखा गया. मतदान क्षेत्रों में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए थे. लेकिन इन सबके बावजूद, हालात पर सरकार या सुरक्षा एजेंसियों का कोई नियंत्रण नही रहा. ज़ाहिर है कि अगर इंटेलीजेंस एजेंसियों को इस हालात का अनुमान पहले होता, तो सरकार और चुनाव आयोग वोट की तारीखें तय करने से पहले सोच-विचार कर लेते या हालात से निबटने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाती. लेकिन साफ़ ज़ाहिर है कि सरकार को इस प्रकार के हालात पैदा होने का कोई अंदाज़ा नहीं था. विश्लेषकों ने इस स्थिति का अलग-अलग तरह से विश्लेषण किया है. कुछ का कहना है कि अलगाववादियों की बायकॉट की अपील का पूरा प्रभाव पड़ा है. वहीं, कुछ का कहना है कि दरअसल हिंसा के कारण भय का वातावरण बना और लोग वोट डालने नहीं निकले. कुछ विश्लेषकों ने तो यहां तक कहा कि हिंसा के द्वारा चुनाव बायकॉट करवाया गया. सच जो भी हो, दिखाई तो यही दे रहा है कि यहां सरकार और इंटेलीजेंस एजेंसियां पूरी तरह से असफल हो चुकी हैं.

किसी भी तरह से ये चुनाव नहीं लग रहा था, ऐसा लगा कि सड़कों पर मौत का नंगा नाच जारी था. सुरक्षा बलों के हाथों 8 युवा मारे गए, दर्जनों घायल हुए. कुछ ही घंटों में हिंसा की 200 घटनाएं घटीं. सुरक्षा बलों और आम युवाओं की मुठभेड़ में दोनों ओर से दर्जनों लोग घायल भी हुए. गंभीर घायलों को जब श्रीनगर के प्राथमिक उपचार केन्द्र या शेर-ए-कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचाया जा रहा था, तो इन अस्पतालों में अजीब सा माहौल देखने को मिला. हर घायल के साथ बड़ी संख्या में युवा नारे लगाते हुए आ रहे थे. सड़कें और राजमार्ग या तो सुनसान थे या फिर हिंसा की आग में जल रहे थे.

श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में तीन ज़िले हैं- श्रीनगर, बडगांव और गांदरबल. हिंसा की अधिकतर घटनाएं बडगांव में घटीं. अन्य जगहों के मुक़ाबले श्रीनगर में हालात शांतिपूर्ण रहे. हालांकि इसके बावजूद इस ज़िले में महज़ 3.84 प्रतिशत मतदान हुआ. यानि जहां हिंसा नहीं हुई, वहां भी पोलिंग का प्रतिशत बेहद कम रहा. 12 लाख 60 हज़ार से अधिक मतदाताओं में से केवल 80 हज़ार लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. गौरतलब है कि 3 वर्ष पूर्व यानि 2014 के संसदीय चुनावों में श्रीनगर में 3 लाख 12 हज़ार से अधिक लोगों ने मतदान किया था. जीतने वाले प्रत्याशी तारिक़ हमीद ने अकेले 1 लाख 75 हज़ार से अधिक वोट प्राप्त किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर फारूक़ अब्दुल्ला थे, जिन्हें 1 लाख 15 हज़ार से अधिक वोट मिले थे. लेकिन आज स्थिति ये है कि साढ़े 12 लाख से अधिक मतदाताओं में से महज़ 80 हज़ार लोगों ने मतदान किया है. इस स्थिति को देखकर चुनाव आयोग ने अनंतनाग संसदीय सीट का चुनाव स्थगित कर दिया है, जो 12 अप्रैल को होना था. उन 38 जिलों में तो महज 2 फीसदी वोटिंग ही हुई, जहां आयोग ने दुबारा मतदान कराने के निर्देश दिए थे. अनंतनाग के चुनाव को स्थगित करने की अपील यहां से पीडीपी के उम्मीदवार व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई तस्दीक़ मुफ्ती ने चुनाव आयोग से की थी. स्पष्ट है कि सरकार श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में शर्मिंदगी उठाने के तुरंत बाद इस प्रकार का एक और रिस्क नहीं लेना चाहती थी या यह कहा जा सकता है कि अब सरकार को ज़मीनी हालात का पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया है.

घाटी में हालात ठीक करना सेना के वश में होता, तो इस काम के लिए तीन दशकों का समय काफी था. इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि कश्मीर में जारी आंदोलन को भरपूर जनसमर्थन प्राप्त है. कश्मीरियों की नई नस्ल पूर्ण रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है. इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए, बिना शर्त बातचीत ही एकमात्र रास्त हो सकता है.

ऐसा नहीं है कि घाटी में इंटेलीजेंस एजेंसियों और सरकार की असफलता का यह एकमात्र उदाहरण है. जुलाई 2016 में भी यही हुआ था, जब हिंसा के कारण कश्मीर 6 महीने तक बंद रहा, 100 लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हुए. पैलेट गन के प्रयोग से सैंकड़ों युवा आखों से वंचित हुए और अरबों रुपए का व्यापारिक नुक़सान हुआ. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तब खुद कहा था कि उन्हें 8 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के एक गांव में हुई झड़प के बारे में पता नहीं था, जिसमें हिज्बुल कमांडर बुरहान वानी मारा गया था. अगर पता होता, तो बुरहान को एक मौक़ा दिया जा सकता था. उल्लेखनीय है कि महबूबा मुफ्ती के पास राज्य का गृह मंत्रालय भी है. इसलिए पता नहीं कि सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें जानबूझकर बुरहान वानी के बारे में ख़बर नहीं दी या सुरक्षा एजेंसियों को खुद भी इस बारे में पता नहीं था.

अब सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि 2016 में घाटी में हालात ख़राब करने की तैयारियां बहुत पहले से शुरू की गई थीं और इसका संरक्षण पाकिस्तान ने किया था. एक पत्रिका ने हाल ही में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें आईबी का कहना है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने घाटी में हालात ख़राब कराने के लिए अलगाववादियों को 800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे. कहने में तो कुछ नहीं जाता है. इसे 800 करोड़ के बजाय 8 हज़ार करोड़ भी कहा जा सकता है. लेकिन तब भी यह सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी राशि घाटी में कैसे पहुंचाई गई? क्या इतनी बड़ी रक़म बोरियां में बंद करके कांधे पर लादकर कंट्रोल लाइन पार करके यहां लाई गई या फिर बैंकिंग के रास्ते यहां पहुंचा दी गई या फिर हवाला के द्वारा वे पैसे कश्मीर में लाए गए. इसका जवाब इंटेलीजेंस एजेंसियों से पूछा जा सकता है कि इस संदर्भ में कोई एक व्यक्ति भी क्यों नहीं पकड़ा गया? जब इंटेलीजेंस एजेंसियों को मालूम है कि कितनी राशि यहां पहुंचाई गई है, तो फिर ये पता क्यों नहीं कि वो रुपए किसके द्वारा पहुंचाए गए हैं और फिर कैसे बांटे गए हैं? ज़ाहिर है, अरबों रुपए के इस लेनदेन में दर्जनों लोगों की सेवाएं शामिल रही होंगी, लेकिन क्या ये हैरान करने वाला नहीं कि इस मामले में किसी एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ा गया. इन्हीं सवालों के कारण कोई भी साधारण सूझबूझ वाला व्यक्ति इंटेलीजेंस एजेंसियों के ऐसे दावों पर विश्वास नहीं करता. अगर यह सच है कि 2016 में हालात ख़राब करने की तैयारियां बहुत पहले से हो रही थीं, तो पूछा जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां क्यों सोई हुई थीं. उन्हें बुरहान वानी की मौत से पहले दो वर्ष तक यह पता नहीं चला कि वो सोशल मीडिया की वेबसाइटों पर कैसे सक्रिय था. वह कहां से अपने बयानों, फोटो और वीडियो संदेश अपलोड करता था. सरकार और इंटेलीजेंस एजेंसियों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बुरहान वानी की लोकप्रियता की सीमाएं कब दक्षिणी कश्मीर लांघकर पूरी घाटी में फैल गई थीं और कब वह कश्मीर के नौजवानों का हीरो बन चुका था. सरकार और उसकी संस्थाएं उस समय हक्का-बक्का रह गईं, जब बुरहानी की मौत के बाद उसकी अंतिम क्रिया में लाखों लोग शामिल हुए और घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में कमोबेश 50 बार उसकी अंतिम क्रिया की औपचारिकता पूरी की गई. किसी भी इंटेलीजेंस एजेंसी ने सरकार को इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होने की संभावना के बारे में अग्रिम सूचना नहीं दी थी. पिछले कुछ महीनों के दौरान घाटी में नौजवानों ने सशस्त्र पुलिसकर्मियों से दर्जनों राइफलें छीन लीं, लेकिन इनमें से कोई भी हथियार बरामद नहीं किया जा सका. आए दिन यह दुष्प्रचार किया जाता है कि कश्मीरी युवाओं को पैसे देकर पथराव कराया जाता है. अगर ये सही है, तो ऐसे 10-20 युवाओं को पकड़कर सबूत समेत मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया जाता. अगर मान भी लिया जाए कि यहां होने वाली हर घटना के पीछे पड़ोसी देश और उसकी एजेंसियां हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में इंडिया की नहीं बल्कि पड़ोसी देश की रट है. ऐसी दर्जनों मिसालें हैं, जो इंटेलीजेंस एजेंसियां, सुरक्षा संस्थान और सरकार को नाकाम साबित करती हैं. केंद्र सरकार कश्मीर के बारे में ज़मीनी तथ्यों को स्वीकार करने के बजाय बल प्रयोग से हालात से निबटने की कोशिश करती नज़र आ रही है. श्रीनगर संसदीय सीट के चुनाव के दो दिन बाद ही यानि 11 अप्रैल को मुंबई में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर के हालात एक वर्ष के अन्दर बदल दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बदलाव कैसे आए, लेकिन यह पक्का है कि कश्मीर एक साल के अन्दर-अन्दर बदल जाएगा. गृहमंत्री ने कहा कि वे सेना प्रमुख के उस बयान से पूर्ण सहमति रखते हैं कि कश्मीर में सुरक्षा बलों को अपनी ड्यूटी में रूकावट डालने वालों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए. घाटी में अधिकतर विश्लेषकों का मानना है कि गृहमंत्री का ये बयान इशारा करता है कि कश्मीर में हालात बेतहाशा बल प्रयोग से ठीक किए जाएंगे. अगर ऐसा ही है, तो संभव है कि आने वाले समय में घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों बड़े पैमाने पर मारधाड़ होगी. लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या इससे वाकई हालात सामान्य हो जाएंगे. संभव है कि इस प्रकार की नीति के कारण यहां क़ब्रिस्तान जैसी ख़ामोशी पैदा होगी, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस प्रकार की खमोशी किसी भी स्थिति में पूर्ण शांति में नहीं बदल सकती है. ये बात कितनी भी कड़वी हो, लेकिन सच तो यही है. कश्मीर समस्या की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. भारत सरकार की अनगिनत वादाखिलाफियों और भ्रम के साथ-साथ मानवाधिकार के खुले उल्लंघन का सिलसिला इस समस्या से जुड़ा हुआ है. यह एक राजनीतिक समस्या है, जिसका हल ताक़त के प्रयोग से हरगिज़ नहीं हो सकता. जम्मू-कश्मीर में फिलहाल लाखों की संख्या में सेना और अर्द्धसैनिक बल मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है कि पिछले तीन दशकों के दौरान इतनी बड़ी सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां यहां हिंसा को खत्म नहीं कर सकी.

घाटी में हालात ठीक करना सेना के वश में होता, तो इस काम के लिए तीन दशकों का समय काफी था. इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि कश्मीर में जारी आंदोलन को भरपूर जनसमर्थन प्राप्त है. कश्मीरियों की नई नस्ल पूर्ण रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है. इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए, बिना शर्त बातचीत ही एकमात्र रास्त हो सकता है. सभी पक्षों के साथ गंभीर और सकारात्मक बातचीत से ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है. इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के बाद ही यहां शांति की स्थापना संभव हो सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों में 2168 करोड़ रुपए की अनियमितता

ग़रीब प्रदेश में 'विकास' की लूट

चौथी दुनिया ब्यूरो

बात एक ऐसे प्रदेश की जिसे प्रकृति ने समृद्ध-संपन्न बनाया, लेकिन प्रशासनिक अकुशलता, सरकारी काहिली, नीतियों और दूरदृष्टि के अभाव में आज यह पिछड़े प्रदेशों से होड़ ले रहा है. आदिवासियों, वंचितों और पिछड़ों की बहुलता वाले इस प्रदेश का आलम यह है कि स्पष्ट सोच और रणनीति नहीं होने के कारण सरकार अपने बजट का 20,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर सकी है. अगर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और सड़क निर्माण की परतों को जरा सा उधेड़ें, तो हर तरफ धूल की मोटी परत जमी नजर आती है.

छत्तीसगढ़ में रमण सिंह की छवि सुशासन बाबू से कमतर नहीं है. अन्य प्रदेशों की भांति यहां भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों का निजीकरण कर मुनाफाखोर कंपनियों के हवाले करने की होड़ मची है. लेकिन कैग की रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के झूठे विकास के दावों की पोल खोल दी है.

भू-जलस्तर बनाए रखने और किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए सरकार 2680 करोड़ रुपए में 369 एनीकेट बना रही है. एनीकेट निर्माण में विलंब एवं आधे-अधूरे बने एनीकेटों पर सरकार ने 1096 करोड़ रुपए व्यर्थ में ही खर्च कर दिए. सरकार की काहिली कहें या प्रशासनिक अक्षमता 10 साल बीत जाने के बाद भी अब तक 280 एनीकेट नहीं बन पाए हैं. यहां तक कि एनीकेट निर्माण के समय बुनियादी चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया गया. मसलन, गर्मी में भू-जल स्तर की उपलब्धता, खेतों में बिजली का नहीं होना, एनीकेट से खेतों की दूरी और खेत के किनारों की अत्यधिक ऊंचाई आदि. या यूं कहें कि विभाग ने एनीकेट से खेतों तक पानी की आपूर्ति का कोई प्रबंधन ही नहीं किया या इस बारे में सोचा भी नहीं.

वहीं, 35 एनीकेटों का निर्माण उन नदियों और नालाओं पर किया गया, जहां बारह मास पानी उपलब्ध नहीं रहते हैं, जिसके कारण यह परियोजना अपने लक्ष्य से दूर होती चली गई. आलम यह है कि मात्र छह से आठ एनीकेटों में ही साल भर पानी उपलब्ध रहता है. केंद्रीय जल बोर्ड ने जानकारी दी कि चयनित मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण 47 एनीकेट भू-जल स्तर में वृद्धि नहीं कर सके. कुछ एनीकेट बने भी, तो डेढ़ साल के भीतर ही खराब हो गए. कबोगा, मैनपुर, सिरपुर और बड़गांव एनीकेट निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण वह ढह गया या मुख्य दीवार में दरार पैदा हो गई.

171 डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में जाकर काम करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया. उलटे उनकी 66 लाख की अनुबंध राशि भी जब्त कर ली गई. मार्च 2016 के आंकड़ों के अनुसार अभी 17 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि सरकार ने दावा किया था कि 1 हजार लोगों पर एक डॉक्टर की सुविधा दी जाएगी. ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने वाली नर्सों की बात करें, तो अभी एक लाख लोगों पर एक नर्स तैनात है, जबकि सरकार ने एक लाख लोगों पर 75 नर्सों की तैनाती का वादा किया था.

अगर किसी राज्य की आर्थिक सेहत और विकास के पैमाने को समझना हो, तो सबसे आसान तरीका सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नीति को जान लेना है. शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो राज्य में केवल 25 प्रतिशत स्कूल ही ग्रेड ए हैं. बाकी 75 प्रशित स्कूल बी से लेकर डी ग्रेड तक के हैं. यह बात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान सर्वेक्षण के दौरान सामने आई. हाल में स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए 858 करोड़ रुपए दिए गए, जिसे सरकार ने शिक्षकों के वेतन पर खर्च कर दिया. पंचायत स्तर पर स्कूलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए, जिसे सरपंचों ने हड़प कर लिया. होटल मैनेजमेंट कोर्स शुरू करने के लिए 18 करोड़ खर्च कर दिए गए, लेकिन कई साल बाद भी क्लास शुरू नहीं हुई है. शिक्षकों और छात्रों के बिगड़े अनुपात को सुधारने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं. राज्य में कुल शिक्षकों के 20 प्रतिशत यानी करीब 12 हजार शिक्षक अनट्रेंड हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए 945 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया. प्रशिक्षु डॉक्टरों को लगता है कि अगर शुरू में ही ग्रामीण इलाकों में काम करना पड़ा तो यह उनके करियर के लिए घातक होगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय उपकरणों का अभाव, एंबुलेंस की सुविधा नहीं होने और बुनियादी समस्याओं के कारण भी डॉक्टर ग्रामीण इलाकों से दूर भागते हैं. लेकिन यह आंशिक सच है. 171 डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में जाकर काम करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया. उलटे उनकी 66 लाख की अनुबंध राशि भी जब्त कर ली गई. मार्च 2016 के आंकड़ों के अनुसार अभी 17 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि सरकार ने दावा किया था कि 1 हजार लोगों पर एक डॉक्टर की सुविधा दी जाएगी. ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने वाली नर्सों की बात करें तो अभी एक लाख लोगों पर एक नर्स तैनात हैं, जबकि सरकार ने एक लाख लोगों पर 75 नर्सों की तैनाती का वादा किया था. माकपा ने कहा है कि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में 2200 करोड रुपयों का घोटाला दिखाता है कि आदिवासी-दलितों व कमजोर तबकों के लिए बनी योजनाओं में किस तरह सेंध लगाई जा रही है. कैग की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदेश में जल, जंगल, जमीन और खनिज की लूट मची है, वहीं पूंजीपतियों और शराब निर्माताओं पर सरकार मेहरबानी बरत रही है.

अगर विज्ञापनों पर एक नजर डालें तो देश के सभी राज्य नंबर वन होने का दावा करते हैं. राज्यों में विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, लेकिन अगर यही कवायद सिर्फ चेहरा चमकाने तक सीमित हो, तो फिर विकास की बात कौन करे? अब तक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक रहे आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है. इस हड़भोंग में आदिवासियों, वंचितों की जायज मांगें भी दफन हो जाती हैं या नक्सल प्रायोजित मांगें बताकर सरकार उन्हें अनसुना कर देती है. ऐसे में विकास के जादुई आंकड़ों से जनता को कुछ समय तक तो भरमाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में सरकार को इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैग ने उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ में महालेखाकार की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि राज्य में 2184 करोड़ रुपए के अनियमित खर्च सरकार ने किए हैं. इस प्रतिवेदन में 3146 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च एवं 2016 के बजट का 80 हजार करोड़ रुपए में से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाने की जानकारी भी दी गई है. मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर विधानसभा की लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा जांच की जाएगी. जांच के उपरांत विधानसभा में इसे प्रस्तुत किया जाएगा. ■

सिंधिया परिवार पर शिवराज के बयान से भाजपा में घमासान

सोरिन शर्मा

सिंधिया परिवार की अंग्रेजों के साथ दोस्ती को लेकर दिए गए शिवराज सिंह चौहान के बयान के कारण भाजपा में अभी भी अंदरूनी कलह मची हुई है. एक तरफ पार्टी जहां इस मामले को दबाने में जुटी है, वहीं भाजपा नेता एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष डॉ. हितेश वाजपेयी ने विवाद को और भी बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री के बयान के बाद सिंधिया परिवार को राष्ट्रीय शर्म का विषय बताने वाले डॉ. वाजपेयी ने एक चैनल पर डिबेट में दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एमपीसीए (म.प्र.क्रिकेट एसोसिएशन) का अध्यक्ष बनवाने में मुख्यमंत्री ने उनकी मदद की थी. वाजपेयी के बयान पर भाजपा ने चुप्पी साध ली है, वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

म.प्र. सरकार में स्वास्थ उप संचालक की नौकरी छोड़कर भाजपा में आए डॉ. वाजपेयी पार्टी के प्रदेश संवाद प्रमुख रहे हैं. प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे की सिफारिश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाकर लालबत्ती दी थी. मुख्यमंत्री के बयान के बाद वाजपेयी द्वारा सिंधिया परिवार पर लगातार तीखे हमले किए जाने को लेकर भाजपा में भी मंथन शुरू हो गया है कि वाजपेयी से सिंधिया परिवार पर हमला करवाने के पीछे की रणनीति क्या है. प्रदेश पदाधिकारी फिलहाल डॉ. वाजपेयी के बयान से किनारा किए हुए हैं, क्योंकि एमपीसीए चुनाव में मुख्यमंत्री द्वारा सिंधिया की मदद करने का डॉ. वाजपेयी का दावा पार्टी के गले नहीं उतर रहा है. यदि वाजपेयी के दावे पर यकीन करें, तो मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को हरवाया, क्योंकि क्रिकेट चुनाव में सिंधिया के सामने विजयवर्गीय ही थे.

इधर कांग्रेस भी सिंधिया मामले में शांत है, क्योंकि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डु ने मुख्यमंत्री के उस बयान का समर्थन किया है, जो उन्होंने अटेर की चुनावी सभा में सिंधिया परिवार को लेकर दिया था. गुड्डु के बयान के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर है. मुख्यमंत्री के उस बयान का सबसे पहले विरोध उन्हीं की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया था. यशोधरा शिवराज सिंह चौहान के बयान से इतनी आहत हैं कि वे अटेर में पार्टी का प्रचार करने भी नहीं गईं. यशोधरा राजे सिंधिया ने जवाबी प्रतिक्रिया में कहा कि भाजपा वो दौर भूल गई, जब महल के भीतर गहने बेचकर भाजपा पर खर्च किया जाता था. चुनाव प्रचार से लेकर पूरा इंतजाम महल के भीतर से होता था. इन्होंने भिण्ड जिले के अटेर और उमरिया के बांधवगढ़ में प्रचार से भी इंकार कर दिया. मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर प्रदेश भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं ने भी यशोधरा राजे का समर्थन किया और इनके साथ खड़े आए. पार्टी के पूर्व सांसद और पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे रघुनंदन शर्मा और पांच बार के सांसद और पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने भी यशोधरा राजे की प्रतिक्रिया पर सहमति जताई. शर्मा ने कहा कि राजमाता ने भाजपा के लिए जो किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए धन के साथ खून पसीना भी लगा दिया था. प्रदेश में पार्टी को विस्तार देने के लिए उन्होंने जो मेहनत की, जिस तरह से लगातार दौरे किए, वह कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है.

यशोधरा राजे

डॉ. हितेश वाजपेयी

पार्टी के कई बुजुर्ग नेता भी इस बात को लेकर अब चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है कि वे राजमाता विजयराजे सिंधिया द्वारा इस पार्टी पर किए गए उपकारों और अहसानों को भुला दे रहे हैं. आज जब ये नेता विजयराजे सिंधिया पर निशान साध रहे हैं, तो कल तो पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे नेताओं की कार्यशैली के बारे में भी सवाल हो खड़े कर सकते हैं. सवाल उठाने वाले ये नेता भूल गए हैं कि राजमाता सिंधिया के साथ-साथ कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल की त्याग तपस्या और कार्यप्रणाली के कारण ही भाजपा आज मध्य प्रदेश में सत्ता में है. भाजपा के कई बुजुर्ग नेता दबी जुबान ये कह रहे हैं कि राजनीति को कमाई और अपनों को फायदा पहुंचाने का जरिया बनाने वाले आज के ये नेता क्या जानें कि राजनीति क्या होती है. पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले जिन नेताओं पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे आज के लोगों को राजनीति सीखने की जरूरत है. आज के इन नेताओं ने राजनीति की आड़ में अपने परिवार का कितना भला किया, ये बताने की बात नहीं है. भाजपा के 13 वर्षों के शासनकाल में सत्ता के दलालों के साथ-साथ प्रदेश में सक्रिय मंत्रियों व अधिकारियों ने किस तरह से लूटमारी और फर्जी आंकड़ेबाजी कर अपनी तिजोरी भरने का काम किया ये सब जानते हैं. आज भी ऐसे रैकेट सक्रिय है. आज प्रदेश में सरकारी योजनाओं में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है. यही कारण भी है कि जिनके पास कल तक टूटी साइकिल तक खरीदने के पैसे नहीं थे, वे आज वह आलीशान भवनों में रह रहे हैं और लग्जरी कारों में फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं.

यशोधरा राजे सिंधिया सरकार और पार्टी में अपनी उपेक्षा को लेकर काफी दिनों से व्यथित हैं. यशोधरा राजे हमेशा ही अपनी मां के पदचिन्हों पर चलते हुए जनहित में काम करती रही हैं. गौर करने वाली बात ये भी है कि मुख्यमंत्री के कहने पर भी यशोधरा राजे ने अपने विभाग से अंबानी को 13 करोड़ रुपए की छूट देने से मना कर दिया था. यही नहीं, उद्योग विभाग में जिस तरह की धांधली चल रही थी, उसे बढ़ावा देने वाले फैसलों को लेकर वे लगातार असहमति जताती रही थीं. यशोधरा राजे के ऐसे कई फैसलों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनका विभाग बदल दिया. इनका विभाग बदलते ही राज्य सरकार की तरफ से न सिर्फ अंबानी को करोड़ों रुपए दिए गए, बल्कि अन्य कई उद्योगपतियों को भी फायदा पहुंचाया गया. इसी क्रम में राज्य में कोकाकोला के प्लांट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. सिंधिया परिवार पर मुख्यमंत्री के बयान को इन सब घटनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

कांग्रेस-मुक्त भारत में कांग्रेस-युक्त नीति

कश्मीर में हुए उपचुनाव में केवल 7 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछले 22 वर्ष में सबसे ख़राब वोटिंग है. लोगों को वोट देने को राज़ी करने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए. कश्मीर में गुलाम मुहम्मद भट्ट के नेतृत्व वाली जमात-ए-इस्लामी के एक अन्य नेता ने एक बार कहा था कि कश्मीर की राजनीतिक स्थिति से चुनाव का कुछ लेना देना नहीं है. कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच सुलझना है. दूसरे शब्दों में, जब तक मसले का कोई समाधान नहीं निकल जाता, तब तक सामान्य गतिविधियां चलती रहनी चाहिए. लोगों को वोट देना चाहिए, उन्हें अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, चाहे वो पंचायत के लिए हो, विधान सभा के लिए हो या संसद के लिए हो. लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए. मुझे इस में कुछ भी ग़लत नहीं लगता यदि राजनीतिक दल यह घोषणा करें कि उनके चुनाव में हिस्सा लेने से कश्मीर मुद्दे पर उनके पक्ष में कोई बदलाव नहीं आएगा और ये हर पक्ष के लिए मान्य होगा.

संसद में कुछ उपयोगी बिल विपक्ष की मदद से पास हुए और कुछ बिल (मनी बिल घोषित करके) विपक्ष की मदद के बिना पास हुए. यह संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परम्परा के लिए ठीक नहीं है. लेकिन संसद के कार्य को रोजाना बाधित करना भी किसी तरह से ठीक नहीं है. लिहाज़ा, कुल मिला कर संसद में कुछ उपयोगी कार्य होने से देश को फायदा हुआ. जीएसटी पर भले ही सभी राज़ी हो जाएं, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है. बहरहाल, यह बिल यूपीए द्वारा लाया गया था और एनडीए द्वारा पास हुआ. लिहाज़ा, इस पर सभी पक्षों की सहमती रही. देखते हैं, जब इसे लागू किया जाता है, तो यह कैसे काम करता है. दूसरे देशों में, जहां जीएसटी लागू हुआ है, वहां 7 साल के बाद रेवेन्यू न्यूट्रल हुआ. भारत के लिए 7 साल एक लम्बा समय है. देखते हैं क्या होता है. लेकिन टैक्स निर्धारण को आसान बनाना हमेशा सराहनीय है. खास तौर पर उपभोक्ता और करदाता के दृष्टिकोण से. भ्रष्ट अधिकारियों को मायूसी होगी, क्योंकि उनके लिए पैसे बनाने के मौके कम हो जाएंगे. कुल मिला कर जीएसटी को कर सुधार के तौर पर देखा जाता है. लेकिन अमेरिका में जीएसटी नहीं है, जबकि यूरोप में यह लागू है. इसके लागू होने के एक या दो साल के बाद ही हम इसकी कामयाबी या नाकामी पर टिप्पणी कर पाएंगे. मैं आशा करता हूं कि संसद के अगले सत्र से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिछले दरवाज़े से कुछ समझौता होगा, ताकि संसद की कार्रवाई के लिए कुछ स्वास्थ्य उदारण स्थापित किया जा सके. देश को इसकी आवश्यकता है.

पाकिस्तान द्वारा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भारतीय कुलभूषण यादव को सजा-ए-मौत सुनाई गई है. आम तौर पर शांतिकाल में जासूसों को सजा-ए-मौत नहीं सुनाई जाती है, अगर मान भी लिया जाए कि वो जासूस हैं. इस मामले को लेकर बहुत विवाद है. लोगों का कहना है कि वो जासूस नहीं हैं. वे वहां आम पासपोर्ट और वीज़ा पर गए थे. लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है. वहां सत्ता किस के हाथ में है, हमें मालूम नहीं है. इस

मामले में सरकार को अपनी पूरी कौशल अपनानी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े, तो पाकिस्तान पर दबाव भी बनाना चाहिए. मैं समझता हूं कि हमारे पास उनके कुछ कैदी होंगे. हम बात कर सकते हैं और बिना जानी नुकसान के कैदियों का आदान प्रदान कर सकते हैं. लेकिन यह विदेश मंत्रालय के नौकरशाहों के अलावा नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर और पीएमओ पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला करते हैं.

कश्मीर में हुए उपचुनाव में केवल 7 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछले 22 वर्ष में सबसे ख़राब वोटिंग है. लोगों को वोट देने को राज़ी करने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए. कश्मीर में गुलाम मुहम्मद भट्ट के नेतृत्व वाली जमात-ए-इस्लामी के एक अन्य नेता ने एक बार कहा था कि कश्मीर की राजनीतिक स्थिति से चुनाव का कुछ लेना देना नहीं है. कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच सुलझना है. दूसरे शब्दों में, जब तक मसले का कोई समाधान नहीं निकल जाता, तब तक सामान्य गतिविधियां चलती रहनी चाहिए. लोगों को वोट देना चाहिए, उन्हें अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, चाहे वो पंचायत के लिए हो, विधान सभा के लिए हो या संसद के लिए हो. लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए. मुझे इस में कुछ भी ग़लत नहीं लगता यदि राजनीतिक दल यह घोषणा करें कि उनके चुनाव में हिस्सा लेने से कश्मीर मुद्दे पर उनके पक्ष में कोई बदलाव नहीं आएगा और ये हर पक्ष के लिए मान्य होगा. लेकिन इतना खर्चीला चुनाव करवाने पर भी यदि उसमें केवल 7 प्रतिशत लोग हिस्सा लें, ये निश्चित रूप से अस्वीकार्य है. हमें आशा करनी चाहिए कि कश्मीर पर सरकार प्रो-एक्टिव रुख अपनाएगी और पाकिस्तान से बैक चैनल बातचीत शुरू करेगी और मसले का कोई समाधान तलाश करेगी.

उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के बाद भाजपा में और सरकार में ये धारणा बन गई है कि उन्होंने भारत पर हमेशा के लिए जीत हासिल कर ली है. ये स्थिति का ग़लत आकलन है. राजीव गांधी लोक सभा में 400 से अधिक सीटों के साथ जीते थे, उनके बाद ऐसी जीत फिर किसी को नहीं मिली है. लेकिन केवल दो साल में उस सरकार ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी थी और वे 1989 का चुनाव हार गए थे. इस सरकार को भी ऐसे ही दिन देखने पड़ सकते हैं, यदि ये सतर्क नहीं हुए. जनता बहुमत इसलिए देती है, ताकि सरकार देश के लिए बेहतर काम कर सके. केवल सत्ता सुख उठाने और संख्या पर इतराने से कुछ नहीं होगा. कुल मिला कर मौजूदा सरकार कांग्रेस की नक़ल कर रही है. चाहे मनरेगा हो या आधार हो. गोवा में जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, वो भी कांग्रेस की ही नक़ल थी. लिहाज़ा, वे कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, लेकिन लोगों को वे कांग्रेस युक्त नीति परोस रहे हैं. वैकल्पिक राजनीति का सवाल अब खत्म हो गया है. देखते हैं अगले आम चुनाव में ये सरकार मतदाताओं को अपनी कौन सी उपलब्धियां दिखाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सुरंग के अंत में भी अंधकार ही है

शुजात बुख़ारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के हालात से निपटने के लिए केवल प्रशासनिक तरीका ही इस्तेमाल करेगी. 2 अप्रैल को श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर बनी भारत की सबसे लंबी सुरंग के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए उन्होंने बंदूक चलाने वाले और पत्थर फेंकने वाले युवाओं के बीच कोई अंतर नहीं किया. दरअसल, उन्होंने उनलोगों की सराहना की जिन्होंने उनके अनुसार सुरंग बनाने के लिए पत्थर की नक्काशी की. अपने जोशीले भाषण में प्रधानमंत्री ने राह भटके युवाओं से टेररिज्म और टूरिज्म के बीच फर्क पहचानने के लिए कहा.

मैं कश्मीर घाटी के राह भटक चुके युवाओं से कहना चाहता हूं कि वे पत्थर की ताक़त को पहचाने, ये बात उन्होंने अपने उस भाषण में कहीं जो विकास पर केंद्रित था और टकराव की राजनीति से बचने वाला था. उन्होंने कहा कि एक तरफ राह भटक चुके युवा हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर से आने वाले वे युवा हैं, जो यहां बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पत्थर पर नक्काशी कर रहे हैं.

मोदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर कश्मीर का दौरा किया है. विकास पर उनके जोर ने यह इशारा दे दिया कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार की कश्मीर नीति क्या होगी. कश्मीर में अभी बसंत का मौसम है. पिछले साल छह महीने तक चली हिंसा, जिसने आम जन-जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, को देखते हुए अभी से लोगों के मन में आशंकाएं पैदा होने लगी है कि इस साल की गर्मियां कैसी बीतने वाली है. यहां संशय बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों की घटनाएं यह ज़ाहिर करती हैं कि अभी भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. मिलिटेंट्स के हमलों की बढ़ रही संख्या और उनको बचाने के लिए एनकाउंटर स्थल पर नागरिकों के पहुंचने की घटनाएं एक अलग तरह की कहानी कहती हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एस पी वैद इसे आत्मघाती प्रवृत्ति बताते हैं. लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने यह साफ़ कर दिया है वे ऐसा करेंगे, भले इसका मतलब मौत ही क्यों न हो.

इस पृष्ठभूमि में मोदी के भाषण से समस्या के समाधान के लिए किसी पहल की ओर कोई इशारा नहीं मिलता. हार्डलाइनर हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अपने एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कश्मीर मामले में वे एक स्टेट्समैन की भूमिका निभाएं. एक तरह से देखा जाए, तो कश्मीर में अभी भी नई दिल्ली से बातचीत की आशा बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली ने अपने सभी दरवाजे बंद कर लिए हैं और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सशस्त्र बलों पर निर्भर है. इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि उसे कोई मतलब नहीं कि हालात राजनीतिक पहल की मांग कर रहा है.

मोदी ने बदलाव के एक एजेंडे के तौर पर बार-बार पर्यटन की बात की. इसमें शक नहीं कि कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में बेपनाह क्षमता है और पर्यटन बाजी पलटने वाला क्षेत्र बन सकता है. वर्ष 2003 से 2007 तक होने वाली राजनीतिक पहल के दौरान यह साबित हुआ कि ऐसा हो सकता है. जब भारत, पाकिस्तान और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जारी थी, तो उस समय पर्यटन अपने चरम पर था. लेकिन 2016 में हुए छह महीने के हंगामे ने यह दिखाया कि कैसे यह बुरी तरह नाकाम भी हो सकता है. पर्यटन के लिए शांति और स्थिरता बड़ी शर्त है. जब बम और बुलेट की बारिश होती है, तो उसमें पर्यटन का विकास नहीं हो सकता. शांति बहाल करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण ज़रूरी है. कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्वीकार लेने से यहां समृद्धि के दरवाजे खुल सकते हैं.

बहरहाल, पिछले कुछ सालों में लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है, खासकर युवा पीढ़ी में, जो राजनीतिक रूप से उग्र हो गई है. जिन्हें नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए वे भारत विरोधी प्रदर्शन का आयोजन करते हुए देखे जा रहे हैं. वे आक्रामक हो गए हैं. इसी वजह से मार्च के आखिरी हफ्ते में मध्य कश्मीर के चदूरा इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान तीन युवा लड़कों की मौत हुई. ऐसी स्थिति से निपटने की चुनौती सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रही है. राजनीतिक मोहभंग को नकारना आग में घी का काम कर रहा है. मोदी के विकास का एजेंडा इस तथ्य के बावजूद आया कि उनकी पार्टी भाजपा क्षेत्रीय पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन के एजेंडे राज्य के राजनीतिक स्वभाव पर केंद्रित हैं.

मोदी ने बदलाव के एक एजेंडे के तौर पर बार-बार पर्यटन की बात की. इसमें शक नहीं कि कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में बेपनाह क्षमता है और पर्यटन बाजी पलटने वाला क्षेत्र बन सकता है. वर्ष 2003 से 2007 तक होने वाली राजनीतिक पहल के दौरान यह साबित हुआ कि ऐसा हो सकता है. जब भारत, पाकिस्तान और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जारी थी, उस समय पर्यटन अपने चरम पर था. लेकिन 2016 में हुए छह महीने के हंगामे ने यह दिखाया कि कैसे यह बुरी तरह नाकाम भी हो सकता है. पर्यटन के लिए शांति और स्थिरता बड़ी शर्त है. जब बम और बुलेट की बारिश होती है, तो उसमें पर्यटन का विकास नहीं हो सकता. शांति बहाल करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण ज़रूरी है. कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्वीकार लेने से यहां समृद्धि के दरवाजे खुल सकते हैं.

पीडीपी-बीजेपी शासन के दो वर्षों के दौरान कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया है. एजेंडे के केवल तीन बिंदुओं को लागू करने में तेज़ी दिखाई गई है. पहला पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के बारे में है. दूसरा, दो मुद्दे कश्मीर के दूसरी तरफ के शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से संबंधित हैं. विवादास्पद मुद्दे, जिनसे क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है, जैसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा), हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ बातचीत और राजनीतिक कैदियों की रिहाई जैसे मुद्दों को छुआ तक नहीं गया है. इससे यही साबित हुआ कि गठबंधन का एजेंडा केवल कागजों पर ही रहा. इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की बात केवल पीडीपी और भाजपा को साथ लेने के लिए माहौल तैयार करने के लिए की गई थी. यह उम्मीद की जा रही थी कि यूपी चुनाव के बाद मोदी, पाकिस्तान और संभवतः कश्मीरियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो उम्मीद समाप्त हो गई है.

मोदी ने एक और दिलचस्प टिप्पणी की, जो कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी. उन्होंने कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत की बात की थी, जिसने एक बार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए मेरा संदेश यह है कि कश्मीर के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी, सरकार उसे आगे बढ़ाएगी और राज्य की जनता का दिल जीतना मेरा लक्ष्य है. उसी तरह 22 नवंबर, 2014 को उन्होंने किश्तवार में कहा था कि अटल जी के शब्दों जम्हूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का कश्मीरियों के दिल में एक विशेष स्थान है. इन शब्दों ने कश्मीर के नौजवानों के दिलों में एक बेहतर भविष्य की आशा जगाई थी. 10 अगस्त 2016 को जब कश्मीर राजनीतिक अशांति की आग में जल रहा था, तो उन्होंने इस बारे में बात तो की, लेकिन सत्ता में आने के बाद से उस दिशा में एक इंच आगे नहीं बढ़े हैं. उन्हें समझना चाहिए कि वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम किया, हिजबुल मुजाहिद्दीन से बातचीत शुरू की और हुर्रियत को बातचीत की मेज तक लेकर आए. हालांकि बात बहुत आगे नहीं बढ़ी, लेकिन वाजपेयी जी ने एक रास्ता दिखाया, जो आशाओं से भरा हुआ था.

जम्मू और कश्मीर में विकास पर लगातार जोर देना, मोदी की कश्मीर नीति का मूल मंत्र है. लेकिन वाजपेयी जी के संदर्भ का मतलब केवल विकास ही नहीं था, बल्कि कश्मीर की राजनीतिक वास्तविकता को पहचानते हुए ऐसे रास्ते पर चलना था, जिसमें राज्य और पाकिस्तान, दोनों शामिल हो सकते थे. जब वाजपेयी जी ने 18 अप्रैल, 2003 को श्रीनगर से पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू की, तो उस समय दोनों देशों के संबंध आज की तुलना में अधिक ख़राब थे. उनके लिए इस्लामाबाद के साथ बिना शर्त दोस्ती की पेशकश करना जोखिम भरा था. इस पेशकश के साथ-साथ उन्होंने कश्मीर में भी एक संवाद प्रक्रिया शुरू की. मोदी को उसी रास्ते पर चलना होगा, जिस पर केवल राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ ही चला जा सकता है. राजनीति के बाद विकास हो सकता है, विकास के बाद राजनीति नहीं हो सकती. ■

लोगों में राजनीतिक सम्भावना जगाई थी. मोदी ने इससे पहले सात बार इसका ज़िक्र किया है. जब 2014 के चुनाव में वे दिल्ली की सत्ता की ओर बढ़ रहे थे, तब पहली बार उन्होंने इस जादुई कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत की बात की थी. 26 मार्च, 2014 को उन्होंने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वे कश्मीर के मामले में वाजपेयी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे. उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि वाजपेयी जी द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा करूं. यह मेरी इच्छा है और मैं इसके लिए बार-बार यहां आऊंगा.

प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपना रुख नहीं बदला और 4 जुलाई 2014 को कटरा

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

योगी आदित्यनाथ जी प्राथमिकताएं और ज़िम्मेदारी तय कीजिए

उत्तर प्रदेश की चर्चा चारों तरफ है और भारतीय जनता पार्टी को मिली अभूतपूर्व विजय ने उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर नए सिरे से स्थापित कर दिया है. अब सवाल इतना है कि ये नक्शा बनता कैसा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रणनीति से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद अपने नाम कर लिया. सच्चाई चाहे जो हो, पर सत्यतता ये है और वास्तविकता भी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं और उत्तर प्रदेश में उनके नाम को लेकर आशाएं भी बढ़ गई हैं. आशाएं बढ़ने के पीछे का कारण है, उनका रुख, उनकी बातचीत का तरीका, उनके तेवर और उनके काम करने की जिजीविषा. ये सब मिलकर योगी को देश के वर्तमान मुख्यमंत्रियों से एक अलग तरह का मुख्यमंत्री बना रहे हैं.

ये सारी बातें आने वाले महीनों में सच साबित होती हैं कि नहीं, इसके ऊपर हल्का सा संदेह या धुंधलापन आ गया है. उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ को कानून और व्यवस्था के ऊपर जो एमफेसिस (जोर) देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया. कानून-व्यवस्था के नाम पर उनके संगठन हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, हिन्दू युवा वाहिनी के हैं या स्थानीय लफंगे हैं, ये तय होना अभी बाकी है. वो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक आतंकवाद फैला रहे हैं. लेकिन इस सांस्कृतिक आतंकवाद से पहले हम कानून और व्यवस्था की बात करते हैं. अगर प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में दिनदहाड़े चौक जैसे व्यस्त क्षेत्र में जेवर की दुकान में डकैती हो जाए और डकैत फायर करते हुए निकल जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे? जबकि वहीं पर कोतवाली है, लोगों की भीड़ है और उन लोगों की भीड़ है, जिन्होंने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय दिलाई. बनारस में ही छह दिन के अंतराल में दिनदहाड़े दूसरी डकैती हुई. लुटेरों को या डकैतों को न कानून व्यवस्था की चिंता है, न पुलिस का डर और न योगी के चेहरे का खौफ. वे निर्द्वंद्व होकर अपराध करके निकल गए. दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस वालों के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं. ठीक वैसे ही, जैसे पिछले शासनकाल में होते थे. पहले सत्ता से जुड़े नेता पुलिस के ऊपर हमला करते थे, अब भी सत्ता से जुड़े नेता पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं. इसलिए जिस कानून व्यवस्था का शोर भारतीय जनता पार्टी ने इतना मचाया था, योगी आदित्यनाथ का पहला एक महीना उन दावों की हंसी उड़ा रहा है. योगी आदित्यनाथ को सबसे पहला ध्यान कानून-व्यवस्था की ओर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले तीस दिन अगर कानून व्यवस्था में सुधार न ला पाए, तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि योगी भी आम मुख्यमंत्रियों की श्रेणी के मुख्यमंत्री वाली सूची में शामिल हो जाएंगे.

अब सांस्कृतिक आंतकवाद. ये रोमियो शब्द किसके दिमाग की ऊपज है, मैं नहीं कह सकता. लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द का इस्तेमाल जरूर किया कि हम एंटी रोमियो स्कवॉड बनाएंगे और पुलिस ने उनके इसी वाक्य को आधार मानकर बजाए गुंडे, लुटेरों, अपराधियों, शोहदों को पकड़ने के, एंटी रोमियो स्कवॉड बना दिया. शुरू के छह-सात दिन, जो लड़का या लड़की या पुरुष या महिला एक साथ दिखाई दिए, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उन्हें रोमियो बना दिया. उनमें कोई पिता-पुत्री थे, कोई चाचा-भतीजी थे, कोई पति-पत्नी थे, कोई भाई-बहन थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़ा. कुछ केस में पुलिस ने छोड़ा, कुछ में पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ा. अब ये खबर योगी आदित्यनाथ को है या नहीं है? योगी जी जनता के बीच से निकलने वाले व्यक्ति हैं. उन्हें मालूम है कि पुलिस लहरें गिनकर या किसी भी योजना को बनाकर किस तरह धन कमाती है. शायद योगी जी इसको भूल रहे हैं या भूलना चाहते हैं. क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी है, जो अपने प्रशासन पर नकेल कम कसती है, प्रशासन का खिलौना जरूर बन जाती है.

अब एंटी रोमियो स्कवॉड के नाम पर कई सारे लोग घरों में घुस रहे हैं. खासकर दूसरे समाज के घरों में और ये देख रहे हैं कि वो घर के अंदर कैसे कपड़े पहने हैं. यानि आप अपने घर के अंदर अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, अपने घर के अंदर आप मर्जी का खाना नहीं खा सकते, अपने घर के अंदर भी मनमर्जी को कोई काम नहीं कर सकते. लेकिन ये सारे काम, जो पार्टी सत्ता में बैठी है, उसके समाज के लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है. क्या इसका पता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती करें, जो हिन्दू युवा वाहिनी के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं. अब इसका जवाब सरकार की तरफ से ये आएगा कि आप हमें उन घरों के नाम बताइए और आप सबूत दीजिए कि उनके घर में कौन घुसा. तो मैं माफी मांग लेता हूं कि मैं न आपको नाम बताऊंगा और न कौन घुसा है ये बताने का साहस करूंगा, क्योंकि ये काम सरकार का है. जिस दिन सरकार या प्रशासन कहेगी कि जनता ही सबूत दे, उस दिन सरकार की जरूरत नहीं है. फिर हम मान लेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी एक नए चेहरे वाले जंगल राज का प्रारंभ हो रहा है.

मुख्यमंत्री योगी से आशाएं हैं. उन आशाओं में उत्तर प्रदेश के लोगों की बुनियादी समस्या शामिल है. इसमें स्कूलों की हालत हैं, अस्पतालों की हालत हैं, चिकित्सा की हालत है, शिक्षक गांव के स्कूल में नहीं जाते, सालों से ऐसा हो रहा है. पंद्रह-बीस सालों से ऐसा हो रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ यूनिट में नहीं रहते. इलाज के लिए बोरा भर रुपया खर्च करना पड़ता है. क्या ये समस्याएं योगी आदित्यनाथ को विचलित करेंगी? अगर वो शिक्षा और स्वास्थ्य, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की

> **अगर प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में चौक जैसे व्यस्त क्षेत्र में दिनदहाड़े जेवर की दुकान में डकैती हो जाए और डकैत फायर करते हुए निकल जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे? जबकि वहीं पर कोतवाली है, लोगों की भीड़ है और उन लोगों की भीड़ है, जिन्होंने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय दिलाई. बनारस में ही छह दिन के अंतराल में दिनदहाड़े दूसरी डकैती हुई. लुटेरों को या डकैतों को न कानून व्यवस्था की चिंता है, न पुलिस का डर और न योगी के चेहरे का खौफ.**

सड़क, को अपनी प्राथमिकता में लेंगे, तो लोग उन्हें शुभकामनाएं देंगे.

आखिर में बिजली व्यवस्था, जिसका बहुत शोर पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने मचाया था, लेकिन अभी भी गांव में बिजली नहीं है. आप शहरों में चौबीस घंटे बिजली देने की बात करते हैं. आप उलटा क्यों नहीं करते कि शहरों को आप बारह घंटे बिजली दीजिए और गांव में चौबीस घंटे बिजली दीजिए. किसान को अगर बिजली मिल जाए और सड़क मिल जाए, तो शायद वो आपको दुआएं देगा और धीरे-धीरे अपनी स्थिति ठीक कर लेगा. क्योंकि उसके बाद की चीजों में बाजार भी अपना हित सधता देख किसानों से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ेगा.

अभी योगी सरकार को कुल मिलाकर तीस दिन हुए हैं. बहुत सारे पाठक कहेंगे कि आपने तीस दिन के भीतर ही योगी आदित्यनाथ की आलोचना शुरू कर दी. हम ऐसे पाठकों से निवेदन करना चाहते हैं कि रास्ता शुरू में ही तय होता है और जब रास्ता ही टेढ़ा अस्तित्वार कर लिया जाए, तो फिर मंजिल पर कभी नहीं पहुंचते. हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए. उन प्राथमिकताओं की जिम्मेदारी तय कीजिए. समयबद्ध योजना बनवाइए और जो इस काम को न करे, उसकी जिम्मेदारी निश्चित कर उसके लिए कोई सजा तय कीजिए. प्रशासन का ताना-बाना बहुत बिगड़ा हुआ है और उन लोगों का दिमाग भी बहुत बिगड़ा हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ के नैतिक शब्दाबली से प्रभावित होकर खुद कानून के रखवाले हो गए हैं. मैं आखिर में फिर योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि गाय को दंगे का कारण मत बनाइए. आप हर जिले में एक गोपालक अधिकारी नियुक्त कीजिए. वो गोपालक अधिकारी इसका लेखा जोखा रखे कि उस जिले में किसके पास गाय है. वो गाय बीमार होती है, तो गोपालक अधिकारी को पता हो. गाय चोरी हो जाती है, तो गोपालक अधिकारी को पता होना चाहिए और थाने को उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए. अगर गाय किसी के घर से बिकती है, तो गोपालक अधिकारी को पता होना चाहिए कि ये गाय बिकी है. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आनेवाला समय साम्प्रदायिक दुर्भावनाओं का समय न बने और गाय उसमें मुद्दा न बने. इसलिए ये आवश्यक है कि गाय का लेखा-जोखा सरकार के पास रहे. आखिर में इन शब्दों के साथ मैं योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि गायें खेत में पैदा नहीं होतीं. गायें 90 प्रतिशत या 99 प्रतिशत हिन्दू पालते हैं. वो गाय को माता कहते हैं, पर ऐसे सारे गाय को माता कहने वाले हिन्दू भाई, जो गोशालाएं चलाते हैं, उनकी रिपोर्ट मंगा लीजिए कि गाय के लिए जो पैसा सरकार देती है, उनमें से कितना पैसा गाय के ऊपर खर्च होता है. वहां पर गायों की हालत क्या है? आप अगर अपील करेंगे, तो जिलों के पत्रकार उन गोशालाओं की हालत पर रिपोर्ट बनाकर अपने अखबारों में देंगे. आप उसको देख सकते हैं. सिर्फ इतना कीजिए. प्राथमिकताएं तय कीजिए और जिम्मेदारी तय कीजिए. आप उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री माने जाएंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो सामान्यतम मुख्यमंत्री की श्रेणी में तो कोई भी शामिल हो सकता है. ■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

लोकतंत्र के ख़िलाफ़ संसद

वित्त विधेयक-2017 लोकतंत्र के मूल आधारों को धता बताने वाला है

परंजय गुहा ठाकुरता

अंतिम समय में कुछ संशोधनों को डालने के बाद सरकार ने जिस तरह से वित्त विधेयक-2017 के जरिए 40 कानूनों में संशोधन कर दिया, उसने स्पष्ट संकेत दिया है. मतलब साफ है कि सरकार अपने विरोधियों से बातचीत में यकीन नहीं करती. सरकार का स्वतंत्र न्यायपालिका में यकीन नहीं है. आयकर अधिकारियों के तलाशी और जब्ती संबंधी अधिकारों पर सरकार बहस नहीं करना चाहती. सरकार तो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन ये ऐसा संशोधन लाई है जिससे भारतीय राजनीति में कॉरपोरेट घरानों की भूमिका काफी अधिक बढ़ने का अंदेशा है.

वित्त विधेयक- 2017 को लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश किया गया. ऐसे विधेयकों में अंतिम निर्णय का अधिकार लोकसभा के पास होता है. सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर कई कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इनमें एक संशोधन आधार को लेकर भी है. जबकि आधार कानून को धन विधेयक के तौर पर पारित करने के सरकार के निर्णय को राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. इस पर सुनवाई अभी होनी है. संविधान के अनुच्छेद 110.3 के मुताबिक किसी भी विधेयक को धन विधेयक तय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है. अनुच्छेद 110.1 के मुताबिक किसी भी विधेयक को धन विधेयक तब निर्धारित किया जा सकता है, जब उसमें सिर्फ कर, सरकार की उधारी और गारंटी, सरकारी खर्च या फिर अन्य किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई चीज हो. हर साल बजट प्रक्रिया के तहत पारित किया जाने वाला वित्त विधेयक अमूमन इस परिभाषा में फिट बैठता है. हालांकि, वित्त विधेयक- 2017 कई मामलों में इस परिभाषा से बाहर जाते दिखता है.

उदाहरण के तौर पर, इसके जरिए कंपनी कानून, 2013 की धारा 182 में संशोधन किया गया है. इस धारा में यह प्रावधान था कि कोई भी गैर सरकारी कंपनी पिछले तीन साल के मुनाफे के औसत का 7.5 फीसदी तक ही राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर दे सकती है. अब सरकार ने इस सीमा को हटा दिया है. अब वे कितना भी राजनीतिक चंदा दे सकती है. पहले के प्रावधान के अनुसार, कंपनियों को ये बताना पड़ता था कि किस राजनीतिक दल को उन्होंने कितना चंदा दिया है. इस बार के संशोधन में ये बाध्यता खत्म कर दी गई है. 1985 से पहले इस तरह का चंदा भारत में प्रतिबंधित था. इसमें 1960 से 1969 का दौर अपवाद है. 1985 में कंपनी कानून-1956 में संशोधन करके इसकी शुरुआत हुई.

चुनाव सुधार को लेकर गठित कई समितियों

> **वित्त विधेयक का एक चिंताजनक पहलू आयकर कानून-1961 में संशोधन भी है. इसके जरिए आयकर अधिकारियों के अधिकारों को काफी विस्तार दिया गया है. नए संशोधन के तहत अगर आयकर अधिकारियों को लगता है कि वे तलाशी या जब्ती कर सकते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे. वह भी 1962 के पूर्व प्रभाव से. अगर अधिकारियों की इस कार्रवाई को कहीं चुनौती दी जाए, तो वे वजह बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे. आयकर अधिकारियों को अब इतने अधिकार मिल गए हैं कि वे किसी को भी परेशान कर सकते हैं.**

ने कहा है कि इस तरह की फंडिंग को कंपनियां निवेश के तौर पर देखेंगी और उसके बाद भविष्य में इस पर मुनाफा कमाना चाहेंगी. कहा गया है कि ऐसे चंदों की वजह से सरकार पर संबंधित कंपनी के पक्ष में काम करने का दबाव बनाया जा सकता है. नए संशोधनों से कारोबारी घरानों और राजनीतिक दलों के गठजोड़ को बढ़ावा मिलेगा. इससे राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और भी अपारदर्शी होगी. हालांकि, राज्यसभा ने इस संशोधन को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन लोकसभा ने इसे नहीं माना. वित्त विधेयक-2016 में इसी तरह का एक संशोधन करते हुए सरकार ने विदेशी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव किया था. यह बदलाव तब किया गया था, जब एक अदालत ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को लंदन की वेदांता जैसी कंपनियों के जरिए अवैध चंदा दिया गया था. कुछ ट्राइब्यूनल्स का भी दूसरे में विलय करने संबंधी संशोधन चिंता की बात है. इससे ट्राइब्यूनल्स की मूल भावना को ही चुनौती दी जा रही है. इनकी विशेषज्ञता खतरे में है और पहले से ही बोझ तले दबे ट्राइब्यूनल्स पर और बोझ बढ़ेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इन ट्राइब्यूनल्स में नियुक्ति, काम की शर्तें और सदस्यों को हटाने संबंधित अधिकार अपने हाथ में करना चाहती है. इससे ऐसी संस्थाओं की स्वायतता खतरे में पड़ेगी. 2014 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ऐसी संस्थाओं की नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका की दखल से मुक्त होनी चाहिए. कई बार सरकार खुद इन ट्राइब्यूनल्स के मामलों में पक्षकार होती है. ऐसे में यह हितों के टकराव का मामला भी है. हालांकि, वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार इन मामलों में न्यायपालिका से सलाह-मशविरा करेगी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.

वित्त विधेयक का एक चिंताजनक पहलू आयकर कानून-1961 में संशोधन भी है. इसके जरिए आयकर अधिकारियों के अधिकारों को काफी विस्तार दिया गया है. नए संशोधन के तहत अगर आयकर अधिकारियों को लगता है कि वे तलाशी या जब्ती कर सकते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे. वह भी 1962 के पूर्व प्रभाव से. अगर अधिकारियों की इस कार्रवाई को कहीं चुनौती दी जाए, तो वे वजह बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे. आयकर अधिकारियों को अब इतने अधिकार मिल गए हैं कि वे किसी को भी परेशान कर सकते हैं. इन संशोधनों को निरस्त करने वाले राज्यसभा के संशोधनों को लोकसभा ने खारिज कर दिया. इन संशोधनों के लिए अपनाए गए तरीके ने भारतीय लोकतंत्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसने संसद की उच्च सदन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है. इसलिए इस सरकार द्वारा राज्यसभा को बाइपास करके कानून पारित करवाना बेहद सामान्य हो गया है. जबकि राज्यसभा की व्यवस्था ही इसलिए है कि लोकसभा पर एक अंकुश रहे. अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाकर न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है, बल्कि संवैधानिक भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रही है. ■

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

टीम नित्यानंद को बताया गिरोह तो मचा बवाल

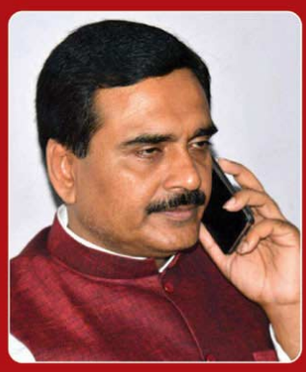

अनुकूल राजनीतिक माहौल के बावजूद सूबे में भाजपा संकट के दौर में फंसती दिख रही है. संकट का एक छोर नए सामाजिक समूहों में अपनी नई-नई पैठ को मजबूत आधार देने का है, तो दूसरा सिरा स्थापित नेतृत्व को साथ रखते हुए उसके अनुभव से लाभ हासिल करते जाने का. बिहार भाजपा के मौजूदा संकट के ये दोनों छोर बड़े ही महत्वपूर्ण बन गए हैं. सूबे की राजनीति में अपनी बढ़त बनाने में दोनों के बीच गंभीर तालमेल की दरकार है. ऐसा करके ही राजनीतिक सक्रियता को सार्थक दिशा दी जा सकती है. ये कैसे होगा, इस बारे में पटना से लेकर दिल्ली तक को सोचना होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व, खास तौर पर अध्यक्ष नित्यानंद राय, के लिए इस महीने के आरंभिक दिन अच्छे नहीं रहे. हालांकि कुछ ही दिन पहले प्रदेश भाजपा की नई टीम घोषित कर दी गई थी. उम्मीद की गई कि नए जोश और नई ऊर्जा से सूबे में पार्टी का काम नए सिरे से पटरी पर आ जाएगा. लेकिन पार्टी के भीतर असंतोष की हवा चलने लगी और रामनवमी आते-आते सब कुछ सतह पर आ गया. प्रदेश भाजपा की नई टीम अपना काम शुरू कर पाती, उससे पहले ही विस्फोट होने लगे. सार्वजनिक तौर पर पहला बड़ा विस्फोट सुधीर कुमार शर्मा ने किया. वे पिछली कमिटी में महासचिव (भाजपा महामंत्री कहना ज्यादा पसंद करती है) थे और कई वर्षों से भाजपा में काफी महत्वपूर्ण बने थे. वे सूबे के तत्कालीन नेतृत्व के प्रियपात्र माने जाते थे. लेकिन नई कमिटी में अपनी (और जैसा वह बताते हैं, कई महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों की) उपेक्षा से आहत होकर वे असंतोष को अभिव्यक्त करने सामने आए और अध्यक्ष पर हमला किया कि अध्यक्ष नित्यानंद राय पार्टी नहीं, गिरोह चला रहे हैं. सुधीर कुमार शर्मा ने प्रादेशिक कमिटी बनाने में और भी गड़बड़ी के कई संगीन आरोप लगाए. इसके दो दिन बाद ही बिहार तैलिक साहू समाज की ओर से एमएलसी लालबाबू प्रसाद को एनडीए की ही एक महिला एमएलसी से दुर्व्यवहार के आरोप में भाजपा से निलंबित कर दिए जाने के विरोध में दिन भर के धरना का आयोजन किया गया था. धरना में लालबाबू प्रसाद तो थे ही, भाजपा के पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू व विधायक सीएन गुप्ता भी शामिल हुए थे. धरना के दौरान सीएन गुप्ता ने तो इतना ही कहा कि वे समाज के साथ हैं और लालबाबू प्रसाद की पार्टी में वापसी चाहते हैं. लेकिन सुनील कुमार पिंटू ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर तानाशाही का आरोप लगाया. उनका कहना था कि लालबाबू प्रसाद का निष्कासन वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का घेराव किया जाएगा. लालबाबू प्रसाद के निष्कासन को नियम के विपरीत बताते हुए धरना स्थल पर नित्यानंद राय का पुतला भी फूंका गया. इसके बाद प्रदेश नेतृत्व सख्त हुआ. पार्टी के बड़े नेता और बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडेय ने चेतावनी दी कि ऐसे आचरण करने वालों को पार्टी माफ नहीं करेगी. इस चेतावनी के अगले ही दिन पार्टी के नव-मनोनीत महासचिव राधामोहन शर्मा ने इन सभी नेताओं से जवाब तलब कर दिया. अब स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही इन सभी- सुधीर कुमार शर्मा, सुनील कुमार पिंटू व सीएन गुप्ता के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकेगा. अभी मामला यहीं पर आकर रूक गया है. लेकिन लाख टके का सवाल है: यहीं रूका रहेगा क्या?

इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है या यों कहें कि कोई देना नहीं चाहता है, न तो नेतृत्व से जुड़ा व्यक्ति और न ही असंतुष्टों की जमात. लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है. हालांकि, सुधीर कुमार शर्मा या सुनील कुमार पिंटू के साथ कोई खुलकर सामने नहीं आना चाहता है, लेकिन पार्टी के बहुत बड़े समूह में नई प्रदेश कमिटी को लेकर तेज खुसर-फुसर जारी है. इस हालत का लाभ फिलहाल सुधीर कुमार शर्मा को मिलता दिख रहा है. पार्टी पदाधिकारियों के सामने कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अनौपचारिक तौर पर सुधीर शर्मा के आरोपों से सहमति जताने वालों की तादाद भी कम नहीं है. सूबे की कुछ महत्वपूर्ण ऊंची जातियों के हर स्तर के भाजपा नेता व सीनियर कार्यकर्ता उनकी बातों का समर्थन करते मिल जाएंगे. ऐसी बात नहीं है कि ऐसा असंतोष केवल कुछ ऊंची जातियों में ही है, अतिपिछड़े सामाजिक समूहों में भी उपेक्षा की चर्चा हो रही है. भाजपा के प्रादेशिक पदाधिकारियों व कार्यसमिति के सदस्यों की सूची पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव की सहमति से नित्यानंद राय ने तय की है. इस सूची से असंतुष्ट लोग भी मानते हैं कि इसमें सभी प्रमुख और दबंग सामाजिक समूहों को शामिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन होशियारी के साथ. इस नेतृत्व में सूबे के विभिन्न सामाजिक समूहों में प्रभावशाली लोगों के बदले राजनीतिक तौर पर अपरिचित, नए और कमजोर लोगों को शामिल किया गया है. चुनाव के ठीक पहले की ऐसी कमिटी किस तरह भाजपा को अगली राजनीति के लिए सक्षम बनाएगी, यह पार्टी से जुड़े या इससे सहानुभूति रखने वालों के लिए भी चिंता की बात हो सकती है. बात इतनी भर नहीं है. इससे भी बड़ी चिंता दूसरी है. पार्टी के बड़े नेता औपचारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर वे भी मानते हैं कि धनबल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. नए लोगों को मौका देने के नाम पर धनबलियों को पार्टी में पद और प्रतिष्ठा मिल रही है. अन्य दलों की तरह भाजपा में भी धनबली को आम चुनावों के साथ-साथ राज्यसभा और विधान परिषद में उम्मीदवारी देने की प्रथा अघोषित तौर पर वर्षों से चली आ रही है. लेकिन अब संगठन में भी पद देकर उन्हें प्रतिष्ठित करने की परंपरा को विकसित किया जा रहा है. सुधीर शर्मा ने इस सिलसिले में देवनारायण मंडल, आनंद झा, विश्वमोहन चौधरी जैसे कुछ नाम गिनाए हैं. पदाधिकारियों की सूची में ऐसे कई नाम हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक वक़त कुछ खास नहीं है. भाजपा के नए समर्थक सामाजिक समूहों की यह स्थिति है, तो इसके पारंपरिक समर्थक वैश्य समुदाय नाराज न भी हों, संतुष्ट तो कतई नहीं हैं. लालबाबू प्रसाद को पार्टी से निकाले जाने से यह समुदाय उत्तेजित है. वैश्य समुदाय का मानना है कि लालबाबू प्रसाद पर कार्रवाई के पहले पार्टी नेतृत्व को मामले की तहकीकात करनी चाहिए थी. जब किसी ने एनडीए की एमएलसी के साथ दुर्व्यवहार की कोई शिकायत ही नहीं की, तो सजा किस अपराध की? भाजपा से जुड़े वैश्य समुदाय का मानना है कि पार्टी के मौजूदा नेतृत्व ने अपनी छवि चमकाने के लिए लालबाबू को बलि का बकरा बनाया है. इसीलिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय पर तानाशाही का आरोप लगा और उनका पुतला फूंका गया.

वस्तुतः अनुकूल राजनीतिक माहौल के बावजूद सूबे में भाजपा संकट के दौर में फंसती दिख रही है. संकट का एक छोर नए सामाजिक समूहों में अपनी नई-नई पैठ को मजबूत आधार देने का है, तो दूसरा सिरा स्थापित नेतृत्व को संग रखते हुए उसके अनुभव से लाभ हासिल करते जाने का. बिहार भाजपा के मौजूदा संकट के ये दोनों छोर बड़े ही महत्वपूर्ण बन गए हैं. सूबे की राजनीति में अपनी बढ़त बनाने में दोनों के बीच गंभीर तालमेल की दरकार है. ऐसा करके ही राजनीतिक सक्रियता को सार्थक दिशा दी जा सकती है. ये कैसे होगा, इस बारे में पटना से लेकर दिल्ली तक को सोचना होगा. वास्तविकता तो यह है कि पार्टी-नेतृत्व के बदले चेहरों से इसके पुराने कहावर नेताओं के कुछ समर्थक संतुष्ट हैं, तो कुछ अन्य कहावर नेताओं के समर्थक घोर असंतुष्ट. वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. अश्विनी कुमार चौबे व डॉ. प्रेम कुमार के लोग इस नेतृत्व से संतुष्ट हैं. वे मानते हैं कि पदाधिकारियों के समूह ही नहीं, मोर्चों व प्रकोष्ठों में भी उन्हें अनुकूल भागीदारी मिली है और अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाने का उन्हें अवसर मिलेगा. नंदकिशोर यादव के समर्थक खुद को न हर्ष न विषाद की स्थिति में पा रहे हैं. हालांकि नंदकिशोर यादव के कुछ खास लोगों, जो अपने सामाजिक समूहों और भौगोलिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, को दरकिनार कर दिया गया और वे भी उत्तेजित जैसी स्थिति में ही हैं. लेकिन वे इसे राजनीति का एक विषम दौर मानकर स्वीकार कर रहे हैं. वे ये सोचकर खामोश हैं कि ये दौर भी गुजर जाएगा. लेकिन सबसे अधिक आहत और उत्तेजित बिहार में भाजपा के सबसे कहावर नेता सुशील कुमार मोदी के समर्थक हैं. ऐसा होना लाजिमी भी है. सुशील कुमार मोदी पिछले दो दशक से बिहार में पार्टी के सबसे प्रतिभावान व प्रभावशाली चेहरा रहे हैं और उनके खाते में ऐसी कई उपलब्धियां हैं, जिनसे भाजपा लाभ की स्थिति में रही है. उनकी राजनीति के कारण नए सामाजिक क्षेत्रों में भाजपा का विस्तार हुआ है और इसीलिए नेताओं-कार्यकर्त्ताओं को प्रतिष्ठित करने में उनकी रुचि-अरुचि ने पिछले डेढ़-दो दशकों में बड़ी भूमिका निभाई है. अब वे दरकिनार हो रहे हैं, तो इनका आहत और उत्तेजित होना भी स्वाभाविक है. ये विस्थापन का दर्द है. सुधीर कुमार शर्मा हों या सुनील कुमार पिंटू या लालबाबू प्रसाद, सभी सुशील कुमार मोदी के खास रहे हैं. ये सब मोदी के आभामंडल के जगमगाते सितारे रहे हैं. अब ये सभी पार्टी के मसले को लेकर सड़क पर आ गए हैं. ऐसे में कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म हो रहा है. निःसंदेह सुशील कुमार मोदी भाजपा के कुछ अति निष्ठावान लोगों में हैं और इसीलिए यह मानना गलत होगा कि इन उत्तेजित लोगों के आचरण को उनकी सहमति हासिल होगी. लेकिन इस फ्रंट पर उनकी खामोशी कुछ सवाल तो पैदा करती ही है. उन्होंने अपने आभामंडल के इन सितारों के ऐसे आचरण की निंदा भी तो नहीं की!

लाल बाबू प्रसाद | सुधीर कुमार शर्मा | सुनील कुमार पिंटू | सुशील मोदी

बिहार को छोड़ कर पूरी हिन्दी पट्टी पर पार्टी कब्जा कर चुकी है. ऐसे में यहां दल की एकजुटता सबसे अधिक जरूरी है. लेकिन हाल के घटनाचक्र विपरीत संदेश दे रहे हैं. यह तो नहीं कहा जा सकता है कि बगावत पार्टी के द्वार पर आ गई है. लेकिन राज्य इकाई में असंतोष के व्रण तो फूटने ही लगे हैं. भाजपा नेतृत्व के लिए इससे भी बड़ी चिंता है कि ये असंतोष पार्टी की ओर मुखातिब नए सामाजिक समूहों में फैल रहा है. प्रादेशिक नेतृत्व के साथ-साथ केन्द्रीय नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है. लेकिन अभी तो बिहार में मौसम अगलगी का है, देखना है भाजपा के भाग्यविधाता इस पर कैसे और कितना पानी डालते हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी राजनीतिक व्यस्तता थी. उसकी उत्कृष्ट सफलता के बाद वह अब 2019 के संसदीय चुनाव की तैयारी में जुट गया है. पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसका कमान संभाल चुके हैं. केन्द्रीय मंत्रियों, सासंदों और प्रांतीय नेतृत्व को टास्क दिए जा रहे हैं. पार्टी को गांव ही नहीं, घर-घर तक पहुंचाने और इसकी आम स्वीकार्यता के स्तर को बढ़ाने के हर उपाय किए जा रहे हैं. नए सामाजिक समूहों, विशेषकर दलित, अतिपिछड़ा व अन्य वंचित समूहों में पार्टी की दीर्घकालिक पैठ बनाने के ख्याल से नए-नए कार्यक्रम लाए जा रहे हैं. केन्द्र सरकार की उपलब्धियों व गरीबों को राहत देने की उसकी योजना व कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति तैयार की जा रही है. ये सब कुछ बिहार में भी होना है. बिहार को छोड़ कर पूरी हिन्दी पट्टी पर पार्टी कब्जा कर चुकी है. ऐसे में यहां दल की एकजुटता सबसे अधिक जरूरी है. लेकिन हाल के घटनाचक्र विपरीत संदेश दे रहे हैं. यह तो नहीं कहा जा सकता है कि बगावत पार्टी के द्वार पर आ गई है. लेकिन राज्य इकाई में असंतोष के व्रण तो फूटने ही लगे हैं. भाजपा नेतृत्व के लिए इससे भी बड़ी चिंता है कि ये असंतोष पार्टी की ओर मुखातिब नए सामाजिक समूहों में फैल रहा है. प्रादेशिक नेतृत्व के साथ-साथ केन्द्रीय नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है. लेकिन अभी तो बिहार में मौसम अगलगी का है, देखना है कि भाजपा के भाग्यविधाता इस पर कैसे और कितना पानी डालते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

मोतिहारी शुगर मिल-मज़दूरों ने किया आत्मदाह-एक की मौत

वेतन के बदले मिली लाठी, गोली और मौत

महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. महात्मा गांधी 10 अप्रैल को पहली बार बिहार आए थे और 15 अप्रैल को चम्पारण के मोतिहारी स्टेशन पर उतरे थे. चम्पारण के किसानों की बदहाली देखकर उन्होंने अंग्रेज नीलही कोठियों के अत्याचार के विरूद्ध सत्याग्रह का आगाज किया था. किसानों-मजदूरों को अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया चम्पारण सत्याग्रह, आजादी की लड़ाई का प्रथम सोपान बना और 30 वर्षों बाद देश आजाद हुआ. कहने को तो आजादी मिल गई पर आज भी किसान-मजदूरों पर अत्याचार बदस्तूर जारी है, केवल स्वरूप बदल गया है.

गांधी के सत्याग्रह की भूमि हुई रक्तरंजित

केन्द्रीय कृषी मंत्री के संसदीय क्षेत्र की घटना

राकेश कुमार

देश भर में बदहाल किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. सरकार और राजनेता किसानों की स्थिति को सुधारने के बजाय उनकी मौत पर राजनीति कर रहे हैं. बापू के सत्याग्रह की धरती चम्पारण पर भी किसान-मजदूर एड़ियां रगड़-रगड़ कर जीने की जद्दोजहद में लगे हैं. अत्याचार अब भी हो रहा है, फर्क इतना है कि अग्रेजों की जगह कतिपय पुलिस प्रशासन, उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों ने ले ली है. 10 अप्रैल को मोतिहारी के हनुमान सुगर मिल के दो मजदूर किसानों द्वारा किया गया आत्मदाह भी इसी गठजोड़ का नतीजा माना जा रहा है. 2002 से बन्द पड़ी चीनी मिल के किसान-मजदूर अपने बकाए के भुगतान और वेतन की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं. मिल के स्थायी मजदूरों को वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है. दो जून की रोटी को तरस रहे मजदूरों को मेहनताना के बदले पुलिस की लाठी-गोली दी जा रही है.

आत्मदाह की घटना कोई अप्रत्याशित नहीं थी. लम्बे समय से आंदोलन चल रहा था. सैकड़ों बार धरना-प्रदर्शन किया जा चुका है. किसान-मजदूर अपनी फरियाद के साथ डीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक से मिल चुके हैं. विगत वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चम्पारण दौरे के दौरान चीनी मिल गेट पर जाकर मजदूरों से मिले थे और समस्या को सुलझाने का आश्वासन भी दिया था. स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी हैं. उनसे भी मजदूरों ने कई बार अपनी फरियाद सुनाई. यहां तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा से नरेन्द्र मोदी ने भी घोषणा करते हुए कहा था कि चुनाव जीत कर अगली बार आऊंगा, तो इसी चीनी मिली की चीनी का चाय पिऊंगा. केन्द्र में भाजपा की सरकार भी बनी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. किसी ने राज्य का मामला, तो किसी ने प्राइवेट मिल होने का बहाना बनाकर इससे अपना पल्ला झाड़ लिया और मजदूरों को तिल-तिल मरने को छोड़ दिया. पूर्व में भी झूठे वादों से परेशान किसान मजदूरों ने आत्मदाह का ऐलान करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था. लेकिन जिला प्रशासन ने वार्ता कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिला कर मामले को शान्त करा दिया था. लेकिन उसके बाद कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया. मजदूरों का आंदोलन चलता रहा और इसकी परिणति दो मजदूरों की आत्मदाह के प्रयास की घटना से हुई. सबसे आश्चर्यजनक तो यह था कि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर-किसानों को खदेड़-खदेड़ कर मारा. पुलिस द्वारा खूब लाठियां चटकाई गईं. आंसू गैस के आठ गोले छोड़े गए और तीन राउण्ड गोलियां भी चलीं.

ज्ञात हो कि हनुमान सुगर मिल, बिड़ला के संबंधी विमल नोपानी का है, जो कोलकाता में रहते हैं. 1905 में स्थापित ये चीनी मिल उस समय चम्पारण का एकमात्र उद्योग था. 1990 तक बिड़ला द्वारा मिल को लीज पर चलाया गया. लीज समाप्त होने के बाद से ही मिल की स्थिति खराब होने लगी. बिमार हाल में चल रहा मिल 2002 से मिल प्रबंधन की उदासीनता के कारण बन्द हो गया तथा किसानों के गन्ना का सौ करोड़ से ज्यादा बकाया रह गया. उसके बाद मिल से सीजनल मजदूरों को हटा दिया गया. स्थायी मजदूरों का भी वेतन बन्द हो गया, परन्तु उन्हें मुक्त नहीं किया गया. एक भी दिन अनुपस्थित होने पर चेतावनी और काम से निकाल देने की धमकी दी जाती, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती. मजदूरी मद में 60 करोड़ मजदूरों का बकाया रह गया. इसी दौरान मिल प्रबंधन के कुछ चहेतों द्वारा मिल की सम्पति बेचने की साजिश रची गई. मजदूरों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. न्यायालय ने आदेश दिया कि मिल की बेची जाने वाली परिसम्पति कर 40 फीसदी राशि से मजदूरों, किसानों के बकाया का भुगतान कराया जाय. लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं कराया जा सका.

कई बार मजदूरों और प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, लेकिन उसपर अमल नहीं किया गया. ये मजदूर-किसान अपनी मांगों को लेकर 7 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. मजदूर संघ के अनुसार, आंदोलन की सूचना पुलिस-प्रशासन सहित अन्य जगहों पर दे दी गई थी. मजदूर संघ 2015 में प्रबंधन और सरकार के नुमाइंदों के साथ हुई वार्ता के निर्णयों को पूरा करने की मांग कर रहा था. इस बीच, धरना स्थल पर बैठे किसान-मजदूरों से मिलने पहुंचे एसडीओ से मजदूरों ने डीएम से मिलने का समय मांगा था. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार डीएम ने सोमवार को मिलने का समय दिया था. मजदूर जब धरना पर बैठे थे, उस समय वहां छतौनी पुलिस भी पहुंची हुई थी. आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेने और पुलिस की धमकी से मजदूरों का आक्रोश फूट पड़ा. पुलिस के समक्ष ही मजदूर नेता नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली. सभी मजदूर दौड़े और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब तक दोनों बुरी तरह आग में झुलस चुके थे. धटना को देख कर मजदूर-किसान उग हो गए. चीनी मिल के मुख्य मार्ग को आगजनी कर बन्द कर दिया गया और नारेबाजी होने लगी. आनन-फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन उसे भी उग्र लोगों ने रोक दिया. बाद में समझाने के बाद एम्बुलेंस को छोड़ा गया, फिर दोनो घायलों को अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में भर्ती सूरज बैठा ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने मांगों को लेकर आत्मदाह किया है. दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए, चिकित्सकों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया गया. इधर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच रोड़ेबाजी शुरू हो गई. बाद में बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और भीड़ को हटाने के लिए बल का प्रयोग करने लगी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 से 12 चक्र गोलियां दागी गईं. आंसू गैस के आठ गोले छोड़े गए. पुलिस ने महिलाओं सहित राहगीरों को भी खदेड़-खदेड़ कर पीटा. इस घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए. घायलों में, मजदूरों के समर्थन में पहुंचे नवयुवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत पाण्डेय, रामचंद्र सहनी, शर्मा ठाकुर, वार्ड पार्षद रमेश कुमार, हरेन्द्र सिंह, गौरव कुमार, मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हरकित बैठा, हरिहर सिंह, जालंधर महतो, चन्नी देवी, आशा देवी आदि शामिल है. वहीं प्रशासन की ओर से शामिल लोगों में अंचलाधिकारी चौधरी बसंत सिंह, छातौनी इंसपेक्टर विजय कुमार, दरोगा अमितेश कुमार, अंगरक्षक मनोज कुमार और सिपाही रंजन कुमार सहित आठ लोग शामिल हैं.

डीएम अनुपम कुमार का कहना है कि चीनी मिल मजदूरों ने आत्मदाह करने संबंधित कोई सूचना सीधे तौर पर नहीं दी थी. रविवार की रात, धरना पर बैठे लोगों की एसडीओ से वार्ता हुई थी. उनके प्रतिनिधिमंडल को सोमवार को दस बजे मिलने का समय दिया गया था. थाना प्रभारी उन्हें लेने गए थे. इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और इसी दौरान उन दोनों ने शरीर में आग लगा ली. भीड़ और शरारती तत्वों ने एम्बुलेंस को भी सही समय पर नहीं जाने दिया. चीनी मिल निजी है. इसके बावजूद मिल मालिकों पर बकाया भुगतान के लिए प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाया जाता रहा है. वहीं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र राणा के अनुसार उग्र भीड़ ने पुलिस पर पहले हमला किया. फिर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के आठ गोले दागे और तीन राउण्ड हवाई फायरिंग की. इसके बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया.

घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है. भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी मोतिहारी पहुंचकर घायलों से मिले और परिजनों से घटना की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि मजदूरों के आत्मदाह की घटना बहुत ही दुखद है और पूरी घटना प्रशासनिक अक्षमता के कारण घटी है. बिहार सरकार में प्रशासन नाम की कोई चीज बची ही नहीं है. उनके साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय भी थे. आम लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. कई संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए मजदूरों के आंदोलन को समर्थन दिया है. इसी बीच पटना के पीएमसीएच मे इलाज करा रहे मजदूर नेता नरेश श्रीवास्तव की मौत हो गई. वहीं सूरज बैठा की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

इधर, घटनाक्रम को प्रशासन ने अचानक यूटर्न दे दिया. जिलाधिकारी अनुपम कुमार और एसपी जितेन्द्र राणा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि मृतक नरेश श्रीवास्तव की पत्नी ने अपने दर्ज बयान में कहा है कि सभी धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे और वार्ता के लिये उन्हें डीएम के पास जाना था. छतौनी पुलिस भी पहुंच गई थी. इसी दौरान मिल मालिक विमल कुमार नोपानी और मैनेजर के द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्वों द्वारा नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा के शरीर में आग लगा दी गई. एसपी श्री राणा ने कहा कि विमल कुमार नोपानी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

आरोप-प्रत्यारोप

"इस पूरी घटना की जिम्मेवारी कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की है. किसान-मजदूरों ने कई बार श्री सिंह से गुहार लगाई थी कि मिल को चालू कराया जाय और बकाये का भूगतान किया जाय. लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की. सुगौली मिल को जिस तरह एचपीसीएल को देकर चालू कराया गया, वैसे ही मोतिहारी चीनी मिल को भी चालू कराया जा सकता था. माननीय प्रधानमंत्री ने भी मोतिहारी में चुनावी सभा के दौरान चीनी मिल को चालू कराने और इसी के चीनी की चाय पीने की बात की थी. कृषि मंत्री की दिलचस्पी मिल चालू कराने के बजाय इसकी जमीन में है. ऐसे कृषि मंत्री को अविलम्ब हटाया जाय, जिसके संसदीय क्षेत्र में किसान मजदूर आत्मदाह करने को विवश हैं."

- राजद नेता और मोतीहारी से लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव

"मोतिहारी चीनी मिल मजदूरों द्वारा की गई आत्मदाह की कोशिश और एक की मौत राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है. यह अधिकार राज्य सरकार को है कि वो मिल प्रबंधन के विरूद्ध कठोर कदम उठाए, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया. यह घटना इसी का नतीजा है. सेंन्ट्रल केन कन्ट्रोल एक्ट के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि ऐसी स्थिति में वह हस्तक्षेप कर किसान मजदूर का बकाया भुगतान करा सकती है. राज्य सरकार मिल मालिक पर केस करे, गिरफ्तार करे और तब भी भुगतान न हो, तो मिल का अधिग्रहण कर किसानों और मजदूरों के हित में काम करे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया."

- राधामोहन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री और मोतीहारी से भाजपा सांसद

मजदूरों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सका तो समझूंगा भाग्यशाली

चीनी मिल को चालू कराकर सैकड़ों मजदूरों को रोजी-रोटी दिलाने के संकल्प को पूरा कराने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते अलविदा कह गया मजदूरों का चहेता नरेश श्रीवास्तव. दो दशकों से ज्यादा समय से नरेश मजदूरों-किसानों के हक की लड़ाई लड़ता आ रहा था. नरेश श्रीवास्तव को कोई संतान नहीं थी. आंदोलन के दौरान बार-बार मिलने के बाद नरेश को नजदीक से जानने का मौका मिला. नरेश ने एक बार बताया था कि मिल बन्द होने के बाद ही निश्चय कर लिया कि हमें बच्चा नहीं चाहिए. मिल के सैकड़ों मजदूरों के बच्चों की खुशियां लौटा सका, तो अपने को भाग्यवान समझूंगा. सभी बच्चे तो मेरे ही हैं. पत्नी को भी समझा दिया हूं.

जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण

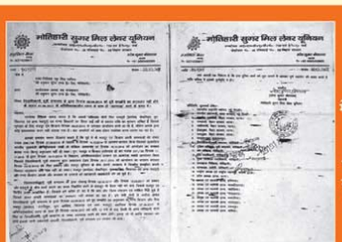

लेवर यूनियन ने पहले ही जिलाधिकारी अनुपम कुमार को मेमोरेंडम देकर सूचित कर दिया था कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 9 अप्रैल के बाद वे कभी भी आत्मदाह कर सकते हैं.

बच्चों में निमोनिया

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr. S.K. Mishra (MBBS,MD.)
Mira Takiz Road, SAHARSA

सहरसा के कुशल चिकित्सक डॉ. एस.के मिश्रा ने बातचीत के दौरान बताया कि नवजात बच्चों की देखभाल बहुत जरूरी हैं वे देश के भविष्य हैं। खास कर ठंढ के मौसम में बच्चों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान दें गर्म कपड़े, गर्म कमरा का भी ख्याल रखें। उन्होंने निमोनिया के बारे में बताते हुए कहा कि निमोनिया...जिसे हम आमतौर पर मामूली बीमारी ही समझते आए हैं वो अब घातक रूप ले चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर घंटे निमोनिया से 45 बच्चों की मौत होती है। यानी करीब हर मिनट हमारे देश में एक बच्चा निमोनिया की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए निमोनिया को मामूली बीमारी समझने की भूल न करें। 45 फीसदी बच्चों में पोषण की कमी है। उन्हें निमोनिया का बैक्टीरिया जल्दी अपने शिकंजे में ले सकता है। निमोनिया की वैक्सीन होने के बावजूद भारत में वैक्सिनेशन की दर महज 50 फीसदी है। यानी देश के आधे बच्चों को वैक्सीन दी ही नहीं जाती। किसी एक बीमारी से हमारे देश में इतनी मौतें नहीं होतीं जितनी निमोनिया से होती हैं। निमोनिया केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। निमोनिया एक प्रकार का संक्रमण है। हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। डॉक्टर के परामर्श से एंटीबायोटिक दवा लेने पर बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। लक्षण और इलाज -सर्दी, हाई फीवर, कफ, कंपकपी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द निमोनिया के लक्षण हैं। छोटे या नवजात बच्चों में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देता है। बच्चे देखने से बीमार लगें तो उन्हें निमोनिया हो सकता है। डॉक्टर के परामर्श के बाद ही एंटीबायोटिक दवाएं लेकर निमोनिया को खत्म किया जा सकता है। निमोनिया के मरीज को सादा खाना खाना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। मरीज को मसालेदार और बाहर के खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। परामर्श के बाद मार्केट से एचआईबी एवं न्यूमोनोकस नामक वैक्सिन बाजार में उपलब्ध हैं उसे ले सकते हैं।■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

भाजपा का अम्बेडकर-प्रेम दलित-वोट साधने का एजेंडा

दलित-हित से अधिक सियासी-हित

एसआर दारापुरी

उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद भातीय जनता पार्टी (भाजपा) को यह अहसास हुआ है कि इस चुनाव में उसे सबसे अधिक आरक्षित सीटें मिली हैं, क्योंकि दलितों का एक बड़ा हिस्सा उसकी तरफ आ गया है. इस सफलता में उस द्वारा पिछले कुछ वर्षों से अम्बेडकर के प्रति दिखाए गए प्रेम का भी काफी बड़ा हाथ है. दलितों को आकर्षित करने के लिए उसने दलित नेताओं को भाजपा में शामिल करने के साथ-साथ अम्बेडकर को भी अपने छाते में लाने के गंभीर प्रयास किए. एक तरफ उसने इंग्लैंड में डॉ. अम्बेडकर के पढ़ाई के दौरान रहने वाले मकान को खरीद कर स्मारक का रूप दिया, दूसरी तरफ बम्बई में उनके रहने के स्थान पर एक भव्य स्मारक बनाने हेतु भूमि का अधिग्रहण भी किया है. पिछले साल मोदीजी ने दिल्ली में बाबासाहेब के निवास स्थान पर एक भव्य स्मारक बनाने का शिलान्यास भी किया था.

14 अप्रैल को भाजपा ने बहुत बड़े स्तर पर अम्बेडकर जयंती मना कर भी यही प्रयास प्रदर्शित किया. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा शुरू से ही जाति-विरोधी नजरिया रखते रहे हैं और अंतरजातीय सहभोज उसका एक पहलू रहा है. संघ विचारधारा के स्तर पर जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ रहा है, यद्यपि वह जाति के उच्छेदन की वकालत नहीं करता, है परन्तु जाति के मुद्दे पर वह रोटी-बेटी के सम्बन्ध द्वारा इसे व्याख्यायित करता रहा है. इसके अलावा वह तथा उसके आनुषांगिक संगठन अधिक से अधिक लोगों को अपने में शामिल करने के लिए एक मंदिर, एक शमशान घाट और एक कुआं की वकालत करते रहे हैं. इसके पीछे उनकी मंशा अपने संगठन में भोजन, पूजा स्थल और पानी के श्रोत सम्बन्धी भेदभाव को समाप्त करना रहा है.

संघ और भाजपा द्वारा अधिक से अधिक दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या डॉ. अम्बेडकर को हथियाने के लिए जो आयोजन किए जा रहे हैं, क्या उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह वास्तव में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना के पक्षधर बन गए हैं? इसके साथ ही क्या यह कहा जा सकता है कि संघ या भाजपा (पूर्व जनसंघ) जिसने डॉ. अम्बेडकर का उनके जीते जी इतना कड़ा विरोध किया था कि हृदय परिवर्तन हो गया है और उन्होंने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही वे डॉ. अम्बेडकर के हिन्दू राष्ट्र के प्रबल समर्थक और कट्टर मुस्लिम विरोधी होने की बात को भी जोर शोर से प्रचारित करते रहे हैं. अतः इस विषय का गहन विश्लेषण करने की ज़रूरत है.

अपने प्रसिद्ध लेख राज्य और क्रांति में लेनिन ने कहा है, मार्क्स की शिक्षा के साथ आज वही हो रहा है, जो उत्पीड़ित वर्गों के मुक्ति-संघर्ष में उनके नेताओं और क्रान्तिकारी विचारकों की शिक्षाओं के साथ इतिहास में अक्सर हुआ है. उत्पीड़क वर्गों ने महान क्रांतिकारियों को उनके जीवन भर लगातार यातनाएं दीं, उनकी शिक्षा का अधिक से अधिक बर्बर द्वेष, अधिक से अधिक क्रोधोन्मत्त घृणा तथा झूठ बोलने और बदनाम करने की, अधिक से अधिक अंधाधुंध मुहिम द्वारा स्वागत किया. लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी क्रान्तिकारी शिक्षा को सारहीन करके, उसकी क्रान्तिकारी धार को कुंद करके, उसे भ्रष्ट करके उत्पीड़ित वर्गों को बहलाने तथा धोखा देने के लिए उन्हें अहानिकर देव-प्रतिमाओं का रूप देने, या यूं कहें, उन्हें देवत्व प्रदान करने और उनके नामों को निश्चित गौरव प्रदान करने के प्रयत्न किए जाते हैं. क्या आज अम्बेडकर के साथ भी यही नहीं किया जा रहा है?

पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल के शिलान्यास के अवसर पर डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के कृत्यों की प्रशंसा करते हुए अपने आप को अम्बेडकर भक्त घोषित किया था. उनकी यह घोषणा भाजपा की हिंदुत्व की भक्ति के अनुरूप ही है, क्योंकि भक्ति में आराध्य का केवल गुणगान करके काम चल जाता है और उस की शिक्षाओं पर आचरण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. तब मोदी जी ने भी डॉ. अम्बेडकर का केवल गुणगान किया था. यह गुणगान भी लेनिन की उपर्युक्त उक्ति वाली रणनीति के अंतर्गत किया जा रहा है. कौन नहीं जानता कि भाजपा की हिन्दुत्ववादी विचारधारा और अम्बेडकर की समतावादी विचारधारा में छत्तीस का आंकड़ा है.

अपने भाषण में मोदी जी ने कहा था कि डॉ. अम्बेडकर ने जाति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, परन्तु कौन नहीं जानता कि भाजपा का जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या नजरिया है. डॉ. अम्बेडकर ने तो कहा था कि जातिविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, परन्तु भाजपा और उसकी जननी संघ तो समरसता (यथास्थिति) के नाम पर जाति और वर्ण की संरक्षक है. मोदी ने अपने भाषण में बाबा साहेब की मजदूर वर्ग के संरक्षण के लिए श्रम कानून बनाने के लिए प्रशंसा की थी. परन्तु मोदी मेक-इन-इंडिया के नाम पर सारे श्रम कानूनों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं. जिन-जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर श्रम कानून समाप्त कर दिए गए हैं. पूरे देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नियमित मजदूरों की जगह ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई है, जिससे मजदूरों का भयंकर शोषण हो रहा है. बाबा साहेब तो मजदूरों की राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी के प्रबल पक्षधर थे. यह भी सर्वविदित है कि वर्तमान में मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी सूत्र दिया था. बाबा साहेब समान, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा के पैरोकार थे. इसके विपरीत वर्तमान सरकार शिक्षा के निजीकरण की पक्षधर है और शिक्षा के लिए बजट में निरंतर कटौती करके गुणवत्ता वाली शिक्षा को आम लोगों की पहुंच से बाहर कर रही है.

जितने भी कानून हैं वे अधिकतर डॉ. अम्बेडकर द्वारा ही बनाए गए थे जिन्हें वर्तमान सरकार एक एक करके समाप्त कर रही है या कमज़ोर बना रही है.

बाबा साहेब के बहुचर्चित शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो के नारे को बिगाड़ कर शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो के रूप में प्रस्तुत करते हुए मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहेब शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और उन्होंने शिक्षित होकर संगठित होने के लिए कहा था ताकि संघर्ष की ज़रूरत ही न पड़े. इस में भी मोदी जी का समरसता का फार्मूला ही दिखाई देता है जबकि बाबा साहेब ने तो शिक्षित हो कर संघर्ष के माध्यम से संगठित होने का

दलितों का सपना पूरा करने में फेल रहीं मायावती

इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 69 सीटें जीत ली. दलितों की नेता बनने वाली मायावती को सिर्फ दो सीटें मिलीं. मोदी ने दलित वोट के अब तक के सारे मिथक तोड़ दिए. हालांकि लोकसभा चुनाव में ही मोदी ने इस मिथक को धराशाई कर दिया था. कांशीराम ने 1984 में बसपा बनाई थी, जो 1993 में सत्ता में आ गई थी. लेकिन इतनी जल्दी पार्टी समाप्त भी हो गई. मायावती से गैर जाटव दलितों का व्यापक मोहभंग हो गया. दलितों का सपना पूरा करने में मायावती पूरी तरह फेल हो गईं. लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने सभी 17 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी. बसपा ने इन्हीं 17 सीटों पर दलितों को टिकट दिए थे, वे सभी चुनाव हार गए थे.

अपने भाषण में आरक्षण को खरोंच भी न आने देने की बात पर मोदी जी ने बहुत बल दिया था. परन्तु उन्होंने वर्तमान में आरक्षण पर सबसे बड़े संकट पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी संविधान संशोधन का कोई उल्लेख नहीं किया. इसके साथ ही दलितों की निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग को बिलकुल नज़रंदाज़ कर दिया जाता रहा है. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि निजीकरण के कारण आरक्षण के निरंतर घट रहे दायरे के परिप्रेक्ष्य में दलितों को रोज़गार कैसे मिलेगा. इसके अतिरिक्त संघ के अलग-अलग पदाधिकारी आरक्षण की समीक्षा तथा इसका आर्थिक आधार बनाए जाने की मांग करते रहे हैं.

मोदी जी ने इस बात को भी बहुत जोर-शोर से कहा कि डॉ. अम्बेडकर औद्योगीकरण के पक्षधर थे, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि वे निजी या सरकारी किस औद्योगीकरण के पक्षधर थे. यह बात भी सही है कि भारत के औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण में जितना योगदान डॉ. अम्बेडकर का है उतना शायद ही किसी और का हो. उन्होंने यह महान कार्य 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी समिति के श्रम सदस्य के रूप में किया था परन्तु इसके लिए उन्हें कोई भी श्रेय नहीं दिया गया. डॉ. अम्बेडकर ने ही उद्योगों के लिए सस्ती बिजली, बाढ़ नियंत्रण और कृषि सिचाई के लिए ओडीशा में दामोदर घाटी परियोजना बनाई थी. बाद में इसके अनुसरण में ही देश में बहुउद्देशीय हाइड्रो-इलेकिट्रक प्रोजेक्ट्स बने थे. इसके लिए उन्होंने ही सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन तथा सेंट्रल वाटरवेज़ एंड नेवीगेशन कमीशन की स्थापना की थी. हमारा वर्तमान पावर सप्लाई सिस्टम भी उनकी ही देन है.

यह सर्वविदित है कि बाबासाहेब राजकीय समाजवाद के प्रबल समर्थक थे जबकि मोदी जी निजी क्षेत्र और न्यूनतम गवर्नेंस के सबसे बड़े पैरोकार हैं. बाबासाहेब पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को दलितों के सबसे बड़े दुश्मन मानते थे. मोदी जी का निजीकरण और भूमंडलीकरण बाबासाहेब की समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा के बिलकुल विपरीत है. मोदी जी ने डॉ. अम्बेडकर की एक प्रख्यात अर्थशास्त्री के रूप में जो प्रशंसा की थी वह ठीक है. परन्तु बाबासाहेब का आर्थिक चिंतन समाजवादी और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का था जिसके लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उन्हें अपने अर्थशास्त्र का पितामह कहा है. इसके विपरीत मोदी जी का आर्थिक चिंतन और नीतियां पूंजीवादी और कारपोरेट परस्त है.

मोदी जी ने डॉ. अम्बेडकर का लंदन वाला घर खरीदने, बम्बई में स्मारक बनाने और दिल्ली में अम्बेडकर स्मारक बनाने का श्रेय भी अपनी पार्टी को दिया था. वैसे तो मायावती ने भी दलितों के लिए कुछ ठोस न करके केवल स्मारकों और प्रतीकों की राजनीति से ही काम चलाया है. भाजपा की स्मारकों की राजनीति उसी राजनीति की पूरक है. शायद मोदी जी यह जानते होंगे कि बाबा साहेब तो खुद को बुत पूजक नहीं, बुत तोड़क कहते थे और वे व्यक्ति पूजा के घोर विरोधी थे. बाबा साहेब पुस्तकालयों, विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना के पक्षधर थे. वे राजनीति में किसी व्यक्ति की भक्ति के घोर विरोधी थे और इसे सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी गिरावट मानते थे. परन्तु भाजपा में मोदी जी को एक ईश्वरीय देन मान कर पूजा जा रहा है.

अपने भाषण में मोदी जी ने दलित उद्यमिओं को प्रोत्साहन देने का श्रेय भी लिया था. मोदी जी जानते होंगे कि कुछ दलितों के पूंजीपति या उद्योगपति बन जाने से इतनी बड़ी दलित जनसंख्या का कोई कल्याण होने वाला नहीं है. दलितों के अंदर कुछ उद्यमी तो पहले से ही रहे हैं. दलितों का कल्याण तो तभी होगा जब सरकारी नीतियां जनपक्षीय होंगी न कि कारपोरेट परस्त. दलितों की बहुसंख्य आबादी भूमिहीन तथा रोज़गारहीन है जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है. दलितों के सशक्तिकरण के लिए भूमि-आवंटन और रोज़गार गारंटी ज़रूरी है, जो मोदी सरकार के एजेंडे में नहीं है. अपने भाषण में मोदी जी द्वारा डॉ. अम्बेडकर का किया गया गुणगान उन्हें केवल राजनीति के लिए हथियाने का प्रयास मात्र है. सच यह है कि भाजपा और उसकी मार्ग दर्शक संघ की नीतियां तथा विचारधारा डॉ. अम्बेडकर की समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक विचारधारा के बिलकुल विपरीत है. वास्तविकता यह है कि भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां भी डॉ. अम्बेडकर को हथिया कर दलित वोट प्राप्त करने की दौड़ में लगी हुई हैं जबकि किसी भी पार्टी का दलित उत्थान का एजेंडा नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपी की नौकरशाही में भाजपाई फेरबदल शुरू, पर ईमानदारी को प्राथमिकता

तंत्र पर चलेगा योगी-मंत्र

योगी की सरकार अखिलेश जमाने के शीर्ष नौकरशाहों के साथ आगे तो बढ़ी, लेकिन किसी को माथे नहीं चढ़ने दिया. मुख्य सचिव राहुल भटनागर को नहीं छुआ गया. अपर मुख्य सचिव सदाकांत की प्रमुखता बनी रही और प्रमुख सचिव नवनीत सहगल सत्ता गलियारे में प्रमुख बने रहे. लेकिन अभी हाल ही सहगल के सभी दायित्व अवनीश अवस्थी को दे दिए गए और सहगल किनारे कर दिए गए. गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पंडा, पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद, कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक दलजीत चौधरी समेत कई अधिकारी अभी अपने पद पर काम कर रहे हैं, इनके भी स्थानांतरण की तैयारी है.

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए. योगी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य काम में लग गए और जनहित के फैसले धड़ाधड़ होने लगे. लेकिन सत्ता गलियारे में यह बात भी गूंजती रही कि योगी सरकार सब कुछ नया करना चाहती है, लेकिन सरकार का तंत्र तो वही पुराना घिसा-पिटा है, जिसके बूते मायावती और अखिलेश की सरकार घिसटती रही. मायावती सरकार का पत्थरनामा बोलता रहा तो अखिलेश सरकार का कारनामा बोलता रहा. इसमें प्रदेश के नौकरशाहों को भी पूरा श्रेय जाता है, जिनकी वजह से बसपा और सपा की गिल्लियां बिखर गईं. बसपा सरकार जिन नौकरशाहों को लेकर शासन करती रही, कमोबेश उन्हीं नौकरशाहों के बूते अखिलेश ने भी शासन किया. इसीलिए दोनों सरकारों का कार्य-चरित्र लगभग एक जैसा ही रहा. योगी सरकार ने लीक से हट कर काम शुरू किया, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि पुराने तंत्र से योगी नया काम कैसे कर दिखाएंगे. लेकिन संत मुख्यमंत्री खुर्राट राजनीतिक की तरह अपने पैंतरे बदल रहा है. योगी धीरे-धीरे अपना मनचाहा शासनिक नक्शा खींचते दिख रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अपने कदम बढ़ा रहे हैं. योगी की सरकार अखिलेश जमाने के शीर्ष नौकरशाहों के साथ आगे तो बढ़ी, लेकिन किसी को माथे नहीं चढ़ने दिया. मुख्य सचिव राहुल भटनागर को नहीं छुआ गया. अपर मुख्य सचिव सदाकांत की प्रमुखता बनी रही और प्रमुख सचिव नवनीत सहगल सत्ता गलियारे में प्रमुख बने रहे. इसी तरह गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पंडा समेत प्रमुख सचिव चंचल तिवारी, प्रमुख सचिव संजीव सरन, प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला जैसे कई अफसर पहले की ही तरह योगी सरकार में भी काम कर रहे हैं. पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद भी काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) दलजीत चौधरी भी अपने पद पर यथावत बने हुए हैं. योगी सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री के पंचम तल वाले अधिकारी जरूर बदले गए, लेकिन बाकी वैसे ही बने रहे. केवल रिज्जियान सैम्फिल ही अकेले ऐसे अधिकारी हैं, जो पंचम तल पर योगी की सहमति से बने रहे. योगी की चुप्पी के कारण सत्ता गलियारे में कभी अवनीश अवस्थी के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बनने की चर्चा उड़ती रही तो कभी देवेश चतुर्वेदी की. कभी सदाकांत मुख्य सचिव बनने की चर्चा में शामिल हो जाते हैं तो कभी केंद्र से किसी वरिष्ठ अफसर के इस पद पर भेजे जाने की चर्चा होती है. कभी महाभ्रष्ट यादव सिंह प्रकरण से जुड़े नौकरशाह रमा रमण के नपने की खबर ने तेजी पकड़ी, तो कभी विवादों के बावजूद सत्ता गलियारे में बने रहने वाले नौकरशाह नवनीत सहगल को ठिकाने लगाने की चर्चा गर्म रही. मुख्य सचिव राहुल भटनागर और डीजीपी जावीद अहमद को लेकर भी तमाम कयास लगातार लगाए जा रहे हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने भटनागर और अहमद को हटाने की चुनाव आयोग से मांग की थी. लेकिन सत्ता में आने के बाद यह मांग ठंडी पड़ गई. भाजपा के साथ अपने समीकरण प्रगाढ़ करने में पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल और वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल भी लगे हुए हैं. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल के भाई अनिल अग्रवाल गुजरात काडर में आईपीएस अफसर हैं, तो वे भी अपने भाई के लिए गुजरात-लाइन ठीक कर रहे हैं. ऊर्जा महकमे पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संजय अग्रवाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को थाम रखा है. संजय अग्रवाल ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव होने के साथ-साथ ऊर्जा महकमे के सभी नौ निगमों के अध्यक्ष भी बने बैठे हैं. दूसरी तरफ, प्रतिनियुक्ति पर गए कई अफसर भी अब वापस लौटने की जुगाड़ में हैं. बसपा और सपा सरकार में कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे. 1981 बैच के राजीव कुमार (प्रथम), 1982 बैच के जेएस दीपक, नीरज गुप्ता, प्रभाष झा, 1984 बैच के दुर्गा शंकर मिश्रा, 1986 बैच के प्रभात कुमार सारंगी, 1987 बैच के अरुण सिंघल, जीवेश नन्दन, 1988 बैच के आलोक कुमार (प्रथम), 1989 बैच के शशि प्रकाश गोयल समेत कई अधिकारियों की यूपी वापसी की चर्चा नौकरशाही गलियारे में तेज है. सपा सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खास नौकरशाहों में आमोद कुमार, पार्थसारथी सेन शर्मा, पंधारी यादव, अमित गुप्ता, जीएस नवीन कुमार, अरविंद सिंह देव, अरविंद कुमार, राजीव कुमार (द्वितीय), रमारमण, प्रांजल यादव, कामरान रिजवी और संजय अग्रवाल वगैरह शामिल रहे हैं. इनमें से भी कई अधिकारी योगी की 'गुड-बुक' में आने के लिए बेचैन हैं. बसपा और सपा के कार्यकाल में सत्ता का फल आपस में बांटने वाले नौकरशाह बाकायदा पहचाने जाते हैं. मायावती की सरकार में उनकी जाति के फतेह बहादुर के साथ-साथ नवनीत सहगल, अनिल सागर, कुमार कमलेश, दिनेश चंद्र, एसएम बोबड़े, सुधीर गर्ग, नेतराम और डीएस मिश्रा जैसे अधिकारियों की तूती बोलती थी. उन्हीं अधिकारियों में से कुछ की अखिलेश सरकार में भी तूती बोलती रही. अब वे योगी सरकार में भी अपनी तूती फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं. कुमार कमलेश को योगी सरकार ने भी नगर विकास के साथ-साथ कई नए दायित्व सौंपे हैं.

योगी ने नौकरशाही में फेरबदल की शुरुआत आजम खान के चहेते नगर विकास सचिव एसपी सिंह को हटा कर की. एसपी सिंह का सपा सरकार में खूब बोलबाला था. सचिव रहते हुए उनके ऊपर कोई प्रमुख सचिव नहीं हो पाया. रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पद पर बनाए रखा गया था. प्रदेश में वि भिन्न विभागों में तैनातकरीब 80 अधिकारी ऐसे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पाकर अपने पद पर जमे हैं. अब उनकी विदाई का 'काउंट-डाउन' शुरू हो गया है. एसपी सिंह के बाद तीन अफसर और स्थानांतरित हुए. भवानी सिंह खंगारौत, राम केवल और कुमार कमलेश. भवानी सिंह को मनरेगा का अपर आयुक्त बनाया गया, राम केवल को महिला कल्याण का निदेशक और कुमार कमलेश को नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलम कार्यक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.

इसके बाद पिछले दिनों मुख्यमंत्री के आदेश पर जब 20 आला नौकरशाहों के तबादले की सूची जारी हुई, तो उसने कई आला अफसरों के मंसूबे पर पानी फेर दिया. अखिलेश सरकार में ताकतवर रहे और योगी के आने पर भी सत्ता शीर्ष पर सक्रिय दिख रहे नवनीत सहगल, दिंपल वर्मा और अनीता सिंह जैसे अधिकारियों को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया गया. योगी ने यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को केंद्र की प्रतिनियुक्ति से बुला कर मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख सचिव तैनात कर दिया और नवनीत सहगल के सभी दायित्व अवस्थी को सौंप दिए. यानि, अवस्थी सूचना विभाग के भी प्रमुख सचिव होंगे और धर्मार्थ कार्य व अन्य उन विभागों का भी दायित्व संभालेंगे जो सहगल देखते थे. आबकारी विभाग के आयुक्त रहे मृत्युंजय कुमार को भी मुख्यमंत्री का सचिव बना कर लाया गया. योगी ने नोएडा अथॉरिटी के विवादास्पद चेयरमैन रमा रमण को भी हटा दिया और लखनऊ के मंडलायुक्त रहे विवादास्पद भुवनेश कुमार को मंडलायुक्त पद से हटा कर किनारे रख दिया. निवेश आयुक्त अमित मोहन प्रसाद को वर्तमान पद के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. नवनीत सहगल के साथ-साथ अनीता सिंह, दिंपल वर्मा, रमा रमण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विजय यादव को उनके पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में रखा गया है. संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. हरिओम और यूपीएसआईडीसी से अमित घोष को भी कोई तैनाती नहीं दी गई है. दिंपल वर्मा की जगह अनीता मेश्राम को बाल विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. अमित घोष की जगह रणवीर प्रसाद को यूपीएसआईडीसी की जिम्मेदारी दी गई है. आलोक सिन्हा को प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास का दायित्व मिला है.

करीब दो दर्जन वरिष्ठ नौकरशाहों के तबादले से प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला नहीं रुकने वाला है. नियुक्ति विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 200 आईएएस और आईपीएस अफसरों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें स्थानांतरित किया जाएगा या नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी. ईमानदार अफसरों को प्रमुख पदों और स्थानों पर तैनात किया जाएगा. ऐसे अफसरों की भी सूची बनी है, जो एक ही जगह कई-कई वर्षों से जमे हैं. स्थानांतरण की तैयारियों के बीच कई अफसरों के प्रशिक्षण पर भेजे जाने की भी तैयारी है. उसी हिसाब से जिला स्तर से लेकर ऊपर तक के तबादलों की रूपरेखा तैयार की जा रही है. उल्लेखनीय है कि आईएएस अफसरों को नौकरी के सात साल बाद ट्रेनिंग पर जाना जरूरी होता है. अफसरों को इस ट्रेनिंग के लिए तीन बार मौका दिया जाता है. इस बार प्रदेश के 47 अफसर इस ट्रेनिंग के लिए चुने गए गए हैं, जिनमें 31 अफसर विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) हैं. ट्रेनिंग पर भेजे जाने से पहले इन जिलों में जिलाधिकारी की नई तैनाती तय हो जानी चाहिए. विडंबना यह भी रही है कि मेधावी अफसरों की अच्छी तैनाती देने को लेकर पूर्व की सरकारों में कोई दिलचस्पी नहीं रही. यहां तक कि मेधावी अफसरों को उपेक्षित स्थानों पर ही तैनात किया जाता रहा. इस वजह से भी कई अफसर बाहर के डेपुटेशन पर चले गए. वर्ष 2000 बैच के ऑल इंडिया टॉपर सौरभ बाबू यूपी कैडर के अफसर हैं, लेकिन उन्हें छोटे जिलों में तैनाती दी जाती रही. लिहाजा वे बाहर चले गए. अभी वे मुम्बई में तैनात हैं. यूपी में कई और हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया, लेकिन उनकी तैनाती उपेक्षित जगहों में की जाती रही और रैंक में काफी नीचे स्थान पर रहने वाले अफसरों को अच्छी जगहों पर तैनाती मिलती रही. ■

इन नौकरशाहों का सीएम की तरह रहा है रुतबा

मुलायम, मायावती और अखिलेश के कार्यकाल में कई अफसरों का रुतबा मुख्यमंत्री से कम नहीं रहा है. मुलायम के मुख्यमंत्रित्व काल में अनीता सिंह का बोलबाला रहा, तो मायावती के कार्यकाल में राय सिंह और शशांक शेखर सिंह का. अखिलेश के जमाने में पहले अनीता सिंह की खूब चली बाद में अखिलेश ने नवनीत सहगल और पंधारी यादव जैसे अधिकारियों का सिक्का चलवाया. मायावती के जमाने में तो पहले राय सिंह और बाद में शशांक शेखर सिंह को 'सुपर सीएम' तक कहा जाता था. मुलायम और मायावती के पूर्ववर्ती शासनकाल में पीएल पुनिया की भी तूती बोलती रही है. इन अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि ये नौकरशाह कम मुख्यमंत्री के 'लायजनर' अधिक रहे. मुख्यमंत्रियों के लिए 'धन-अर्जन' में भी ये माहिर रहे हैं. लेकिन अखिलेश के कार्यकाल में यादव सिंह जैसे इंजीनियर-नौकरशाह ने अन्य अफसरों के होश उड़ा दिए. उसके धन-सामर्थ्य के आगे अखिलेश सरकार चक्करघिन्नी बनी नाचती रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं. मायावती के कार्यकाल में ताज कॉरीडोर घोटाले के जनक पीएल पुनिया थे, लेकिन बाद में ऐसा पलटे कि कॉरीडोर में केवल मायावती ही फंसी रह गईं. ताज कॉरीडोर प्रकरण में पीएल पुनिया के कारण ही मायावती सीबीआई की गुत्थियों में उलझीं, लेकिन पुनिया बड़ी सफाई से बाहर निकल आए. अखिलेश सरकार में गैर आईएएस अफसर यादव सिंह की तूती तो बोलती रही, लेकिन मायावती के शासनकाल में शशांक शेखर सिंह जैसे गैर आईएएस अफसर ने जैसा रुतबा दिखाया, वैसा न कभी पहले हुआ और न अब होगा. एक सामान्य पाइलट होते हुए भी शशांक शेखर सिंह ने खुद को न केवल आईएएस के रूप में नोटिफाई कराया, बल्कि प्रदेश का कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन बैठा. शशांक का सत्ता गलियारे में ऐसा जलवा था कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से लेकर मंत्री तक शशांक की चाटुकारिता में लगे दिखते थे. नवनीत सहगल आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वे भी मुख्यमंत्री पटाने के फन में माहिर माने जाते हैं. पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में नवनीत सहगल यूपी के नगर विकास मंत्री लालजी टंडन के खास थे. केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय स्टील मंत्री डॉ. अखिलेश दास के खास हो गए. फिर मायावती मुख्यमंत्री बनीं, तो उनके खास हो गए और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो सहगल उनके भी खास हो गए. सहगल योगी आदित्यनाथ के भी खास बनने के जतन में लगे थे, लेकिन योगी सजग थे, इसलिए सहगल दरकिनार हो गए. ■

अवनीश अवस्थी

रमारमण

नवनीत सहगल

feedback@chauthiduniya.com

लंदन में हिंदी का परचम

अनंत विजय

पिछले दिनों लंदन में हिंदी के लिए काम करने वाली संस्था वातायन ने हिंदी के तीन लेखकों और हिंदी के ही एक प्रकाशक को सम्मानित किया. अंतरराष्ट्रीय वातायन शिखर सम्मान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को दिया गया, अंतरराष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान उत्तर प्रदेश के कवि, शायर, गायक हरिओम को दिया गया और अंतरराष्ट्रीय वातायन संस्कृति सम्मान कवयित्री और मुंबई में साहित्य, कला और संस्कृति को गांव से जोड़ने वाली संस्कृतिकर्मी स्मिता पारिख को दिया गया. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वातायन प्रकाशन सम्मान वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी को प्रदान किया गया. लंदन में आयोजित एक भव्य समारोह में जब इन रचनाकारों को सम्मानित किया जा रहा था, तब वहां रहने वाले तमाम साहित्य प्रेमियों की मौजूदगी हिंदी साहित्य को आश्वस्त कर रही थी. लंदन में भारत के उच्चायुक्त ने इन सबको सम्मानित किया. पुरस्कार देने वाली संस्था की कर्ताधर्ता दिव्या माथुर और पद्मेश गुप्ता ने इसको हिंदी से जोड़कर आगे बढ़ाने की बातें की. पुरस्कार से नवाजे गए इन शख्सियतों को ब्रिटेन के चार शहरों में हिन्दुस्तानियों से संवाद का भी मौका मिला, कवि गोष्ठी और बातचीत के माध्यम से. हिंदी के लोगों को सम्मानित करने से ज्यादा बड़ा काम वातायन ने यह किया है कि उसने हिंदी के लेखकों और प्रकाशकों का संपर्क वृहत्तर पाठक वर्ग से करवाया. इसके अलावा एक अच्छी बात यह रही कि इस दौरे में हरिओम ने अपनी गायकी से श्रोताओं का दिल जीत लिया. वहीं स्मिता पारिख ने अपनी चर्चित और लोकप्रिय कविताएं सुनाकर श्रोताओं के सामने कई तरह के सवाल उछाले. ब्रिटेन के साथ इस तरह से अगर साहित्यक साझेदारी बनती या बढ़ती है, तो यह हिंदी साहित्य के लिए अपने दायरे को विस्तार देने जैसा होगा.

ब्रिटेन के चार शहरों में हुई इन गोष्ठियों के खत्म होने के बाद एक प्रश्न अब सबके मन में उठ रहा है कि क्या इस पुरस्कार की निरंतरता बनी रहेगी. आयोजक दिव्या माथुर और पद्मेश गुप्ता के सामने यह बड़ी चुनौती है. कई सालों तक कथाकार तेजेन्द्र शर्मा ने भी हिंदी के लेखकों को पुरस्कार दिया, पहले भारत में फिर कई बार लंदन बुलाकर रचनाकारों को सम्मानित किया गया. पिछले कई सालों से यह पुरस्कार बंद है. दो-तीन साल पहले कथा से अलग विधा के रचनाकार को सम्मानित किया गया. हिंदी में अपनी पहचान बना चुके इस पुरस्कार का बंद होना या स्थगित होना अपनी भाषा हिंदी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस पुरस्कार के माध्यम से हिंदी के रचनाकारों को लंदन में मंच मिलता था. हिंदी के बारे में देश के बाहर बात होती थी और भाषा के विस्तार की जमीन भी तैयार होती थी. विदेश में रह रहे लेखकों को अपनी माटी, अपने वतन के लेखकों से मिलने का अवसर मिलता था. लेकिन जब कोई भी पुरस्कार व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने लगे, तो उसका ज्यादा दूर तक चल पाना मुमकिन हो नहीं पाता है. वातायन ने जब इस साल का पुरस्कार दिया है, तो इसमें गद्य के लिए कोई पुरस्कार नहीं है. एक कविता और एक संस्कृति के लिए है, बाकी दो में से एक प्रकाशक और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा है. संभव है कि आयोजकों ने कुछ ऐसा नियम बनाया हो, जिसमें हर वर्ष अलग-अलग विधा के लेखकों को बुलाने की योजना हो, लेकिन अगर ऐसा ही नियम है, तो उसे अभी हिंदी जगत के सामने आना शेष है. विदेशों में हिंदी पर बात होती रहती है, लेकिन उसमें ज्यादातर बुजुर्ग लेखकों को बुलाया जाता है. लेकिन हाल के दिनों में विदेशों में नए लेखकों को मौका मिलने लगा है. अपेक्षाकृत नए लेखकों को विदेश में जाकर अपनी बात साझा करने से, अपनी रचना प्रक्रिया पर बात करने से, अपनी रचनाओं के साझा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है.

ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर अन्य तमाम तरह की चीजों के लिए जब बाजार खुले, तो 1994 में भारत की सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड चुना गया था. उसके छह साल बाद भारत से ही लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड चुनी गईं थीं. यह सब बाजार तय कर रहा था. नेशनल अवॉर्ड में बारह साल बाद हिंदी की किताब और ऑक्सफोर्ड में हिंदी के प्रकाशक को सम्मानित किए जाने की घटना को जोड़कर देखते हैं, तो यह बाजार में हिंदी की धमक के तौर पर नजर आती है. कुछ लोगों को ये दलील या ये आकलन दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन बाजार के अपने कायदे कानून होते हैं, जिसको समझने की जरूरत होती है.

पिछले दो तीन सालों में हिंदी में काम भी अच्छा हुआ है और उत्साह का माहौल भी बना है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी. पूरी दुनिया को अब हिंदी का बड़ा बाजार नजर आ रहा है, लिहाजा हिंदी में निवेश की संभावनाएं भी तलाशे जा रहे हैं. पिछले दिनों वाणी प्रकाशन के निदेशक अरुण माहेश्वरी को लंदन के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज ने बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड से नवाजा. ऐसा पहली बार हुआ कि किसी हिंदी के प्रकाशक को ऑक्सफोर्ड में सम्मानित किया गया हो. इस मौके पर ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर स्टीव ब्रिस्टो ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और भारतीय भाषाएं इस विविधता को प्रतिबंधित करती हैं. उन्होंने कहा कि उनके लिए यह गौरव का विषय है कि भारतीय भाषाओं में प्रमुख भाषा हिंदी के श्रेष्ठ प्रकाशक को ऑक्सफोर्ड सम्मानित कर रहा है. प्रोफेसर स्टीव ब्रिस्टो ने भारत में भाषा के बड़े बाजार को भी रेखांकित किया और कहा कि भारत भाषायी रूप से सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का सोपान है. यह हिंदी के लिए भी गौरव की बात है कि इस भाषा के प्रकाशक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है. पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत के भाषाई बाजार पर लगी है और उनको लगता है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से इस बाजार पर पकड़ बनाई जा सकती है. आपको याद होगा कि जब 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, तब भारत में पूरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संभावनाएं नजर आने लगी थीं. ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर अन्य तमाम तरह की चीजों के लिए जब बाजार खुले, तो 1994 में भारत की सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड चुना गया था. उसके छह साल बाद भारत से ही लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड चुनी गईं थीं. यह सब बाजार तय कर रहा था. नेशनल अवॉर्ड में बारह साल बाद हिंदी की किताब और ऑक्सफोर्ड में हिंदी के प्रकाशक को सम्मानित किए जाने की घटना को जोड़कर देखते हैं, तो यह बाजार में हिंदी की धमक के तौर पर नजर आती है. कुछ लोगों को ये दलील या ये आकलन दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन बाजार के अपने कायदे कानून होते हैं, जिसको समझने की जरूरत होती है. बाजार उस पर ही अपना दांव लगाता है, जिसमें उसको संभावना नजर आती है और इस वक्त हिंदी से ज्यादा संभावना किसी और दूसरी भाषा में पूरी दुनिया में नहीं है. यह बाजार का ही दबाव है कि ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस भी अब हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करने लगा है. जरूरत इस बात की है कि हिंदी बाजार का इस्तेमाल अपने हक में करे. ■

anant.ibn@gmail.com

कुटकी

परिचय

आयुर्वेदीय प्राचीन संहिताओं जैसे चरक-संहिता के लेखनीय, भेदनीय तथा स्तन्यशोधन महाकषाय में इसका वर्णन प्राप्त होता है. इसके अतिरिक्त सुश्रुत-संहिता में अनेक रोगों की चिकित्सा में कुटकी का प्रयोग किया गया है. यह अत्यंत कड़वी होती है, इसलिए इसे कटुम्भरा कहा जाता है. अत्यन्त प्राचीन काल से औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है. यह पौधा हिमालय में जम्मू-कश्मीर से सिक्किम तक 2700-4500 मी की ऊंचाई पर प्राप्त होता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **कण्ठ रोग-** कुटकी चूर्ण का क्वाथ बनाकर 10-15 मिली क्वाथ में गोमूत्र अर्क मिलाकर पीने से कण्ठ रोगों में लाभ होता है.
- **मुख रोग-** कुटकी क्वाथ का गरारा करने से मुख की कटुता तथा मुखपाक का शमन होता है.
- कुटकी आदि औषधियों से निर्मित क्वाथ का 10-15 मिली मात्रा में सेवन करने से रात्रिजागरण जन्य विकार, तृष्णा, मुख-शोष, दाह, कास तथा श्वास का शमन होता है.
- **हृदय रोग-** मुलेठी और कुटकी से निर्मित 2 ग्राम कल्क को मिश्री युक्त जल में घोलकर पीने से पित्तज हृदय रोग में लाभ होता है.
- **अम्लपित्त-** 2 ग्राम कुटकी चूर्ण में 2 ग्राम शर्करा तथा मधु मिलाकर चाटने से अम्लपित्त में लाभ होता है.
- **उदरशूल-** 1-2 ग्राम कुटकी चूर्ण में 500 मिग्रा काली मिरच का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से उदरशूल का शमन होता है.
- 3-5 ग्राम कुटकी मूल चूर्ण को समभाग मधु के साथ प्रतिदिन, दिन में तीन बार सेवन करने से यकृत-विकारों में लाभ होता है.
- 2-4 ग्राम कुटकी चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खिलाने से

यकृत तथा प्लीहा रोगों का शमन होता है.
- 2 ग्राम कुटकी चूर्ण में शक्कर मिलाकर गुनगुने जल के साथ खाने से पीलिया में लाभ होता है.

त्वचा रोग

- **कुष्ठ-** समभाग प्रियंगु, निर्गुण्डी बीज, कुटज बीज, अतिविषा, खस, लाल चंदन तथा कुटकी को पीसकर, इससे निर्मित लेप को पित्तज-कुष्ठजन्य पर लगाने से लाभ होता है.

सर्वशरीर रोग

- **ज्वर-** मिट्टी के नवीन पात्र में कुटकी का क्वाथ बनाकर, छानकर, 20 मिली क्वाथ में 10-12 ग्राम घी मिलाकर पीने से ज्वर तथा दाह का शमन होता है.
- इंद्रयव, नागरमोथा तथा कुटकी का शीत कषाय बनाकर मधु मिलाकर पीने से पित्तज्वर में लाभ होता है.
- 10-20 मिली कुटकी क्वाथ का सेवन करने से ज्वर में लाभ होता है.
- 1-2 ग्राम कुटकी चूर्ण में समभाग नीम छाल मिलाकर क्वाथ बनाकर पिलाने से ज्वर तथा अत्यधिक प्यास का शमन होता है.
- समभाग कुटकी, द्राक्षा, मुलेठी तथा नीम से निर्मित 10-20 मिली शीतल क्वाथ या हिम का सेवन करने से अथवा 2-3 ग्राम कुटकी चूर्ण में दोगुना मिलाकर नियमित सेवन करने से पित्तज्वर तथा कफपित्तज-ज्वर में लाभ होता है.
- कुटकी, खस, धनिया, पर्पट तथा नागरमोथा से निर्मित क्वाथ का सेवन करने से ज्वर का शमन होता है.

विष चिकित्सा

- **सर्पविष-** हरीतकी, आंवला, बहेड़ा, अतिविषा, कृठ, निर्गुण्डी बीज, तगर और कुटकी को समान मात्रा में लेकर चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करने से सर्पदंशजन्य-विषाक्त प्रभावों में लाभ होता है.

प्रयोज्यांग : *शुष्क प्रकन्द.*
मात्रा : *चूर्ण 0.5-1 ग्राम, 3-6 ग्राम या चिकित्सक के परामर्शानुसार.*
विषाक्तता : *यह त्वक् स्फोट उत्पन्न करता है. इसमें उपस्थित कुकुरबिटेसिन अतिसार, उदरगतवायु-विकार एवं शीतज्वर उत्पन्न कर सकते हैं.*

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

गुरू-निर्देशों का पालन

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

बाबा द्वारा दिखाए गए पथ के गहन विश्लेषण से कुछ स्पष्ट संकेतों का ज्ञान होता है, जो कि मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए बहुत आवश्यक है. शिरडी में बाबा के रहने के समय विभिन्न धर्मों एवं पंथों को मानने वाले बाबा से मिलने आते थे और वहां बाबा का लोगों से विचारों का आदान-प्रदान हुआ करता था. उस सम्पर्क के दौरान बाबा ने बार-बार कुछ भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक क्रियाएं एवं नियम बताए तथा भक्तों को उनका पालन करने के लिए कहा. इस सन्दर्भ में यद्यपि अधिकांश भक्तों की तात्कालिक या रोजमर्रा की सांसारिक समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार विशेष निर्देश भी दिए थे, फिर भी नैतिक जीवन एवं आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए आवश्यक उनके आदेश एवं निर्देश अधिक गहन एवं दीर्घकालिक हैं. बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात् जिन भक्तों ने अपने शेष जीवन में बाबा द्वारा बतलाए गए आदेशों एवं निर्देशो का पालन किया, उनको जीवन में बहुत लाभ हुआ. लेकिन बाबा द्वारा देह छोड़ने के बाद जिन भक्तों ने उनके आदेशों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया, वे भटक गए और आध्यात्मिक रूप से अधिक विकसित नहीं हो पाए. बाबा के कुछ श्रेष्ठ भक्तों की जीवनियों को पढ़ने से निस्संदिग्ध रूप से यही निष्कर्ष निकलता है.

'श्री साईं सच्चरित्र' के अंतर्गत शिरडी में वास्तविक जीवन में घटने वाले किस्सों का वर्णन एवं उनकी व्याख्याओं का विवरण मिलता है. उनके माध्यम से जीवन को सुख-शान्ति एवं सन्तोष देने वाले और चेतना को विकसित करने वाले बाबा द्वारा बताए गए आवश्यकीय मानदण्डों का गहन एंव व्यापक वर्णन किया गया है. बाबा पर लिखी गई अधिकांश पुस्तकों में भी इन्हीं आदेशों एवं उपदेशों को विभिन्न शैलियों में दर्शाया गया है. 'श्री साईं सच्चरित्र' तथा अन्य प्रकाशित पुस्तकों में बाबा के जीवन के ये उदाहरण और निर्देश एवं उपदेश व्यवस्थित रूप से वर्णित हैं. ये आवश्यकीय निर्देश किसी भी उत्कृष्ट भक्त के नैतिक आचरण और आध्यात्मिक प्रगति को दिशा देने में श्रेष्ठ और सटीक मार्ग हैं. इसी कारण मैं बाबा के भक्तों और अन्य सभी मार्गों एवं धर्मों के अनुयायियों को सदैव विशेष रूप से 'श्री साईं सच्चरित्र' और उससे सम्बन्धित अन्य साईं-साहित्य पढ़ने के लिए कहता हूं. किसी भक्त को जब भी किसी बात के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका उत्तर पाने के लिए 'श्री साईं सच्चरित्र' में निरूपित समान घटनाओं और परिस्थितियों के सन्दर्भ में दी गई जानकारी को अपनी स्थिति से मिलाकर देखना चाहिए. हर भक्त को सदैव यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह जब भी कोई काम कर रहा हो, तो 'श्री साईं सच्चरित्र' में वर्णित बाबा के निर्देशों एवं आदेशों के कितना पास या दूर है? उसके लिए यह भी देखना जरूरी है कि वह इन निर्देशों का मूल्यांकन कर उन्हें अपने नैतिक जीवन का आधार बनाने में कहां तक सफल हुआ है?

बाबा ने इन श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन-सिद्धान्तों के विषय में अत्यन्त सरल रूप से बताया है. साथ ही अपने क्रिया-कलापों द्वारा उन्हें दर्शाया भी है, जो कि स्वयं में उदाहरण हैं. उदाहरण के तौर पर 'श्री साईं सच्चरित्र' में वर्णित उस प्रसंग को लीजिए जहां कि किसी ने बाबा से किसी अन्य की निन्दा की थी. तब बाबा ने उससे कहा था कि सूअर को चाहे कितना ही अच्छा भोजन क्यों न दिया जाय, वह सदैव मैला ही खाएगा. इस वाक्य का अर्थ इतना सरल एवं स्वतः स्पष्ट है कि इसे किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है. एक अन्य घटना पर विचार करें, जिसमें बाबा ने राधाकृष्णा आई के घर पर चढ़ने एवं उतरने में सीढ़ी द्वारा सहायता पहुंचाने वाले को दो रुपए दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि दूसरे द्वारा किए गए श्रम का उदारतापूर्वक भुगतान अवश्य करना चाहिए. बाबा द्वारा विभिन्न समय पर दिए निर्देशों का निष्कर्ष 'श्री भगवत् गीता' में दिए गए उपदेशों का व्यावहारिक रूप दर्शाता है. अर्थात् उनसे यह पता चलता है कि जीवन में इन निर्देशों का व्यावहारिक रूप से पालन कैसे किया जा सकता है.

ज्यादातर भक्तों के साथ समस्या यह है कि वे 'श्री साईं सच्चरित्र' पढ़ते समय अलौकिक घटनाओं से अधिक आकर्षित होते हैं, जबकि वे व्यावहारिक जीवन में नैतिकता लाने वाले बाबा के इन निर्देशों, आदेशों या उपदेशों को गम्भीरता से समझने का प्रयास नहीं करते. यही नहीं बल्कि साथ ही वे सांसारिक कर्मों अथवा दुष्कर्मों को करते समय बाबा द्वारा उस सन्दर्भ में दिए गए निर्देशों को भूल जाते हैं और इस नासमझी के कारण वे विभिन्न समस्याओं के विषय में लगभग उन्हीं प्रश्नों को दोहराते रहते हैं.

बाबा चाहते थे कि उनके भक्त इन निर्देशों को मात्र पढ़ें ही नहीं बल्कि अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उनका पालन भी करें. जहां तक हम बाबा के निर्देशों को समझ पाए हैं. मूल बात यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इस दिशा में प्रयास करते हुए कितनी बार असफल हुआ है. बल्कि प्रश्न यह है कि कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करते समय क्या वह बाबा की इन बातों को याद रखता है? क्या वह इनका पालन करने के विषय में दृढ़-संकल्प है? हर भक्त को चाहिए कि वह स्वयं से यह प्रश्न करे और खुद ही उसका उत्तर ढूंढ़े. 'श्री साईं सच्चरित्र' इस दिशा में केवल पथ-प्रदर्शन कर सकता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं. क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

जंतर-मंतर: जहां से लोक पहुंचाता है तंत्र तक फ़रियाद

इंसाफ़ मिले न मिले आवाज़ उठाना ज़रूरी है

जंतर-मंतर की सूर्य घड़ी सटीक समय बताए न बताए, यहां बैठे लोगों को देखकर देश की हालत और व्यवस्था की दिशा का सही-सही अनुमान लगाया जा सकता है. हमारे देश में सरकार और व्यवस्था दबे-कुचले और पीड़ितों की नहीं आंदोलनकारियों की सुनती है और जंतर-मंतर वो जगह है, जो आम जनता को आंदोलनकारी की पहचान देता है, ताकि सरकार उनकी बात सुन सके. सियासत और व्यवस्था में कई बदलावों का साक्षी रहे जंतर-मंतर को कभी संसद के कान के नीचे की जगह के रूप में जाना जाता था, जहां से चिल्लाने पर संसद तक आवाज पहुंचती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं लगता. पिछले 12 मार्च से तमिलनाडु के किसान यहां से आवाज लगाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा. सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे दर्जन भर से ज्यादा व्यक्ति और संगठन हैं, जो कई सालों से यहां आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं... चौथी दुनिया संवाददाता निरंजन मिश्रा की रिपोर्ट...

नरमुंडों के साथ अब भी डटे हैं तमिलनाडु के किसान

कर्ज के बोझ और अन्न के अभाव में आत्महत्या करने को मजबूर हुए अपने लोगों के नरमुंडों के साथ तमिलनाडु के किसान पिछले 12 मार्च से जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं. जंतर-मंतर से जब इनकी आवाज नहीं सुनी गई, तब ये इस उम्मीद में पीएमओ के सामने नंगे हो गए कि शर्म के कारण शायद सरकार इनकी बात सुन ले. लेकिन तब भी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई. इनका कहना है कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं कर देती. ■

अब भी जारी है पूर्व सैनिकों का आंदोलन

ओआरओपी को लेकर जून 2015 से जंतर-मंतर पर शुरू हुआ पूर्व सैनिकों का आंदोलन अब भी जारी है. स्वेच्छा से रिटायरमेंट समेत कई मुद्दों पर अभी भी इनका सरकार के साथ गतिरोध बरकरार है. इनका कहना है कि सितंबर 2015 में सरकार ने जिस ओआरओपी को मंजूरी दी, उसमें हमारी सभी मांगे नहीं मानी गईं. सरकार ने उस समय हमारी एक ही मांग मानी और छह मांगे नकार दी थी. हम यहां तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक सरकार हमारी पूरी मांगें नहीं मान लेती. ■

5 सालों से जंतर-मंतर पर डटे हैं भगाना पीड़ित

भगाना के पीड़ितों का आंदोलन उन आंदोलनों में से एक है, जो कभी हरियाणा से लेकर दिल्ली तक में चर्चित रहा था. हिसार लघु सचिवालय से शुरू हुआ आंदोलन पिछले 21 मई 2012 से लगातार जंतर-मंतर पर जारी है. जिन 137 परिवारों को दबंगों के कारण अपना गांव और अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, उन लोगों ने आंदोलन को जारी रखने के लिए खुद में ही कई टीमें बनाकर उन्हें पालीबद्ध कर दिया है. आंदोलन के खर्च का वहन भी ये सब लोग मिलकर करते हैं. वर्तमान में आंदोलन पर बैठे सतीश काजला का कहना है कि आजादी के इतने सालों बाद भी अपने समाज में हम सम्मानजनक जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि हमें इज्जत के साथ अपने गांव, अपने घर में रहने का इंसाफ नहीं मिल जाता. सतीश कहते हैं कि चाहे वो हरियाणा की हुडडा सरकार हो या खट्टर सरकार, केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी सरकार, किसी ने भी हमें इंसाफ नहीं दिया. ■

आरोप उसी पर जिससे इंसाफ की आस है

ये मामला है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार के आरोप का. ये लोग 10 अगस्त 2015 से दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठे हुए हैं. पौने दो साल के आंदोलन में ये इतने टूट चुके हैं कि अब इंसाफ की आस भी छोड़ने लगे हैं. जंतर-मंतर के इनके आंदोलन स्थल पर जब हम पहुंचे, तो वहां केवल होर्डिंग और खाली जगह दिखी. फोन पर हुई बातचीत में आंदोलन से जुड़े नरेश खुर्राना ने बताया कि हम पिछले पौन दो साल से सीएम खट्टर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. हम मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर गए थे, जब वहां की पुलिस रात के नौ बजे महिलाओं और बच्चियों को जबर्दस्ती उठाकर ले गई. पीटते-पीटते उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया था. नरेश ने कहा कि हम अपने पैसों और खर्चों से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं. घर से खाने पीने का सामान और खर्च के पैसे लाकर हम जंतर-मंतर पर आंदोलन करते हैं. हम इसी आस में आंदोलन कर रहे हैं कि भारत का संविधान सबके लिए एक कानून की बात करता है, जुर्म चाहे आम आदमी ने किया हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने. ■

गाय को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए आंदोलन

वर्तमान सरकार में जो विषय सबसे चर्चित रहे उनमें से एक है, गौ हत्या पर प्रतिबंध और गौ सुरक्षा. इसी विषय को लेकर जंतर-मंतर पर पिछले साल 30 जनवरी से एक आंदोलन जारी है. इस आंदोलन से जुड़े सतीश नारायण बताते हैं कि कृषि आधारित भारत में गौवंश की सुरक्षा और देशहित इसका सदुपयोग बहुत जरूरी है. गाय को हम भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बना सकते हैं. हमारी मांग है कि सरकार गाय और बैलों की हत्या और इनके मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाए. आंदोलन के खर्च और आंदोलनकारियों के रहने-खाने की व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाने पर सतीश नारायण का कहना था कि यहां स्थाई तौर पर हम दो लोग रहते हैं, एक मैं और एक अन्ना यादव. रहने-सोने के लिए रामलीला मैदान की हनुमान वाटिका में हमें एक कमरा मिला है. कई बार वहीं पर भोजन भी मिल जाता है, नहीं तो यहां बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के लंगर में हम भोजन कर लेते हैं. ■

राष्ट्रवादी सरकार से कश्मीर में राष्ट्रवाद की मांग

ने शनल पैंथर्स पार्टी द्वारा 11 सितंबर 2015 से जंतर-मंतर पर जारी ये आंदोलन कश्मीर में धारा 370 में संशोधन की मांग को लेकर है. इसके बारे में बताते हुए, नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रवक्ता अलमदार अब्बास ने कहा, हमारी मांग है कि धारा 370 में संशोधन किया जाय. आंदोलन के खर्च और जंतर-मंतर पर रहने वालों के खाने-पीने की व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर अलमदार अब्बास का कहना था कि नूं तो खर्च की व्यवस्था हमारी पार्टी की तरफ से होती है, लेकिन कई बार हम खुद से या किसी अन्य व्यक्ति-संगठन के सहयोग से भी अपना काम चला लेते हैं. अलमदार अब्बास ने हालांकि ऐसे संगठनों का नाम बताने से इंकार कर दिया. ■

आंदोलनकारियों की आवाज बनने वालों का आंदोलन

जंतर-मंतर पर आंदोलन करने वाले लोगों की पहली आशा-आकांक्षा पत्रकारों से होती है कि वे उनकी बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे. लेकिन पत्रकार बिरादरी के कुछ लोग भी अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए जंतर-मंतर पर पिछले

पांच महीने से आंदोलनरत हैं. ये आंदोलन प्रेस रिपोर्टर्स यूनियन के बैनर तले चल रहा है. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अजीत कुमार ने बताया कि हम पत्रकार आम लोगों की बात सरकारों तक पहुंचाते हैं, उनके समाधान का जरिया बनते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा और सम्मान को लेकर कोई कानून नहीं है. हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा गारंटी बिल संसद में पेश करे. ■

संत रामपाल मामले में सीबीआई जांच के लिए आंदोलन

हिसार के बरवाला आश्रम से नवंबर 2014 में गिरफ्तार हुए संत रामपाल को निर्दोष साबित कराने के लिए उनके अनुयायी भारी संख्या में जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं. 16 सितंबर 2015 से आंदोलन कर रहे इन लोगों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो. धरने पर बैठे सुरेश दास ने बताया कि हमारे गुरुजी पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा दायर किया गया है, इसलिए हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. आंदोलन के खर्च के बारे में उन्होंने बताया कि यहां आंदोलन कर रहे लोगों के खाने-पीने और खर्च की व्यवस्था मुंडका में स्थित हमारे आश्रम के जरिए की जाती है. ■

भूखमरी के शिकार अफ़्रीकी बच्चों की भी चिंता

जंतर-मंतर पर एक तरफ जहां लोग देश की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं यहां विदेशों में बच्चों की खराब हालत के लिए काम करने की ललक भी दिखी. दिल्ली के सरिता विहार की मेहरुनिसा इस मांग के साथ धरने पर बैठी हैं कि उन्हें सरकार से अनुमति और सहायता मिले कि वे नाइजिरिया और वर्मा जैसे देशों में जाकर वहां के बच्चों की खराब हालत के लिए काम कर सकें. मेहरुनिसा कहती हैं कि मैं एक सामान्य परिवार से हूं, अपने खर्च से यहां आंदोलन कर रही हूं. मैंने सरकार से मांग की है कि मुझे इसके लिए अनुमति दी जाय. मैं राजनाथ सिंह जी से भी मिली, लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं की. ■

पंजाब से पानी के लिए हरियाणा का आंदोलन

एसवाईएल नहर बीते कई सालों से पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का कारण रहा है. इससे जुड़ा आंदोलन 6 अप्रैल से जंतर-मंतर पर जारी है. इंडियन नैशनल लोक दल के नेतृत्व में इस आंदोलन के बारे में बताते हुए अरविंद भारद्वाज ने कहा कि पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी रोक रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय भी दे दिया, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि 15 मार्च को हमने यही जंतर-मंतर से ही सरकार को ज्ञापन सौंपा था, उस दिन हमपर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए. हम यहां से तभी जाएंगे, जब केंद्र सरकार हमें पानी दिलवा देगी. ■

जाट आंदोलनकारी भी हैं मैदान में

आरक्षण को लेकर अपने आंदोलन से पूरे देश में चर्चा का विषय बने जाटों का आंदोलन जंतर-मंतर पर भी जारी है. यहां धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि उन जाट युवाओं पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएं और उन्हें रिहा किया जाय, जिन्हें जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और नुकसान के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

5 अप्रैल से जारी इस आंदोलन के बारे में बताते हुए धर्मेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हमारा पूरा समुदाय इस मामले में एकसाथ है. हम सब अपनी तरफ से इसके लिए खर्च भी कर रहे हैं, अभी भले ही सरकार हमारी बात नहीं सुन रही हो, लेकिन गेहूं कटाई के बाद हम फिर बड़े स्तर पर यहां आंदोलन करेंगे. ■

सवर्ण आरक्षण के लिए आंदोलन

सवर्ण आरक्षण की मांग को लेकर ये 8 दिसंबर 2016 से जंतर-मंतर पर जारी इस आंदोलन के बारे में बताते हुए सतीश मुखिया ने कहा, हमारी मांग है कि सवर्णों को भी आरक्षण दिया जाय. आज आरक्षण के कारण ऐसे कई सवर्ण लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो नौकरी के काबिल हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ लेकर नाकाबिल लोग भी ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाते हैं. उन्होंने बताया, इस आंदोलन में हमें कई सवर्ण संगठनों का साथ मिल रहा है. सभी मिलकर इसके लिए खर्च की व्यवस्था करते हैं, ताकि आंदोलन जारी रहे. ■

दो बार जीत चुके हैं नेशनल अवॉर्ड

शानदार अदाकारी के लिए अजय देवगन को दो बार फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिल चुका है. उन्होंने पहला नेशनल अवॉर्ड 1998 में आई फिल्म *जख्म* और दूसरा 2002 में आई *द लीजेंड ऑफ भगत सिंह* के लिए मिला था. द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह का रोल करने के पहले अजय ने अपना वजन कम किया था और भगत सिंह के बारे में कई किताबें पढ़ी थी और इनका उन पर गहरा असर हुआ.

दो दशक से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं अजय देवगन

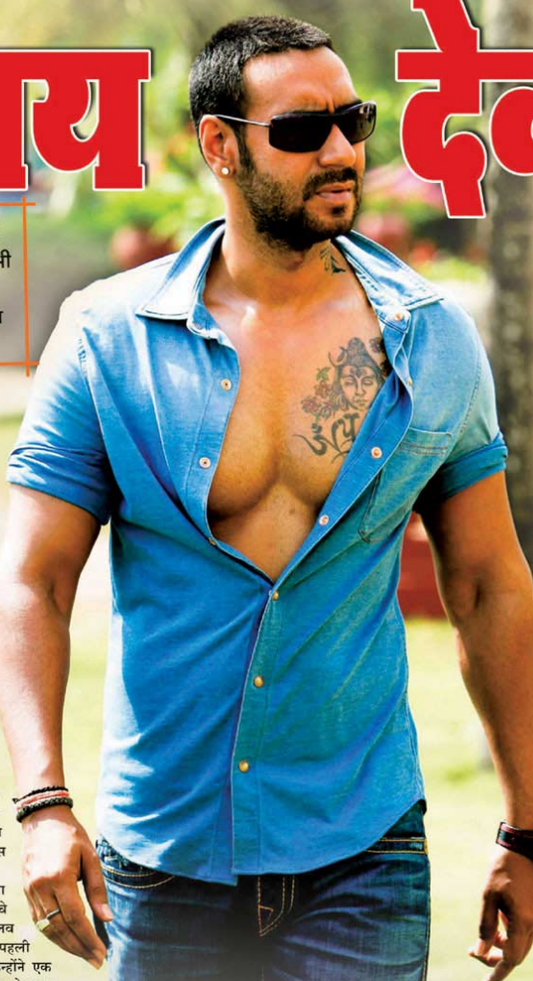

एक समय था जब इस सिंघम का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया जिसमें करिश्मा कपूर, रवीना टंडन आदि भी शामिल थी. लेकिन अजय को सच्चे प्यार के रूप में मिली काजोल. अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी फिल्म हलचल (1995) के सेट पर शुरू हुई थी.

प्रवीण कुमार

2 अप्रैल 1969 को नई दिल्ली में जन्में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने अपने 48 वर्ष पूरे किए. सभी को पता है कि अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है, जबकि प्यार से उन्हें राजू बुलाया जाता है. अजय को फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हुए 25 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका हैं. जहां एक तरह बॉलीवुड में एक से एक अभिनेता इंडस्ट्री में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर अजय टॉप-5 के अभिनेताओं में गिने जाते हैं. उनकी फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार रहती हैं. अजय उन अभिनेताओं में से एक है जो अपनी फिल्मों को खुद के दम पर हिट कराना जानते हैं. अजय बॉलीवुड में डार्क, एरोगेंट स्टंट और एक्शन हीरो की पहचान रखते हैं हालांकि वो रियल लाइफ में काफी सिंपल हैं.

बॉलीवुड में अजय ने लगभग अपने सभी किरदारों को परदे पर बखूबी निभाया और अपने अभिनय से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. बॉलीवुड में अजय देवगन के इस अहम योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनको 2016 में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया.

अजय का डेब्यू बेहद शानदार रहा. वर्ष 1991 में अजय ने अपना फिल्मी करियर फिल्म 'फूल और कांटे' से शुरू किया. फिल्म सुपरहिट रही और अजय का करियर चल पड़ा और आज तक वह बॉक्स ऑफिस पर राज़ कर रहे हैं. वैसे तो सभी का पता है कि अजय ने 'फूल और कांटे' से करियर की शुरूआत की लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 16 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्म में काम किया था. जी हां, जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म का नाम था 'प्यारी बहना'. 1985 में आई इस फिल्म में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के यंगर वर्जन को निभाया था.

एक समय था जब इस सिंघम का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया जिसमें करिश्मा कपूर, रवीना टंडन आदि भी शामिल थी. लेकिन अजय को सच्चे प्यार के रूप में मिली तो वह है काजोल. अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी फिल्म 'हलचल' (1995) के सेट पर शुरू हुई थी. बताया जाता है कि पहली मुलाकात के दौरान अजय देवगन को चुप-चुप देख काजोल हैरान थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे कैसे इस एक्टर के साथ काम करेगी. बाद में दोनों ने 'इश्क', 'प्यार तो होना ही था', 'दिल क्या करे', 'राजू चाचा' और 'यू मी और हम' जैसी कई फिल्में साथ की.

अजय का फिल्मी करियर आज ऐसे मुकाम पर है जो बेहद कम लोगों को ही नसीब होता है. एक समय ऐसा भी था जब अजय की लगातार फ्लॉप फिल्मों से उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था. लेकिन कुछ फिल्मों में उनकी गंभीर अदाकारी ने दर्शकों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी की उनकी पहचान एक्शन से हटकर गंभीर किरदारों के लिए भी उन्हें जाना जाने लगा. इसमें उनकी फिल्म 'जख्म', 'हम दिल दे चुके सनम', 'गंगाजल', 'अपहरण', 'राजनीति', 'सत्याग्रह', 'सिंघम', 'सिंघम रिटर्न' आदि फिल्में शामिल थी जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी मदद की.

अजय देवगन इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'बादशाहों' और 'गोलमाल-4' की शूटिंग कर रहे हैं. समय-समय पर अजय देवगन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस का अपनी अपकमिंग मूवी और उनसे जुड़ी जानकारियां अकसर देते रहते हैं. फिल्म 'बादशाहों' और 'गोलमाल-4' के बाद बॉलीवुड का यह सिंघम रोहित शेट्टी की ही फिल्म 'सिंघम-3' पर भी काम जल्द ही शुरू कर देंगे. इसके बाद अजय अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म 'ऑफ सरदार: द बैटल ऑफ सारागढ़ी' का निर्माण करेंगे. यानि अजय देवगन, अक्षय कुमार की तरह साल में 3-4 फिल्में बैक टू बैक करके बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने की फिराक में है. आईए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनकी जानकारी शायद कम ही लोगों को होगी.

ऐसे रहते हैं फिट

अजय बताते हैं, वर्कआउट करते वक्त मैं ट्रेडमिल पर 13-14 की स्पीड से 45 मिनट तक दौड़ता हूं. मैं बैंच प्रेस करता हूं. मैं एक बार में 500 पुश एप्स करता हूं. साथ ही मैं सूर्य नमस्कार भी करता हूं. हालांकि मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करता हूं बस रात के खाने पर थोड़ा ध्यान देता हूं. मुझे अच्छा खाना काफी पसंद है लेकिन जब वो मेरे सामने होता है तो मैं थोड़ा ही खा पाता हूं. एक फिटनेस हीरो के तौर पर अजय बताते हैं, मैं कभी सिक्स पैक बनाने के लिए वर्क नहीं करता हूं. मैं टोन्ड लुक पर ध्यान देता हूं. एक मजबूत बॉडी दिखनी चाहिए. मेरा वर्कआउट मेरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है. मेरा कोई स्टाइल नहीं है. मैं सब ऑन द स्पॉट करता हूं.

अजय की आने वाली फिल्में

1. बादशाहों -	अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलेना डी-सूजा, ईशा गुप्ता और विद्युत जामवाल
2. गोलमाल 4-	अजय देवगन, परिणीति चौपड़ा, तब्बू , अरशद वारसी, कुनाल खेमू, जॉनी लीवर
3. सन ऑफ सरदार 2 -	अजय देवगन
4. सतसंग-	प्रकाश झा
5. राजनीति 2-	प्रकाश झा

इन फिल्मों के अलावा अजय देवगन कई ऐसे दूसरे प्रोजक्ट में भी व्यस्त हैं जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा.

पिता हैं जाने-माने स्टंट कोरियोग्राफर

अजय देवगन के पिता वीरू देवगन जाने-माने स्टंट कोरियोग्राफर हैं और उनकी मां वीणा प्रोड्यूसर. अजय के एक भाई भी हैं, जिनका नाम अनिल देवगन है. वे राजू चाचा जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं. अजय की पहली फिल्म 'फूल और कांटे' में भी वीरू ही स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर थे. वीरू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी थे. उन्होंने साल 1999 में आई फिल्म 'हिंदुस्तान की कसम' को डायरेक्ट किया था.

2012 में दोहराया डेब्यू फिल्म का स्टंट

डेब्यू फिल्म 'फूल और कांटे' में अजय देवगन की एंट्री दो मोटरसाइकिलों पर एक स्टंट के साथ हुई थी. वह स्टंट काफी फेमस हुआ था. सालों बाद ऐसा ही स्टंट अजय ने 2012 में फिल्म 'सन ऑफ सरदार' में भी किया था. फर्क यह था कि इस बार वे मोटरसाइकिलों पर नहीं, बल्कि घोड़ों पर थे.

अजय को ऑफर हुई थी 'करन-अर्जुन'

1995 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करन-अर्जुन' में पहले करन का रोल अजय देवगन को ऑफर किया गया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इसे ठुकरा दिया. बाद में यह रोल सलमान खान को ऑफर किया गया और उन्होंने इसे तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया.

मसेराती क्वाट्रोपोर्टे कार खरीदने वाले पहले भारतीय अजय

बताया जाता है कि मसेराती क्वाट्रोपोर्टे कार खरीदने वाले अजय देगवन पहले भारतीय हैं. अजय ने जिस वक्त मसेराती क्वाट्रोपोर्टे ली थी, उस वक्त इसकी कीमत 4 करोड़ के आसपास थी.

एक्टर नहीं, निर्देशक बनना चाहते थे अजय देवगन

कम लोगों को ही पता होगा कि अजय देवगन एक्टर नहीं, बल्कि डायरेक्टर बनना चाहते थे. अजय ने मीठी बाई कॉलेज से ग्रैजुएशन किया. इसके बाद डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने लगे. इसी दौरान उनकी मुलाकात कुकू कोहली से हुई, जो उस वक्त 'फूल और कांटे' बना रहे थे. उन्होंने अजय को इस फिल्म में लीड रोल ऑफर किया. फिल्म सुपरहिट हुई और अजय देवगन की पहचान एक एक्शन हीरो के रूप में बन गई.

अजय ने आगे चलकर अपनी छवि को बदला और उन्होंने फिल्म 'यू मी और हम' और 'शिवाय' जैसी फिल्मों का निर्माण किया. अजय जल्द ही फिल्म 'सन ऑफ सरदार: द बैटल ऑफ सारागढ़ी' का निर्माण करेंगे.

काजोल और अजय की लव स्टोरी

अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी फिल्म 'हलचल'(1995) के सेट पर शुरू हुई थी. बताया जाता है कि पहली मुलाकात के दौरान अजय देवगन को चुप-चुप देख काजोल हैरान थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे कैसे इस एक्टर के साथ काम करेगी. बाद में दोनों ने 'इश्क', 'प्यार तो होना ही था', 'दिल क्या करे', 'राजू चाचा' और 'यू मी और हम' जैसी कई फिल्में साथ की.■

सौ करोड़ क्लब में अजय की 6 फिल्में

गोलमाल-3
110.75 करोड़

सिंघम
101 करोड़

बोल बच्चन
100.10 करोड़

सन ऑफ सरदार
102. 80 करोड़

सिंघम रिटर्न
139 करोड़

शिवाय
100.30 करोड़

feedback@chauthiduniya.com

अजय को इन फिल्मों के लिए मिला अवॉर्ड

1992 में फिल्म फूल और कांटे के लिए फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू

1999 में अजय को पहला नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फिल्म जख्म के लिए चुना गया

2003 में फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर

2003 में फिल्म दीवानगी के लिए फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट निगेटिव रोल

2003 में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और कंपनी के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर

2012 में अजय को सिनेमैटिक आइकॉन ऑफ द इयर मेल का अवार्ड दिया गया

2017 में फिल्म शिवाय को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का नेशनल अवार्ड दिया है.

2016 में अजय देवगन को पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया

अजय को कई ऐसे बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया है जिसके वह हकदार थे. इसके अलावा उनका नाम 'गंगाजल', 'सिंघम', 'वंस अपॉन ए टाईम इन मुंबई', 'ऑल द बेस्ट', 'सन ऑफ सरदार', 'सिंघम रिटर्न', 'दृश्यम' आदि फिल्मों के लिए अवार्ड शो में नॉमिनेट किया जा चुका हैं. हाल ही में अजय की फिल्म 'शिवाय' को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का नेशनल अवार्ड दिया गया है. इसका निर्देशन भी खुद अजय देवगन ने ही किया है.